BLM Academy

Affiliated to C.B.S.E. New Delhi, C.B.S.E. Affiliation No.: 3530343
ISO 9001:2015 (QMS) Certified School

"The Best Way To Predict Your Future Is To Create It With BLM Academy."

पोस्टल रजि.नं.यूए-नैनीताल-356-2021-2023

Admission Open
For The Academic Session 2026-27
(Classes Nursery to IX & XI)

LIMITED SEATS
APPLY NOW

Vision -
To prepare the children empowered with Indian ethical and spiritual values to face the global challenges.

Mission-
To produce enriched and enlightened human resource for the country.

Pillars -
SATYA, PURUSHARTH & PARAMARTH

Goal-
ब्रह्म तद् लक्ष्यम्

Streams: Science, Commerce & Humanities

Celebrate The Gift of Life

+91 7055515681
+91 7055515683
www.blmacademy.com

Padampur Devaliya, Gora Parao, Haldwani (Nainital), Uttarakhand

blma.principal@gmail.com

प्रणवो धनुः शरो हि आत्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते।
अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत् ।। (मुण्डक उपनिषद)

जुलाई 2026

उत्तरांचल दीप पत्रिका

यशस्वी पत्रकार वेदप्रकाश गुप्ता को समर्पित

₹:40

ई-मेल: uttranchaldeepatrika@gmail.com

Web: uttaranchaldeep.com

छल से पीएम बने थे नेहरू

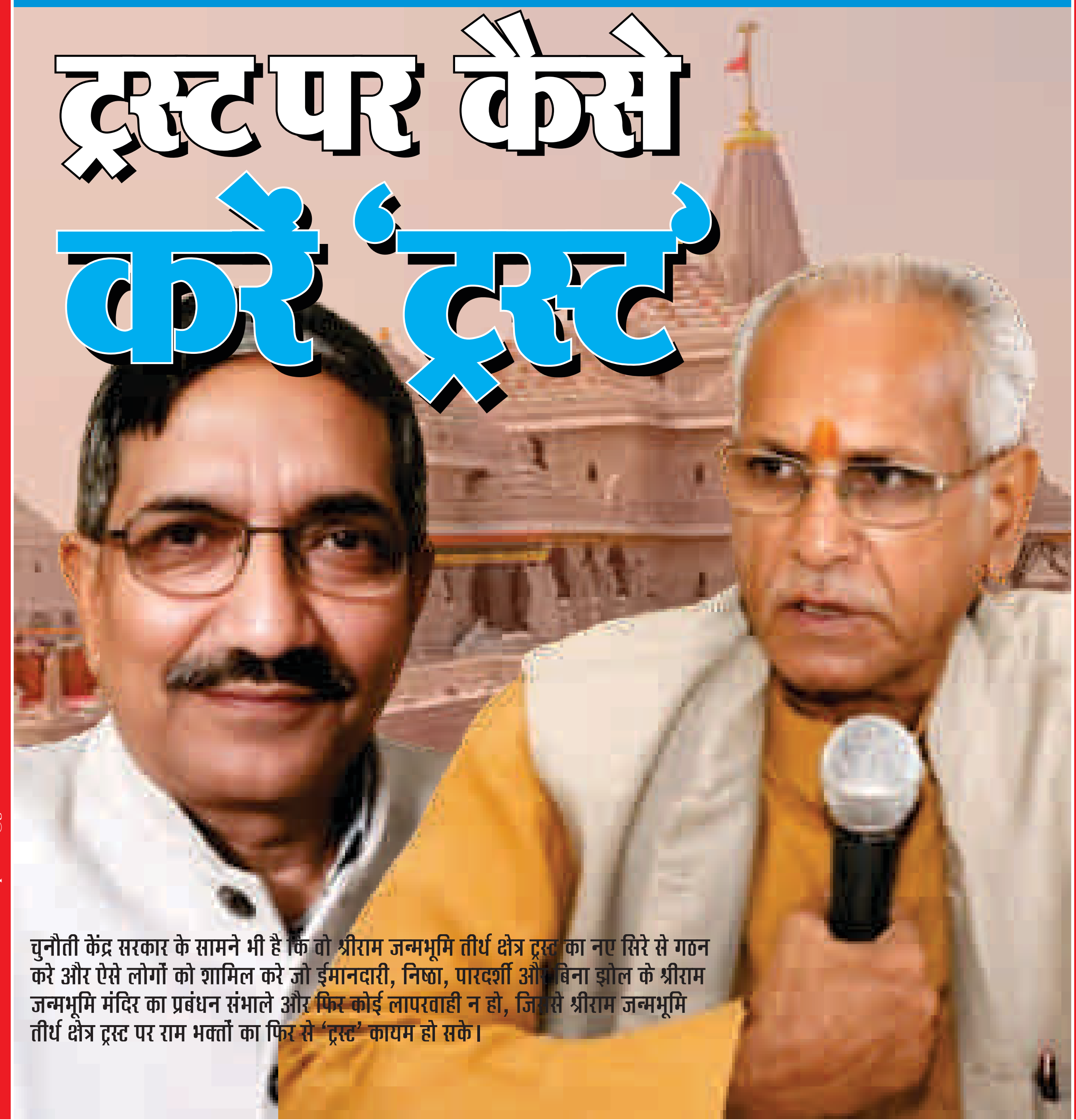

ट्रस्ट पर कैसे करें 'ट्रस्ट'

चुनौती केंद्र सरकार के सामने भी है कि वो श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का नए सिरे से गठन करे और ऐसे लोगों को शामिल करे जो ईमानदारी, निष्ठा, पारदर्शी और बिना झोल के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर का प्रबंधन संभाले और फिर कोई लापरवाही न हो, जिससे श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर राम भक्तों का फिर से 'ट्रस्ट' कायम हो सके।

Nupur Creations

Jute Hand Bags, Craft & Many More

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की **वोकल फॉर लोकल** नीति से प्रेरित उत्तराखंड के हस्तकला के क्षेत्र में उभरता नाम

नुपूर

उत्तराखंड की हस्तकला को राष्ट्रीय पहचान दिलाना हमारा लक्ष्य

उत्तराखंड की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना हमारा प्रयास

जूट से बने फेंसी आइटम, होम डेकोरेशन की फेंसी सामग्री, गिफ्ट आइटम की बड़ी रेंज ऑन लाइन उपलब्ध

SHAKTI PURAM GALI,
NAWABI ROAD, HALDWANI
(NAINITAL), Uttarakhand

CALL:
05946 220841, +91 9410334041
+91 9760590897

www.facebook.com/nupurnrityakalakendra
You Tube: Search: nupurnrityakalakendra
nupurnritya99@gmail.com
www.nupurcreations.co.in

Log in for purchase Items ONLINE:

मासिक **उत्तरांचल दीप** पत्रिका

वर्ष:9, अंक 3, जुलाई 2026

संस्थापक संपादक
स्व.वेदप्रकाश गुप्ता
प्रधान संपादक
साकेत अग्रवाल
संपादक
श्रीमती आदेश अग्रवाल
मुख्य कार्यकारी संपादक
केके चौहान
मुख्य उप संपादक
उदयभान सिंह
मार्केटिंग हेड
तारु तिवारी
प्रबंधक
दीपक तिवारी
वरिष्ठ संवाददाता
रवि दुर्गापाल

उत्तरांचल दीप ब्यूरो
दिल्ली : शालिनी चौहान
रुद्रप्रयाग : हिमांशु पुरोहित
नैनीताल : अफजल फौजी
अल्मोड़ा : कमल कपूर
पिथौरागढ़ : ललित जोशी
बागेश्वर : नरेंद्र बिष्ट
चंपावत : मनोज राय
बरेली : अनुज सक्सेना
मुरादाबाद : आर्शेंद्र कुमार अग्रवाल
डोईवाला : चंद्रमोहन कोठियाल
किच्छा : राजकुमार राज
रामनगर : एचसी भट्ट
थत्यूड़ : मुकेश रावत
रुद्रपुर : मुकेश गुप्ता
बाजपुर : इंद्रजीत सिंह
ग्राफिक्स डिजाइन: देवेंद्र सिंह बिष्ट
सभी पद अवैतनिक एवं परिवर्तनीय

मुख्यालय
हल्द्वानी: चंद्रकांता हाउस, जजी के सामने
नैनीताल रोड, हल्द्वानी (उत्तराखंड)

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक व संपादक श्रीमती आदेश अग्रवाल द्वारा उत्तरांचल दीप, चंद्रकांता हाउस, जजी के सामने नैनीताल रोड हल्द्वानी से मुद्रित व प्रकाशित।
आएनआई नंबर: UTTHIN/2018/77440
पोस्टल रजि.नं.यूए-नैनीतील-356-2021-2023

उत्तरांचल दीप पत्रिका में प्रकाशित लेख, पत्र व अन्य कालम में लेखकों के विचार होते हैं, उनसे संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है।
समस्त विवाद हल्द्वानी न्यायालय के अधीन होंगे।

www.uttaranchaldeep.com
uttranchaldeepatrika@gmail.com
+91 8881788066 @uttranchaldeep

अंदर

कांग्रेस सत्ता पाने के लिए बेचैन है, लेकिन उत्तराखंड में कांग्रेस का सीएम पद का चेहरा कौन होगा? क्या हरीश रावत कांग्रेस का चेहरा होंगे, क्या यशपाल आर्या, प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल, हरक सिंह रावत या करण महरा इसे लेकर स्थिति साफ नहीं है, जबकि भाजपाई मानकर चल रहे हैं कि पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर ही भाजपा विधानसभा चुनाव में उतरेगी, ऐसे संकेत पहले से मिल रहे हैं।

12

नेशनल

नमो युग के 12 बरस

एनडीए के 12 वर्षों की एक सफलता ये है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है, कांग्रेस ने देश को लाचारगी, बेचारगी और ...

16

धरोहर

अल्मोड़ा में पाषाण जीवन के प्रमाण

नवपाषाण यानी नियोलिथिक युग, काल, अवधि, या नव पाषाण युग मानव प्रौद्योगिकी के विकास ...

14

उत्तर प्रदेश

विपक्षी सियासत दांव पर

जनगणना अभियान में प्रशासनिक सिस्टम को घर-घर जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन करना है ...

18

उत्तराखंड

पुनर्वास की चुनौती

उत्तराखंड में 465 गांव ऐसे हैं, जिन्हें संवेदनशील माना गया है, इन गांवों को कहीं और बसाया जाना है ...

साकेत अग्रवाल

राम मंदिर पर फिर सियासत

उत्तर प्रदेश का अयोध्या शहर पहले राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद के लिए दुनिया भर में चर्चित रहा फिर भव्य राम मंदिर के निर्माण को लेकर पूरी दुनिया में अयोध्या ने सुर्खियां बटोरी। अब यही अयोध्या शहर भगवान श्रीराम के भव्य मंदिर में आने वाले चढ़ावे की चोरी को लेकर सुर्खियों में है। सिर्फ इतना ही नहीं अब मंदिर में दान राशि की चोरी का मुद्दा यूपी की राजनीति के केंद्र में भी आ चुका है। समाजवादी पार्टी के बाद कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को भाजपा के खिलाफ हथियार बना लिया है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगले बरस फरवरी में विधानसभा चुनाव होने है। लिहाजा राजनीति का पारा तो हाई होगा ही। विपक्षी दलों को अयोध्याकांड में सत्ता नजर आ रही है। इसलिए सपा मुखिया अखिलेश यादव ने 7 जून को श्रीराम जन्मभूमि मंदिर से 5 से 7 करोड़ रुपये के चढ़ावा चोरी का डंका पीटा। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने अयोध्या में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अखिलेश से आगे निकलते हुए दावा किया कि मंदिर के दान में लगभग 200 करोड़ रुपये की हेराफेरी की गई है, लेकिन अब तक केवल 80 लाख रुपये ही बरामद हुए हैं। केजरीवाल के चेले चपाटे राम मंदिर में 1000 से अधिका की हेराफेरी का दावा करने लगे। यूपी में चढ़ावा चोरी के यज्ञ में कांग्रेस आहुति डालने में पीछे कैसे रहती? लिहाजा राहुल गांधी को इस मुद्दे पर बोलने से रोकते हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने अयोध्या के श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी की रकम 1400 करोड़ रुपये बता दी। साथ में भाजपा और आरएसएस को चढ़ावा चोरी में घसीट लिया। जबकि श्रीराम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से इन दोनों संगठनों का कोई सीधा वास्ता नहीं है। ट्रस्ट में सभी पदाधिकारी व सदस्य विश्व हिंदू परिषद से जुड़े लोग हैं। खैर अब विपक्षी दलों में कंपटीशन इस बात को लेकर हो रहा दिखता है कि कौन चढ़ावे की चोरी हुई राशि को कितना अधिक बता कर आगे निकल सकता है। अखिलेश यादव ने 7 करोड़ रुपये की चोरी का आरोप लगाया तो अरविंद केजरीवाल ने अखिलेश को पीछे छोड़ दिया। कांग्रेस को लगा कि वो अयोध्याकांड में समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी को पछाड़ कर आगे निकलेगी, लिहाजा अजय राय ने चोरी की रकम बढ़ाकर 1400 करोड़ रुपये कर दी। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या दान चोरी की रकम निर्धारित करने वाले विपक्षी दलों के नेता भी चोरी में शामिल हैं? यह सवाल इसलिए क्योंकि चोरी हुए चढ़ावे के आकंड़े इन नेताओं को मिले कहां से? 7 करोड़, 200 करोड़ या फिर 1400 करोड़ की चोरी का दावा किस आधार पर किया जा रहा है? इन नेताओं के पास यदि चोरी के कोई सबूत है तो फिर अयोध्या पुलिस अथवा एसआईटी को क्यों नहीं देते, सिर्फ बयानबाजी से राम भक्तों के विश्वास को डगमगाया नहीं जा सकता है। क्या इस तरह की राजनीति से उत्तर प्रदेश की सत्ता पाना आसान हो सकता है?

समाजवादी पार्टी हो या आम आदमी पार्टी अथवा कांग्रेस ये वो दल हैं जिनके मुखिया राम मंदिर के विरोध में रहे हैं। सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने तो राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थीं। मुलायम सिंह के बेटे और सपा मुखिया अखिलेश यादव आज तक न तो राम मंदिर गए और न ही फूटी कोड़ी राम मंदिर के लिए दान में दी, लेकिन राम मंदिर पर सियासत फुल कर रहे हैं। चुनाव करीब है इसलिए श्रीराम के लिए बिचलित हो रहे हैं। खुद को सबसे बड़ा राम भक्त साबित करने की फिराक में हैं। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल भी चढ़ावा चोरी से बहुत बेचैन हैं। ये वही केजरीवाल हैं जो मीडिया को नानी की कहानी सुनाते थे कि मेरी नानी कहती थी कि मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़कर बनाए गए मंदिर में नहीं बस सकता। केजरीवाल की पार्टी के ही संजय सिंह ने संसद परिसर में नारा लगाया था कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्रीराम। एक और आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा था कि मंदिर व मस्जिद वालों से पूछकर वहां एक अच्छी यूनिवर्सिटी या अस्पताल बना दो, राम मंदिर बनने से राम राज्य नहीं आएगा। बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस ने तो राम के अस्तित्व को ही नकार दिया था। श्रीराम को काल्पनिक बता दिया था। ये वो नेता हैं जिन्होंने कभी राम काज में कोई हाथ नहीं बटाया, लेकिन आजकल राम काज करने वालों पर सवाल उठा रहे हैं। खुद को ब्रह्मांड का सबसे बड़ा राम भक्त दर्शाने की सुपारी लेकर घूम रहे हैं। खैर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, जिनकी टीआरपी अयोध्याकांड से भी कम नहीं हुई। यूपी ही नहीं देश के सनातनियों को भरोसा है कि योगी आदित्यनाथ अयोध्याकांड के किसी भी दोषी को छोड़ने वाले नहीं हैं। जिन्होंने चढ़ावे की जितनी चोरी की है वो ब्याजा सहित वसूल कर लेंगे। योगी आदित्यनाथ ने भी विपक्षियों खासकर अखिलेश यादव को चुनौती दे दी है, उन्होंने एक जनसभा में कहा कि अयोध्या तो रामभक्तों ने सजा दी है। जो सनातन की चिंता कर रहे हैं, जो खुद को सनातनी और धार्मिक बताने की कोशिश कर रहे हैं वो मथुरा में श्रीकृष्ण मंदिर पर खुलकर बोलें। मथुरा में श्रीकृष्ण मंदिर बनाने के लिए आगे आएं, आंदोलन करें। लेकिन चुनाव के सीजन में हिंदू बनने का नाटक करने वाले सपा मुखिया अखिलेश यादव, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं को मुसलमानों की ज्यादा चिंता रहती है। मुल्ला और मौलवियों के सामने ये घुटने टेके रहते हैं। इससे यूपी की सियासत में नई बहस शुरू हो गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि जिस राम मंदिर के निर्माण का सपा ने सालों तक विरोध किया, उसी मंदिर को लेकर अब सवाल उठाना राजनीतिक अवसरवाद जैसा लगता है। आलोचकों का मानना है कि मंदिर की भव्यता, करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और उसके महत्व पर कभी सकारात्मक टिप्पणी न करने वाले नेता अचानक चढ़ावे की पारदर्शिता पर सवाल खड़े करते हैं, तो सवाल उन नेताओं पर भी उठते हैं जो सनातन को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। क्योंकि 1990 में अयोध्या में कारसेवकों पर हुई पुलिस कार्रवाई और गोलीकांड का दृश्य आज भी सनातनियों के जहन में है। ●

पंजाबी की निर्वाचित कहानियां

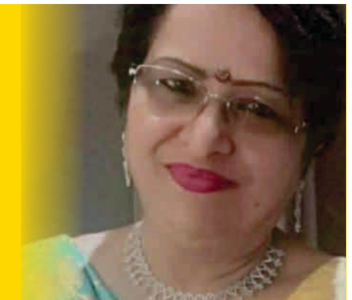

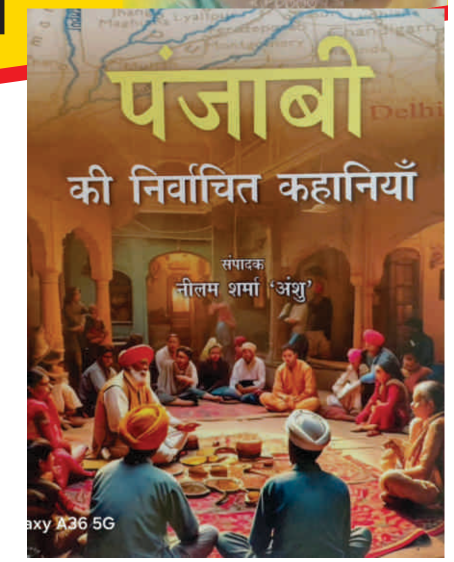

इस संग्रह की पहली कहानी नानक सिंह की अंतिम किरण है, जिसमें एक कोठे पर लेखक से होने वाली गुफ्तगू है, जहां एक वेश्या कहती है-'दिल जैसी चीज कौन किसके पास अमानत रखता है? हम लोगों के पास जो दिल बतौर अमानत रखे जाते हैं ना वे असली नहीं होते और ऐसे दिलों की कीमत भी कोई बहुत ज्यादा नहीं होती।'

रावेल पुष्प
बोस रोड, कोलकाता

वैसे तो हर भाषा का अपना-अपना साहित्य है, लेकिन दूसरी भाषा के साहित्य से परिचय तो अनुवाद के माध्यम से ही हो सकता है। इसी संदर्भ में अगर हम पंजाबी के समृद्ध कथा साहित्य की बात करें तो कई नाम हमारे सामने आते हैं, जो अनुवाद के कारण ही हिंदी के पाठकों को अपने लगते हैं। मसलन- नानक सिंह, करतार सिंह दुग्गल, अमृता प्रीतम, बलवंत गार्गी और भी कई। मुझे याद आता है राजपाल एंड संस की 2009 में अलग-अलग भाषाओं की श्रेष्ठ कहानियों की एक सीरिज आई थी, जिसमें पंजाबी की 18 श्रेष्ठ कहानियां विजय चौहान के संपादन में प्रकाशित हुई थीं। उसके बाद भी इस तरह के प्रयास हुए हैं। इधर हाल ही में नीलम शर्मा 'अंशु' के संपादन में शानदार हार्ड बाउंड में एक पुस्तक आई है 'पंजाबी की निर्वाचित कहानियां', जिसमें कुल मिलाकर 27 कथाकारों की कहानियां हैं, जिनका अनुवाद भी नीलम ने ही किया है। इस संग्रह की कहानियों का चयन नीलम ने अपनी रूचि और विवेक से किया है। यहां ये कोई दावा भी नहीं है कि ये पंजाबी की श्रेष्ठ कहानियां हैं। हां उनके चयन में वो कहानियां आ पाई हैं, जिन कहानियों के किसी न किसी पक्ष ने उनके दिल को गहराई तक छुआ है। नीलम दरअसल बंगाल में रहते हुए नेशनल लाइब्रेरी के माध्यम से पंजाबी साहित्य का रसास्वादन ले सकीं। इसके साथ ही पंजाबी में इन दिनों लगभग हर विषय पर कहानियां लिखी जा रही हैं और इन सब से गुजरते हुए उनकी सदिच्छा रही कि हिंदी पाठकों तक ये कहानियां पहुंच सकें। वैसे ये तो महज बानगी भर ही है, भविष्य में वे और भी अनूदित कहानियां पाठकों के लिए पेश करेंगी। इसके अलावा वे आकाशवाणी कोलकाता के एफएम चैनल पर लगभग 25 वर्षों तक रेडियो जॉकी भी रहीं हैं। उनकी हिंदी, पंजाबी और बांग्ला में आपसी अनुवाद की अब तक 21 पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है, जिसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित बांग्ला लेखक देवेश राय के उपन्यास 'तिस्ता पारेर ब्रितांतो' का साहित्य अकादमी के लिए ही सीधे पंजाबी में अनुवाद 'गाथा तिस्ता पार दी' शामिल है। इसके अलावे विभिन्न साहित्यक पत्रिकाओं में भी उनके द्वारा अनुदित कहानियां ससम्मान प्रकाशित होती रहती हैं।

इस संग्रह की पहली कहानी नानक सिंह की अंतिम किरण है, जिसमें एक कोठे पर लेखक से होने वाली गुफ्तगू है। जहां एक वेश्या कहती है-'दिल जैसी चीज कौन किसके पास अमानत रखता है? हम लोगों के पास जो दिल बतौर अमानत रखे जाते हैं ना वे असली नहीं होते और ऐसे दिलों की कीमत भी कोई बहुत ज्यादा नहीं होती। बल्कि कभी-कभी तो ये सब्जी मंडी के सड़े हुए आमों से भी सस्ते बिक जाते हैं।' लेकिन खुदा न खास्ता अगर कोई सच्चा मिल भी जाए तो समाज उसे जीने नहीं देता। एस बलवंत की कहानी-'दिल्ली में खोई चवन्नी' में कथा के बहाने पुरानी दिल्ली के इतिहास के कई अनछुए पहलू उजागर हुए हैं मसलन-सब्जी मंडी के ऊपर एक पहाड़ी थी, जहां एक मीनार बनी हुई थी उसे जीतगढ़ कहा जाता था। इसके अलावे जीबी रोड वाली आंटियों के बारे में यह भी सुना था कि शाही महल में रहने के कारण इनके पास तहजीब और बातचीत के सलीके का बहुत बढ़िया हुनर था। इन सब के सलीके और तहजीब में माहिर होने के कारण कई धनाढ्य माता-पिता द्वारा अपने बिगड़ैल शहजादों को तहजीब सीखने के लिए इन आंटियों के पास भेजते थे। इसी तरह वीना वर्मा की 'खरीदी हुई औरत' में पंजाब के ऐसे बंदे की कथा है जिनकी शादी किसी कारण से नहीं हो पाती थी। वैसे पंजाब में लड़कियों का अभाव भी काफी था। लोग बंगाल से गरीब घर की लड़कियां खरीद कर ले जाते थे और विवाह करते थे। इसी तरह इन चयनित कहानियों में पंजाब के रहन-सहन, सामाजिक ताने-बाने और वहां की मिट्टी की खुशबू भरी है। चयनित कहानीकारों में दिलीप कौर टिवाणा, रामस्वरूप अणखी, मोहन भंडारी, हमदर्द वीर नौश हरवी, जिंदर, वरियाम सिंह संधू, अजमेर सिद्धू, भगवंत रसूलपुरी, परवेज कौर संधू तथा अन्य शामिल हैं। इस चयन में एकाध कमजोर कहानी छोड़कर सभी जीवन के किसी न किसी पक्ष को बखूबी रेखांकित करती हैं और पंजाब की बनती-बिगड़ती आबोहवा से भी रु-ब-रु कराती हैं। नवीन प्रकाशन कोलकाता द्वारा प्रकाशित ये पुस्तक सही अर्थों में हिंदी पाठकों के लिए एक अनुपम उपहार है। ●

सुर्खियां

थरूर ने की मोदी की तारीफ

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉ. शशि थरूर ने एक लेख लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की तो कांग्रेस में खलबली मच गई। केरल के तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी नेतृत्व क्षमता की तारीफ करते रहे हैं, जो पार्टी में ही उनके विरोधियों को कई बार रास नहीं आती हैं। थरूर ने देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद पीएम मोदी के नेतृत्व की तारीफ करते हुए कहा है कि इससे यह बात तय हो गई है कि 21वीं सदी में भारत कैसे आगे बढ़ेगा। शशि थरूर ने 12 साल के पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का किया आकलन करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर प्रोजेक्ट सिंडिकेट में लिखे अपने एक लेख को री-पोस्ट किया है। शशि थरूर ने लिखा-क्या पिछले 12 सालों में भारत में बुनियादी बदलाव आया है? प्रोजेक्ट सिंडिकेट के लिए अपने हालिया लेख में डॉ. शशि थरूर ने मोदी सरकार के दौर में हुई तरक्की और उससे जुड़ी चिंताओं का आकलन करते हैं और बताते हैं कि इसका भारत के भविष्य पर क्या असर होगा। थरूर ने लेख में लिखा-है कि पिछले 12 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में आर्थिक आधुनिकीकरण और सरकारी क्षमता बढ़ाने के मामले में जबरदस्त तरक्की हुई है। साथ ही संस्थागत स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों को शामिल करने के मामले में निराशाजनक गिरावट भी देखी गई है। यह रिकॉर्ड इस बात की अहम जानकारी देता है कि भारत 21वीं सदी में कैसे आगे बढ़ेगा। थरूर ने लिखा है-10 जून को नरेंद्र मोदी देश के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा करने वाले चुने हुए प्रधानमंत्री बन गए। उन्होंने आजादी के दौर के नायक जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्होंने पहले आम चुनावों के बाद 4,398 दिनों तक पद संभाला था। थरूर ने लिखा-हालांकि नेहरू ने आम चुनाव से पहले भी पांच साल तक भारत का नेतृत्व किया था और इंदिरा गांधी ने कुल मिलाकर उनसे ज्यादा समय तक सेवा की थी, लेकिन लगातार नहीं।

जागेश्वर धाम का कायाकल्प

देवभूमि उत्तराखंड के पावन आंचल में स्थित विश्व प्रसिद्ध श्री जागेश्वर धाम में श्रद्धा, अध्यात्म और प्रकृति का एक अनूठा संगम आकार ले रहा है। जागेश्वर की पवित्र भूमि पर एक अत्यंत आधुनिक और भव्य आश्रम का निर्माण कार्य 75 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। देवदार के गगनचुंबी वृक्षों, शीतल हवाओं और हिमालय पर्वत की श्रृंखलाओं के अलौकिक दर्शन से विभूषित यह स्थान साधकों और श्रद्धालुओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। इस नवनिर्मित दिव्य परिसर में भक्तों की आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने और उनके प्रवास को सुगम बनाने के लिए विशेष निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। आश्रम के केंद्र में देवाधिदेव महादेव के नीलकंठ स्वरूप को समर्पित एक अत्यंत सुंदर और भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, जहां शिवभक्त शांत वातावरण में शिव की आराधना कर सकेंगे। मानसिक शांति और आत्मिक उन्नति के लिए परिसर में एक अत्याधुनिक ध्यान-योग केंद्र बनाया जा रहा है, जहां हिमालय की शुद्ध ऊर्जा के बीच ध्यान लगाना संभव होगा। दूर-दराज से आने वाले शिवभक्तों की सुविधा के लिए एक सर्व सुविधा युक्त धर्मशाला बनाई जा रही है, जिससे यहां रुकना सुगम हो जाएगा। इस पवित्र आश्रम में श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए उत्तम, स्वच्छ और सुरक्षित कमरे तैयार किए जा रहे हैं। यहां आने वाले हर भक्त के लिए शुद्ध, सात्विक भोजन और निरंतर चलने वाले भंडारे की उचित व्यवस्था की जाएगी। महामंडलेश्वर कैलाशानंद महाराज मुख्य पुजारी श्री ज्योतिर्लिंग जागेश्वर धाम ने अपने जीवन भर की कमाई, प्रापर्टी इस जनहित कार्य के लिए समर्पित कर दी है। देवदार के घने जंगलों से घिरा यह आश्रम प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक ऊंचाइयों का जीवंत उदाहरण होगा। इस आश्रम का विधिवत शुभारंभ आगामी श्रावणी मास को होना तय किया गया है। सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। इस अवसर पर प्राण प्रतिष्ठा, भव्य पूजा-अर्चना और भंडारे के साथ आश्रम को जनमानस के कल्याणार्थ समर्पित कर दिया जाएगा।

मन की बात

मोदी की सफल विदेश नीति

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वाधिक समय तक इस पद पर बने रहने का रिकॉर्ड कायम किया है। मोदी जी के 12 वर्षों के कार्यकाल के दौरान भारत ने प्रगति की नई ऊंचाइयों को छुआ है। जैसे कि पूरे देश में चमचमाते हुए एक्सप्रेस हाईवे का जाल, बॉर्डर पर सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण, हिमालय के दुर्गम क्षेत्रों में पूरे वर्ष निर्बाध यातायात के लिए बनाई गई सैकड़ों किलोमीटर लंबी सुरंगें, श्रीनगर तक रेल का पहुंचना यह सब अपने आप में महत्वपूर्ण सफलताएं हैं। दूसरी ओर सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन, सिंदूर, कश्मीर से धारा 370 का खात्मा, नक्सलवाद का समूल नाश, डिजिटल पेमेंट, मेक इन इंडिया, युवाओं को रोजगार देने वाले हजारों स्टार्टअप, करोना महामारी के चुंगल से देश को सुरक्षित निकाल लाना जैसे अनेकों इतने सारे बेहतरीन कार्य इनके कार्यकाल में हुए हैं कि उन सभी को एक बार में लिख पाना संभव नहीं है। वैश्विक राजनीति में मोदी जी की सफल विदेश नीति के कारण आज भारत का नाम पूरे विश्व में सम्मानपूर्वक लिया जाता है। यदि पिछली सरकारों के साथ तुलना की जाए तो कांग्रेस और कांग्रेस की नीतियां मोदी या भाजपा की नीतियों के सामने कहीं भी नहीं ठहरती। क्योंकि कांग्रेस ने सिर्फ बांटों और राजनीति की है, कांग्रेस के तुष्टीकरण के कारण देश का बहुसंख्यक खुद को दोयम दर्जे का नागरिक समझने लगा था।

चंद्र प्रकाश साह, अल्मोड़ा, उत्तराखंड

चुनाव जीतना भाजपा से सीखें

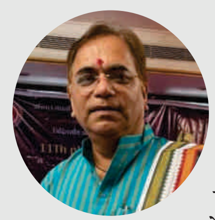

अगर मैं पिछले बारह वर्षों की केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का पुनरावलोकन करूं तो मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि मोदी सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 व धारा 25 को समाप्त कर एक देश एक संविधान लागू करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। क्योंकि देश के अभिन्न अंग जम्मू-कश्मीर में भारत का संविधान पूरी तरह लागू नहीं होता था। आतंकवाद के पोषक पाकिस्तान पर एक बार सर्जिकल स्ट्राइक एक बार एयर स्ट्राइक और फिर पहलगाम में धर्म पूछकर हिंदुओं की हत्या के बाद ऑपरेशन सिंदूर कर भारत की मोदी सरकार ने दुनिया को अपनी ताकत दिखाकर देश गौरव बढ़ाया है। चुनाव कैसे लड़ा और जीता जाता है यह भाजपा से अच्छा कोई नहीं जानता। महत्वपूर्ण ये नहीं कि आप सफलतापूर्वक सरकार चला रहे हैं महत्वपूर्ण ये है कि भाजपा ने अपने मेनिफेस्टों में जो मुख्य बिंदु देश के सामने रखे उसे केंद्र और राज्य सरकारों ने समय बद्ध और चरण बद्ध रूप से पूर्ण भी किया हैं। एक देश एक विधान हो या राष्ट्र या फिर प्रतीक्षारत समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी की शुरुआत और करोड़ों सनातनियों के आराध्य श्रीराम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण यही है असली मेरे अपने मन की बात।

प्रदीप भट्ट, कवि, मेरठ

पहले खास लोगों को मिलते थे पुरस्कार

देश की राजधानी दिल्ली के स्कूल में एक शिक्षिका होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात जब ऑल इंडिया रेडियो पर प्रसारित हो तब न केवल मैं सुनूं बल्कि अपने स्कूल और परिवार के बच्चों को उससे अवगत भी कराऊं। उन्हें बताऊं कि दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों या बच्चों द्वारा किस क्षेत्र में क्या रचनात्मक काम किए जा रहे हैं। नए इनोवेशन के प्रति बच्चों में कैसे नव उत्साह का संचार किया जा सकता है, इसके लिए हम सभी को निरंतर प्रयास करना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बच्चों को देश प्रेम एवं भारतीय सेना द्वारा किए जा रहे प्रतिकार की पूरी जानकारी बच्चों को विभिन्न माध्यमों से मिल रही थी, किंतु एक टीचर होने के नाते मैं स्वयं बच्चों को ऑपरेशन सिंदूर के विषय में जानने के लिए प्रेरित करती थी। आखिर वे ही तो इस देश का भविष्य हैं। हमने देखा है 2014 से पहले कुछ खास लोगों को राष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिलते थे, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने दूर दराज के गांवों कस्बों में रहने वाले उच्चकोटि विशिष्ट सेवा करने वालों को सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जिन्हें देश जानता भी नहीं था, लेकिन मोदी सरकार ने उनके राष्ट्र के प्रति समर्पण को पहचाना और उन्हें पद्मश्री, पद्मभूषण, पद्मविभूषण और भारत रत्न जैसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिए। सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वालों में आदीवासी क्षेत्र में काम करने वाले वो लोग भी शामिल हैं जिनके पैरों में चप्पल तक नहीं थीं

सन्तोष सम्प्रीति,
स्कूल टीचर, दिल्ली

ऑल इंडिया रेडियो पुर्नजीवित

सबको लगता है कि हर माह के अंतिम रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात करते हैं, पर इस बार मैं अपने मन की बात करना चाहती हूं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया के 34 देशों ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा है। यह सम्मान उन्हें वैश्विक कूटनीति, द्विपक्ष ीय संबंधों को मजबूत करने और भारत की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा के लिए दिए गए हैं। मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्हें वैश्विक स्तर पर पसंद किया जाता है, इससे पहले भारत के किसी प्रधानमंत्री को वैश्विक स्तर पर इतने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नहीं मिले हैं। ये मेरे लिए ही नहीं बल्कि हर भारतीय के लिए गौरव की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाज में अंतिम लाइन में खड़े अपने हर नागरिक के जीनव स्तर को सुधारने के लिए जनधन खाते खुलवाकर सीधे मदद की है। इससे महिलाओं की चिंताएं किसी हद तक दूर हुई हैं। मोदी सरकार के कार्यकाल में ही जीएसटी रिफॉर्म लागू हो पाया, मोदी सरकार ने नोट बंदी कर आतंकवाद की कमर तोड़ने काम किया है। डोकलाम में भारतीय सेना द्वारा चीनी सेना को उसी की भाषा में जवाब देना, पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करने से लेकर ऑपरेशन सिंदूर चलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साबित किया है कि ये नया भारत है। यही नहीं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने पहलगाम में धर्म पूछकर हिंदुओं की हत्या करने वाले आतंकियों के ठिकानों को न सिर्फ ध्वस्त किया बल्कि पानी बंद कर आतंकवाद के पोषक पाकिस्तान को बूंद-बूद पानी के लिए तरसा दिया है। मन की बात ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के माध्यम से ऑल इंडिया रेडियो को पुर्नजीवित भी कर दिया है।

अनन्या भट्ट, छात्रा खालसा कॉलिज
दिल्ली यूनिवर्सिटी

मन की बात

ग्रामीण भारत को निकट से देखा

मैं बिहार के सीतामढ़ी जिले से आती हूं। मैंने ग्रामीण भारत को निकट से देखा है। मैंने वो दिनों भी देखे हैं जब विकास की बातें बहुत होती थीं, लेकिन धरातल पर विकास स्पष्ट दिखाई नहीं देता था। आज जब मैं पिछले 40 वर्षों की यात्रा को याद करती हूं, तो मुझे यह स्वीकारने में कोई संकोच नहीं है कि पिछले दस वर्षों में विकास की जो गति मैंने देखी है, वो उससे 3 दशकों की तुलना में कहीं अधिक तीव्र, व्यापक और प्रभावशाली रही है। यह केवल मेरी व्यक्तिगत अनुभूति नहीं है। गांवों, कस्बों और शहरों में रहने वाले असंख्य लोग इस परिवर्तन को महसूस कर रहे हैं। सड़कें, बिजली, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी योजनाओं की पहुंच इन सभी क्षेत्रों में परिवर्तन दिखाई देता है जिसने आम नागरिक के जीवन को सीधे प्रभावित किया है। विकास अब केवल सरकारी घोषणाओं का विषय नहीं रह गया, बल्कि जनजीवन की वास्तविकता बनता दिखाई देता है। मेरे लिए पीएम नरेंद्र मोदी आज तक के सबसे बेस्ट नेताओं में से एक हैं। इसका कारण केवल उनका व्यक्तित्व नहीं, बल्कि उनका कार्य और कार्यशैली है। उन्होंने ऐसे अनेक निर्णय लिए जिन्होंने भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को नई दिशा देने का प्रयास किया है। एक सामान्य नागरिक के रूप में मुझे सबसे अधिक प्रभावित उनकी दूरदर्शिता, दृढ़ निश्चय और देशहित को सर्वोपरि रखने की भावना ने किया है।

अनामिका सिंह, कोलकाता

मोदी के 12 साल बेमिसाल

पीएम नरेंद्र मोदी के 12 साल बेमिसाल हैं। इन दिनों मोहर्रम का महीना चल रहा है, पीएम मोदी ने गुजरात के सूरत में बोरा समुदाय के इमामबाड़े में हजरत इमाम हुसैन का मर्सिया पढ़ने के बाद कहा कि वो भी बचपन में ताजियों के नीचे से निकलते थे। मान्यता है कि ताजियों के नीचे से बच्चों को निकाला जाता है जिससे कि वे दुख दर्द, रोगों से दूर रहें और दीर्घायु हों। पीएम का यह बयान इतिहास में दर्ज हुआ और उन्होंने यह कहकर कि वह ताजियों के नीचे से निकलते थे देश-दुनिया के करोड़ों मुसलमानों का दिल जीत लिया। मोदी ने कोरोना काल में लॉक डाउन लगाकर लाखों जिंदगियों को बचाया। मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजराईल और ईरान युद्ध के दौरान स्टेट आफ होर्मुज बंद होने से पेट्रोल और एलपीजी की दिक्कत नहीं होने दी। वैश्विक स्तर पर 17 जून 2026 को फ्रांस में जी-7 समिट के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक के दौरान पीएम मोदी ने कनेक्टिविटी व्यापार के लिए इंटरनेशनल मोबिलाइजेशन पार्टनरशिप फॉर एक्सलरेटिंग एंड ट्रेड पर जोर दिया। कांग्रेस का दौर और था उस समय भारत अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था और बंटवारे के दर्द से उबर रहा था। तब परिस्थितयां और थीं और आज परिस्थियां और हैं वह जिक्र करना बेकार है। आज भारत विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ रहा है। शीघ्र ही विकसित भारत भी बनेगा ऐसी उम्मीद है।

सुहेल जैदी, पत्रकार, रामपुर यूपी

मध्यम वर्ग पर महंगाई का बोझ

पीएम नरेंद्र मोदी का 12 वर्ष का कार्यकाल देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था और वैश्विक नीति में हस्तांतरण का दौर रहा है। देश में राजनीतिक स्थिरता रही है और कड़े निर्णय लेने वाली एक मजबूत सरकार की छवि उभरी है, डिजिटल इंडिया और जनधन, आधार, मोबाइल, डिजिटल भुगतान एवं सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थियों के खातों में पंहुचाना क्रांतिकारी कदम रहा, जिसने भ्रष्टाचार को कम किया। हाईवे, एक्सप्रेसवे, वंदे भारत ट्रेनें और हवाई अड्डों का विस्तार देश की प्रगति में साफ दिखता है। अनुच्छेद 370 की समाप्ति, नारी शक्ति वंदन एक्ट जैसे फैसलों ने देश की राजनीतिक दिशा को मजबूत किया। हर घर शौचालय और हर घर नल से जल जैसी योजनाओं ने ग्रामीण भारत के जीवन स्तर में बड़ा सुधार किया है। पिछले एक दशक में युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन न होना और मध्यम वर्ग पर महंगाई का बोझ बड़ी चिंता है। 2016 में नोटबंदी के फैसले से छोटे व्यापारियों और असंगठित क्षेत्र को जो झटका लगा, उससे उबरने में लंबा समय लगा। कृषि कानूनों को लागू करने तथा विरोध के कारण उन्हें वापस लेने की पूरी प्रक्रिया में किसान संगठनों और सरकार के बीच संवाद की कमी नजर आई। सामाजिक ताने-बाने में राजनीतिक और धार्मिक ध्रुवीकरण बढ़ा है, जिससे समाज में आपसी सामंजस्य पर असर पड़ा है। पीएम मोदी वैश्विक स्तर पर अब तक के सबसे प्रभावशाली और मुखर नेताओं में से एक हैं।

विनोद शाह,
प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, मुंबई

मोदी का 12 वर्षों का कार्यकाल प्रभावशाली

प्रधानमंत्री का 12 वर्षों का कार्यकाल भारतीय राजनीति में सबसे प्रभावशाली माना जाता है। समर्थक और आलोचक दोनों उनके कार्यकाल को बड़े बदलावों का दौर मानते हैं। ऐसे फैसले जिन्हें समर्थक प्रमुख उपलब्धि मानते हैं। बुनियादी ढांचे पर बड़ा निवेश, डिजिटल इंडिया और यूपीआई, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) अनुच्छेद 370 हटाना, विदेश नीति, कोविड वैक्सीनेशन, वो फैसले जिनकी आलोचना हुई, नोटबंदी, कृषि कानून, रोजगार सृजन, सामाजिक ध्रुवीकरण के आरोप, संस्थागत स्वतंत्रता पर बहस शामिल हैं। राष्ट्रीय स्तर पर पीएम मोदी अत्यंत लोकप्रिय और चुनावी दृष्टि से सफल नेता रहे। निर्णय लेने की मजबूत क्षमता और केंद्रीय नेतृत्व शैली के लिए जाने जाते हैं। लेकिन आलोचक कहते हैं कि सत्ता का केंद्रीकरण बढ़ा है। वैश्विक स्तर पर भारत की पहचान पहले की तुलना में अधिक प्रमुख दिखाई देती है। मोदी विश्व मंच पर सबसे अधिक पहचाने जाने वाले भारतीय नेताओं में गिने जाते हैं। हालांकि विदेश नीति की सफलता का मूल्यांकन विश्लेषक अपने तरीके से करते हैं। यदि प्रभाव और परिवर्तन की दृष्टि से देखा जाए, तो मोदी स्वतंत्र भारत के सबसे प्रभावशाली पीएम माने जाएंगे। उनके समर्थक उन्हें परिवर्तनकारी और निर्णायक नेता मानते हैं, जबकि आलोचक उनके कार्यकाल को आर्थिक, सामाजिक और संस्थागत चुनौतियों से जोड़कर देखते हैं। दोनों पक्षों के तर्क मौजूद हैं, इसलिए अंतिम मूल्यांकन काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि आप आर्थिक विकास, सामाजिक समरसता, राष्ट्रीय सुरक्षा, लोकतांत्रिक संस्थाओं और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में से किसे अधिक महत्व देते हैं।

ललित दुमका,
कौशल्या एनक्लेव रूद्रपुर।

राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता नहीं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का कायाकल्प होते देखना अत्यंत प्रेरणादायी है। उन्होंने देश को मेक इन इंडिया के दूरदर्शी विचार पर लाकर खड़ा किया है, जिसने देश के युवाओं और कार्यबल (वर्कफोर्स) में आत्मनिर्भर बनने की एक नई चेतना और ऊर्जा का संचार किया है। तकनीकी क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए देश में सेमीकंडक्टर चिप उद्योग की स्थापना करना, उनकी इसी दूरगामी सोच का परिणाम है। इसके साथ ही, दशकों पुरानी जटिल समस्याओं का समाधान करते हुए अनुच्छेद 370 का उन्मूलन करना, भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण कराना और समान नागरिक संहिता (यूसीसी) जैसे ऐतिहासिक निर्णयों की दिशा में आगे बढ़ना, उनके दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए कठिन आंतरिक सुरक्षा नीतियों और वैधानिक सुधारों को लागू करते हुए, अवैध घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने का उनका कड़ा रुख यह साबित करता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में वे कोई समझौता नहीं करने वाले नेता हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा और सांस्कृतिक पुनरुत्थान के साथ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूलमंत्र पर चलते हुए समाज के हर वर्ग को आगे ले जाने की उनकी यह कार्यशैली वास्तव में बेहद अनुकरणीय और प्रेरणाप्रद है। मैं यह मानती हूं कि देश को सशक्त बनाने के लिए हमें योग्यता को प्राथमिकता देनी होगी।

डा.उर्वशी श्रीवास्तव, विचारक,
ईएम बाइपास कोलकाता।

विकसित देश बन जाएंगे

आजादी के बाद देखा जाए तो 12 वर्ष का समय स्वर्णिम काल कहा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कुशल वक्ता, दूरदर्शी रणनीतिकार और जनता की नब्ज पहचानने वाले लोकप्रिय नेता के रूप में देखे जाते हैं। उनमें कड़े और बड़े फैसले लेने की इच्छाशक्ति है, जो उन्हें समकालीन राजनीति में सबसे आगे खड़ा करती है। अगर कोई खास तौर पर उन क्षेत्रों के नाम पूछे जिनमें सुधार हुआ है, तो जवाब होगा सभी क्षेत्रों में बेहतर काम हुआ है। 12 वर्षों में आंतरिक और राष्ट्रीय सुरक्षा, डिजिटल गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और वैश्विक साख के मामले में भारत का बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला है। पीएम मोदी ने हर क्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव डाला है। देश के सांप्रदायिक माहौल में परिवर्तन देखने को मिला है। मोदी की कूटनीति दुनिया में अग्रणी देश बनने का संदेश देती है। मोदी की वजह से भारत के प्रति दूसरे देशों की सोच बदली है और एक नई विश्व व्यवस्था का रास्ता खुला है। तथाकथित विकसित देशों को भी अपनी कार्ययोजना पर पुनर्विचार करना पड़ रहा है। अब हम गर्वित भारतीय हैं और दुनिया में सिर उठाकर चल सकते हैं। हमारे पासपोर्ट की रैंकिंग पहले से बेहतर हुई है। विकासशील देश हमें उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। अगर सब कुछ सही दिशा में आगे बढ़ता रहा, तो 2047 तक हम एक विकसित देश बन जाएंगे, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए।

डा.सुधीर सिंह,
बाल रोग विशेषज्ञ,
मुरादाबाद

विदेशी धरती पर भारत की पहचान

निसंदेह कांग्रेस के अलावा अन्य दलों की सत्ता बदली लोगों के स्वप्नों ने भी उड़ान भरी। कांग्रेस ने जब देश पर राज किया तब राजनीतिक दलों की इतनी बड़ी मंडी नहीं थी। विरोधी स्वर और समीक्षा करने वाले भी लगभग नगण्य थे। जो भी कॉपी में लिख दिया जांचने वालों ने नंबर दे दिए। उस समय की राजनीति में विदेशी परिवार से राजनीतिक रिश्तों के कारण सत्ता का रुझान भी विदेशी रहा। भाजपा ने जब सत्ता संभाली, कुछ बरगद के पेड़ों को उखाड़ा ही नहीं छोटे-छोटे गमलों पर भी कैमरा लगा दिया। पीएम मोदी ने विदेशी धरती पर भारत की पहचान ही नहीं बनाई, बल्कि भारत को सम्मान दिलाने में भी सार्थक पहल की। भारत ने विकास की विभिन्न योजनाओं के साथ ही सीमा सुरक्षा और हथियारों के निर्यात में भी रिकॉर्ड सफलता अर्जित की। कुछ असामाजिक शक्तियां फन फैला रही थी, उनको बीजेपी सरकार कुचलने में सफल रही, लेकिन तीसरे कार्यकाल में जनता यह अपेक्षा करती थी कि राजनीतिक शुद्धिकरण के साथ ही भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। कुछ ठोस फैसले लिए जाएंगे जिससे जनता को राहत मिलेगी। राजनेताओं की सुविधा में कोइ कटौती होगी। यदि आगामी चुनावों में बीजेपी को अपना आधार मजबूत करना हैं तो कुछ ठोस फैसले लेने होंगे। धरातल पर अब जनता का भाजपा से धीरे-धीरे मोहभंग हो रहा है। अयोध्या के घोटाले के दाग छुड़ाने में यह सर्फ काम नहीं करेगा। तत्काल मुफ्त भोजन और अनुदान बंद होने चाहिए।

एचपी शर्मा
मुरादाबाद

बैंकों की मनमानी

जहां तक हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल का विश्लेषण करते हैं तो निश्चित रूप से कई माध्यमों जिनमें डिजिटल इंडिया, मुफ्त राशन, 4 करोड़ परिवारों को आवास, किसान सम्मान निधि, जन औषधि केंद्र, डीबीटी, यूपीआई पेमेंट, इनकम टैक्स में अभूतपूर्व छूट, धारा 370 का हटाना, 553 नये रेलवे स्टेशन बनाना 1500 नए ओवर ब्रिज का निर्माण 200 से अधिक बेकार कानून हटाकर जनता को राहत देने जैसी योजनाओं से आम जनता सीधे लाभान्वित हुई है। केंद्र की कुछ योजनाएं ऐसी भी हैं जो धरातल पर उस रूप में नहीं उतर पाई जिस तरह लागू होनी थी, मसलन एमएसएमई, मुद्रा लोन जैसी योजनाओं में बैंकों की मनमानी उजागर होती रही हैं। जबकि इन योजनाओं में बैंक लोन की गारंटी सरकार देती है। इसी प्रकार कई अन्य योजनाएं हैं जिस पर नौकरशाही के हावी होने से पात्रों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। भाजपा सरकार के लिए राम मंदिर का निर्माण एक बड़ी उपलब्धि के रूप में याद किया जाएगा, जो करोड़ों हिंदुओं की आस्था का शानदार उदाहरण है। 500 वर्षों से ज्यादा श्रीराम जन्मभूमि मंदिर का विवाद बिना किसी हंगामे के शांतिपूर्ण तरीके से तय हो गया सभी पक्षों ने देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले को स्वीकार किया। अब समय है धर्म की व्यवस्था से हटकर रोजगार, ग्रामीण पलायन, स्वास्थ्य, शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने का ताकि उत्तराखंड जैसे राज्य से पलायन पर ब्रेक लग सके।

विजय पंत,
अधिवक्ता, नैनीताल

ट्रस्ट पर कैसे करें 'ट्रस्ट'

चुनौती केंद्र सरकार के सामने भी है कि वो श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का नए सिरे से गठन करे और ऐसे लोगों को शामिल करे जो ईमानदारी, निष्ठा, पारदर्शी और बिना झोल के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर का प्रबंधन संभाले और फिर कोई लापरवाही न हो, जिससे श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर राम भक्तों का फिर से 'ट्रस्ट' कायम हो सके।

केके चौहान

राम नाम की लूट है लूट सके तो लूट अंत समय पछताएगा जब भांडा जाएगा फूट...। यही हुआ भांडा फूटा तो कलंक उन पर भी लगा जो आजीवन निष्कलंक रहे। जिन्होंने राम जन्मभूमि मंदिर के लिए जीवन खपा दिया। वो चंपत राय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नगीना की सराय मीर के रहने वाले हैं। चंपत राय का पूरा नाम चंपत राय बंसल है। उनका जन्म 1946 में रामेश्वर प्रसाद बंसल के परिवार में हुआ था। चंपत राय बचपन से ही आरएसएस से प्रभावित थे। संघ के विचारों के प्रचार-प्रसार के लिए कड़ी मेहनत की और संगठन के लिए एक प्रचारक के रूप में कार्य किया। उन्होंने बिजनौर जिले के धामपुर में स्थित आरएसएम डिग्री कॉलेज में भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में भी काम किया। 1975 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई तो चंपत राय को भी गिरफ्तार किया गया था। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह खुद को राम मंदिर आंदोलन के लिए समर्पित कर दिया। राम जन्मभूमि मंदिर की अदालती लड़ाई से लेकर मंदिर निर्माण तक में चंपत राय की बड़ी अहम भूमिका रही है। केंद्र सरकार ने फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अयोध्या में भव्य श्रीराम मंदिर निर्माण और प्रबंधन की जिम्मेदारी के लिए श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया था। चंपत राय बंसल को ट्रस्ट का महामंत्री बनाया गया था। चंपत राय को राम लला का 'रिकॉर्ड कीपर' भी कहा जाता है। मंदिर निर्माण के समय से ही चंपत राय विवादों का हिस्सा बन गए। उन पर पहले भूमि खरीद घोटाले का आरोप लगा, फिर चंदे में हेराफेरी का आरोप लगा, लेकिन चंपत राय सतर्क होने के बजाये एक के बाद एक गंभीर चूक करते रहे। अब उम्र के आखिरी पड़ाव पर उनकी एक बड़ी और गंभीर लापरवाही ने उनके जीवन भर की निष्कलंकिता को कलंकित कर दिया। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर से चढ़ावा चोरी का खुलासा होने के करीब 15 दिन बाद चंपत राय को ट्रस्ट के महामंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ा। उनके साथ ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने भी ट्रस्ट की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है। लेकिन त्यागपत्र देने में जो देरी की गई उससे भी ट्रस्टियों पर संदेह गहराता है। होना ये चाहिए था कि जिस दिन चढ़ावे की चोरी का आरोप लगा था उसी दिन या अगले दिन चंपत राय सहित ट्रस्ट के बाकी पदाधिकारी व सदस्य खुद से त्यागपत्र देकर कहते कि जांच होने तक वो मंदिर के प्रबंधन से खुद को अलग रखेंगे। तब तो माना जाता कि चढ़ावा चोरी में ट्रस्ट की भूमिका नहीं है, लेकिन राम काज में हेराफेरी करने वालों की बुद्धि भ्रष्ट हुई और जब तक त्यागपत्र दिया बहुत देर हो चुकी थी। वैसे यह सच है कि चंपत राय को चढ़ावा चोरी की पूरी जानकारी थी। चंपत राय ने ही 5 जून को चढ़ावा चोरी करने वाले अविनाश के घर पुलिस के साथ छापा मारकर कैश बरामद किया था, फिर भी चढ़ावे की चोरी करने वालों के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं कराई, जबकि अयोध्या पुलिस चंपत राय से बार बार कहती रही कि ये गंभीर अपराध है, इसकी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए लेकिन चंपत राय ने एफआईआर दर्ज कराने से साफ इनकार कर दिया। लिहाजा उनकी भूमिका चढ़ावा चोरी में मानी जा रही है। इस बात का उल्लेख एसआईटी की रिपोर्ट में भी है। रिपोर्ट में अनिल मिश्रा की पिछले कुछ दिनों में अचानक बढ़ी संपत्ति का भी उल्लेख है।

आरएसएस और वीएचपी चंपत राय और अनिल मिश्रा को बचाने के पक्ष में नहीं हैं, दोनों संगठन चाहते हैं कि चोरी की निष्पक्ष जांच के लिए चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा दें, लिहाजा वीएचपी के महामंत्री बजरंग लाल बागड़ा, केंद्रीय संगठन महामंत्री मिलिंद पराडे और केन्द्रीय सह-संगठन महामंत्री विनायक राव को अयोध्या भेजा गया, तीनों ने चंपत राय और अनिल मिश्रा साफ बता दिया कि वीएचपी का नेतृत्व क्या चाहता है?

ट्रस्ट की विश्वसनीयता संदिग्ध

ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि जिस ट्रस्ट पर मंदिर के प्रबंधन की जिम्मेदारी थी उसके महामंत्री चंपत राय क्या अपने ड्राइवर को असीमित अधिकार दे सकते थे? चंपत राय क्या ट्रस्ट के सिंहासन पर बैठने के लिए महामंत्री बनाए गए थे? मंदिर में लम्बे समय से चोरी होती रही और ट्रस्ट के किसी सदस्य या पदाधिकारी को इसकी भनक तक नहीं लगी ऐसा कैसे हो सकता है? सवाल ये भी कि चढ़ावा चोरी की जानकारी होने के बावजूद ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने क्या इसे रोकने की कोई कोशिश की, यदि नहीं की तो फिर चढ़ावा चोरी में चंपत राय ही नहीं पूरा ट्रस्ट शामिल माना जाए। सभी के खिलाफ एफआईआर हो और सभी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्योंकि यह कोई छोटा पाप नहीं है बल्कि करोड़ों राम भक्तों की आस्था से विश्वासघात है। सवाल ये भी कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय के पास श्रीराम मंदिर की बड़ी जिम्मेदारी थी, असीमित अधिकार थे, लेकिन उन्होंने अपने मामूली से ड्राइवर रमाशंकर यादव उर्फ टून्नू यादव को वो अधिकार क्यों दिए? रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव ही श्रीराम मंदिर चढ़ावा और चंदा घोटाले का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है। क्योंकि उसका अतीत बेहद साधारण रहा है। उसके पिता अयोध्या में नया घाट क्षेत्र में चाय बेचते थे और टिन्नू यादव टेंपो चलाने के साथ ड्राइवरी करता था। राम मंदिर निर्माण की शुरुआत में वो किसी तरह चंपत राय का ड्राइवर बन गया। फिर इसके बाद अचानक उसके पास अकूत दौलत आने लगी। वह ट्रस्ट में वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालने लगा। अब वो 50 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का मालिक है। रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव की दौलत बढ़ने से पूरे अयोध्यावासी इसकी चर्चा करने लगे, लेकिन चंपत राय आंख मूंदे क्यों बैठे रहे? ये वो सवाल हैं जो ट्रस्ट की विश्वसनीयता तो संदिग्ध बनाते हैं। लिहाजा करोड़ों राम भक्त श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर कैसे भरोसा रखे? कैसे माने कि जो दान वो राम काज के लिए दे रहे हैं वो उनके आराध्य प्रभु श्रीराम के काज में लग रहा है या श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में घुसे कालनेमियों की जेबों में जा रहा है।

चढ़ावा चोरी का खुलासा

दरअसल 7 जून 2026 को समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक पवन पांडे ने सार्वजनिक तौर पर आरोप लगाया कि श्रीराम मंदिर के दान-पात्रों से 7 से 7.5 करोड़ रुपये की चोरी हुई है। पूर्व विधायक के इन आरोपों से देश की राजनीतिक में भूचाल आ गया। 9 जून 2026 को भाजपा नेता डॉ. रजनीश सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर कथित चंदा चोरी मामले की सीबीआई जांच की मांग की। इसके बाद पीएमओ ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी। 13 जून 2026 को राम मंदिर ट्रस्ट की सिफारिश पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चंदा चोरी की जांच के लिए तीन सदस्यों वाली एसआईटी का गठन किया। 14-21 जून 2026 तक एसआईटी ने कैश-हैंडलिंग प्रोसेस और 35 डोनेशन बॉक्स पर ध्यान केंद्रित करके अपनी जांच को आगे बढ़ाया। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि उसने 27 अप्रैल 2026 से 5 जून 2026 तक उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज की जांच की। इस दौरान 72 बार कैश चोरी की गतिविधियां सामने आईं। रिपोर्ट में कहा गया है कि जांच के दौरान मिले अहम सबूतों से दान चोरी की पुष्टि हुई है। चढ़ावे के गणना कक्ष तक नगदी संचालन और प्रबंधन व्यवस्था में बड़ी खामियां मिली। जांच में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों, गवाहों के बयान और आरोपियों से पूछताछ के आधार पर आठ लोगों को आरोपी बनाया गया है। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि ट्रस्ट को काफी पहले ही चोरी की आशंका हो गई थी। लिहाजा सितंबर 2024 और फरवरी 2025 में ट्रस्ट और भारतीय स्टेट बैंक के बीच कैश गणना प्रक्रिया को लेकर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) तैयार की गई। इस दस्तावेज पर स्टेट बैंक की ओर से गोविंद मिश्र और ट्रस्ट की ओर से अनिल मिश्र ने हस्ताक्षर किए थे। हालांकि बाद में एसओपी का पालन नहीं किया गया। जांच के दौरान पता चला कि टिन्नू यादव के पास बिना किसी आदेश के दान पेटियों की चाबियां रहती थीं। कई बैंक अधिकारियों के नाम भी सामने आए हैं। एसआईटी ने टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव की कैश चोरी की साजिश में अहम भूमिका बताई है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच कर रही एसआईटी ने चंपत राय और अनिल मिश्रा को भी दोषी पाया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चंपत राय ने चोरों के घर जाकर खुद चोरी की रकम बरामद की। अयोध्या पुलिस चंपत राय से बार बार कहती रही कि ये गंभीर अपराध है, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए

- **चंपत राय ने ही 5 जून को चढ़ावा चोरी करने वाले अविनाश के घर पुलिस के साथ छापा मारकर कैश बरामद किया था, अयोध्या पुलिस चंपत राय से बार बार कहती रही कि ये गंभीर अपराध है, इसकी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए लेकिन चंपत राय ने एफआईआर दर्ज कराने से साफ इनकार कर दिया था आखिर क्यों?**
- **फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अयोध्या में श्रीराम मंदिर निर्माण और प्रबंधन के लिए श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया था, चंपत राय को ट्रस्ट का महामंत्री बनाया गया, मंदिर निर्माण के समय से ही चंपत राय विवादों में फंस गए, उन पर भूमि खरीद घोटाले का आरोप लगा, फिर चंदे में हेराफेरी का आरोप लगा, पर चंपत राय सतर्क होने के बजाये गंभीर चूक करते रहे।**

लेकिन चंपत राय ने एफआईआर दर्ज कराने से इनकार कर दिया। लिहाजा भविष्य में चंपत राय और अनिल मिश्रा की मुश्किल बढ़ सकती है, यहां तक कि दोनों जेल भी जा सकते हैं? एसआईटी की रिपोर्ट के आने के बाद आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद चंपत राय और अनिल मिश्रा को बचाने के पक्ष में नहीं हैं। आरएसएस और वीएचपी के बड़े नेताओं की राय है कि निष्पक्ष जांच के लिए चंपत राय और अनिल मिश्रा अपने पदों से इस्तीफा दें। लिहाजा वीएचपी के महामंत्री बजरंग लाल बागड़ा, केंद्रीय संगठन महामंत्री मिलिंद परांडे और केन्द्रीय सह-संगठन महामंत्री विनायक राव को अयोध्या भेजा गया, इन तीनों ने चंपत राय और अनिल मिश्रा के साथ लंबी बात की और वीएचपी का नेतृत्व क्या चाहता है, ये साफ बता दिया। इस बैठक के बाद ही ट्रस्ट की तरफ से चढ़ावे की चोरी की एफआईआर दर्ज कराई गई। अब अगर कोई ये कहे कि चंपत राय सीधे-सादे हैं, तो ये बेकार का तर्क है।

नए ट्रस्ट का गठन होना चाहिए

25 जून 2026 को एसआईटी जांच के नतीजों के आधार पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की तहरीर पर श्रीराम जन्मभूमि थाने में 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और चंदे की गिनती करने वाले कर्मचारियों सहित आठ रमाशंकर यादव टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडेय, मनीष यादव, सुभाष श्रीवास्तव और रमा शंकर मिश्र को गिरफ्तार किया गया। ये सभी आपस में रिश्तेदार हैं, इन्हें चंपत राय और अनिल मिश्रा के कहने पर गिनती के काम में लगाया गया था। इनमें से 7 आरोपियों से करीब 79.84 लाख रुपये बरामद किए हैं। ये आरोपी मंदिर से कैश और ज्वेलरी अपने साथ ले जाते थे सीसीटीवी फुटेज में ये आरोपी कैश और जेवर चोरी करते साफ दिखाई दिए हैं। ये गिरफ्तारी अंतिम नहीं है, गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर चंपत राय और अनिल मिश्रा के साथ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों व सदस्यों की भूमिका की भी जांच होगी तो चौकाने वाले तथ्य सामने आएंगे। क्योंकि चढ़ावा, गहने और शिलाएं या कैश चोरी करने वाले तो गुनाहगार हैं लेकिन सबसे बड़े गुनाहगार वो हैं जिन्होंने श्रीराम मंदिर के चढ़ावे की चोरी होने दी। जिन पर श्रीराम मंदिर के प्रबंधन की जिम्मेदारी थी वो अपनी जिम्मेदारी से क्यों भागे? क्यों चोरी करने वालों को चोरी करने का मौका दिया? क्यों करोड़ों राम भक्तों की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम किया? चुनौती केंद्र सरकार के सामने भी है कि वो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का नए सिरे से गठन करे और ऐसे लोगों को शामिल करे जो ईमानदारी, निष्ठा, पारदर्शी और बिना झोल के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर का प्रबंधन संभाले और फिर कोई लापरवाही न हो जिससे श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर राम भक्तों का 'ट्रस्ट' कायम हो सके। क्योंकि राम मंदिर के दान में चोरी, लूट की लीपापोती और भाई-भतीजावाद लंबे अर्से से चल रहा था। चंपत राय ट्रस्ट को अपनी जागीर समझ बैठे थे, अपने ड्राइवर को मंदिर के खजाने की चाभियां सौंप दीं, उसे गिनती के काम में लगा दिया। ड्राइवर अपने भतीजे को ले आया। देखा देखी दूसरे लोग भी चोरी में शामिल हो गए। वे लोग भी अपने बेटे-दामाद को ले आए। चंपत राय और अनिल मिश्रा आग से खेलते रहे। कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे। ●

हैट्रिक लगा पाएंगे धामी ?

कांग्रेस सत्ता पाने के लिए बेचैन है, लेकिन उत्तराखंड में कांग्रेस का सीएम पद का चेहरा कौन होगा ? क्या हरीश रावत कांग्रेस का चेहरा होंगे, क्या यशपाल आर्या, प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल, हरक सिंह रावत या करण महरा इसे लेकर स्थिति साफ नहीं है, जबकि भाजपाई मानकर चल रहे हैं कि पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर ही भाजपा विधानसभा चुनाव में उतरेगी, ऐसे संकेत पहले से मिल रहे हैं।

अनिल मामगाई
वरिष्ठ पत्रकार

उत्तराखंड में राजनीतिक गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं। प्रदेश में कमजोर पड़ चुकी कांग्रेस दस साल से सत्ता से बाहर है, इसलिए उसे अपनी बंजर हो चुकी जमीन पर फसल लहराने की चुनौती है, तो अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा करने की तरफ बढ़ रहे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने चुनौती हैट्रिक लगाने की है। उत्तराखंड में कांग्रेस और भाजपा के अलावा बाकी दलों यूकेडी, वाम मोर्चा, बसपा सपा और आप जैसी पार्टियों का कोई खास वजूद नहीं है। इसलिए चुनाव तो कांग्रेस और भाजपा के बीच ही होगा। कांग्रेस सत्ता पाने के लिए बेचैन तो है, लेकिन उत्तराखंड में कांग्रेस का सीएम पद का चेहरा कौन होगा? क्या हरीश रावत कांग्रेस का चेहरा होंगे, क्या यशपाल आर्या, प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल, हरक सिंह रावत या करण महरा, इसे लेकर स्थिति साफ नहीं है, जबकि भाजपाई मानकर चल रहे हैं कि पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर ही भाजपा विधानसभा चुनाव में उतरेगी। ऐसे संकेत पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने हल्द्वानी दौरे के समय दिए थे। इसके बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तराखंड प्रवास के दौरान पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर लगभग मोहर लगा दी है। लिहाजा अभी तक तो यही माना जा रहा है कि भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव धामी के चेहरे पर ही लड़ेगी। क्योंकि पुष्कर सिंह धामी ने बहुत से एतिहासिक फैसले भी लिए इनमें उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करना, मदरसा बोर्ड समाप्त करना, सख्त नकल विरोधी कानून व धर्मांतरण विरोधी कानून को मंजूरी और चार धाम सहित पौराणिक स्थलों का विकास शामिल है। केदारनाथ-बदरीनाथ के पुनर्निर्माण कार्यों के साथ मानस खंड कॉरिडोर के जरिए कुमाऊं क्षेत्र के पौराणिक मंदिरों (कैंची धाम) को पर्यटन से जोड़ा गया है। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30 प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण दिया है। स्थानीय पहाड़ी उत्पादों को वैश्विक बाजार देने के लिए हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड की शुरुआत की है। धामी सरकार के कड़े और बड़े फैसलों के साथ विकास कार्यों को लेकर भाजपा चुनाव मैदान में होगी तो कांग्रेस सिर्फ पुष्कर सिंह धामी के फैसलों व विकास कार्यों को हवा-हवाई बताएगी।

उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में एसआईआर का असर भी देखने को मिलेगा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के सीमांत जिलों के बहुत से परिवार यूपी और उत्तराखंड दोनों राज्यों के चुनावों में मतदान करते रहे हैं, इस बार ये संभव नहीं होगा, यानी नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून जैसे मैदानी जिलों में एसआईआर का असर साफ नजर आएगा।

नेताओं का हृदय परिवर्तन

उत्तराखंड में कांग्रेस और भाजपा संगठन को मजबूत करने में लगे हैं। 28 मार्च को कांग्रेस की उत्तराखंड प्रभारी कुमारी शैलजा की मौजूदगी में रुद्रपुर के पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल सहित 6 पूर्व भाजपा नेताओं ने कांग्रेस की विचारधारा से समझौता कर लिया। यानी जो भाजपाई थे वो कांग्रेसी हो गए। रुद्रपुर विधानसभा से दो बार भाजपा के विधायक रहे राजकुमार ठुकराल ने 2022 में भाजपा का टिकट न मिलने पर बगावत की और निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया था। जिसके बाद भाजपा ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। राजकुमार ठुकराल विधायक बनने से पहले रुद्रपुर नगर पालिका के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। रुड़की के पूर्व मेयर गौरव गोयल ने भी कांग्रेस की विचारधारा स्वीकार ली है। हरिद्वार जिले में गौरव गोयल की अच्छी पकड़ बताई जाती है। घसाली से दो बार भाजपा विधायक रहे भीमलाल आर्य ने भी कांग्रेस का दामन थामा है। हालांकि 2016 से ही उनका रुझान कांग्रेस की ओर हो गया था। ऊधमसिंह नगर जिले की सितारगंज विधानसभा से दो बार बहुजन समाज पार्टी के विधायक रहे नारायण पाल ने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया है। भीमताल के ब्लॉक प्रमुख रहे लखन सिंह और उनकी पत्नी कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। मसूरी नगर पालिका अध्यक्ष रहे अनुज गुप्ता कांग्रेसी बन चुके हैं। भाजपा या बसपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने वाले ज्यादातर नेताओं का अब वो जनाधार नहीं रहा जो भाजपा में रहते हुए होता था। बसपा के नारायण पाल भाजपा में शामिल होना चाहते थे, उन्होंने कुछ भाजपा नेताओं से संपर्क भी किया, लेकिन बात नहीं बनी और कांग्रेस में जाना उनकी मजबूरी हो गई।

भाजपा व कांग्रेस की गुटबाजी में अंतर

कांग्रेस कुछ भाजपा नेताओं को अपने पाले में लाकर सत्ता का रास्ता तलाश रही है तो भाजपा भी पीछे नहीं है। राजकुमार ठुकराल की धुरविरोधी रुद्रपुर नगर पालिका की पूर्व अध्यक्ष मीना शर्मा कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गई। मई 2026 में ही रुद्रप्रयाग जिला पंचायत की पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मी राणा और घनसाली विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी दर्शन लाल आर्य ने भाजपा का दामन थाम लिया। इससे पहले 27 फरवरी 2026 को देहरादून में भाजपा के प्रदेश कार्यालय में एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस, बसपा, यूकेडी और अन्य दलों से जुड़े सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। खैर पाला बदलने की परंपरा तो चुनाव से एक साल पहले शुरू हो जाती है। कुछ नेताओं को टिकट कटने का डर रहता है तो कुछ चुनाव लड़ने के लिए विचारधारा बदल लेते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए करो या मरो जैसा है, यदि 2027 में कांग्रेस चुनाव हारती है तो फिर कांग्रेस उत्तराखंड से लुप्त हो सकती। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि लगातार तीसरा चुनाव हारने पर उत्तराखंड कांग्रेस में हताशा और निराशा बढ़ेगी, कार्यकर्ताओं और नेताओं का मनोबल टूटने लगेगा, कांग्रेस के वोट बैंक में निराशा जन्म लेगी। एक सच ये भी है कि कांग्रेस को विधानसभा चुनाव दो मोर्चे पर लड़ना है। पहला मोर्चा भाजपा से है तो दूसरा कांग्रेस की गुटबाजी का। क्योंकि कांग्रेस की गुटबाजी ने ही उत्तराखंड में कांग्रेस को कमजोर करने का काम किया है। गुटबाजी सिर्फ कांग्रेस में ही है, ऐसा भी नहीं है, ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं जिसमें गुटबाजी या भितरीघाती न होते हों, उत्तराखंड भाजपा में भी गुटबाजी है, राजनीति के जानकारों को सब पता रहता है, कौन किसके गुट में है, लेकिन भाजपा में एक खासियत है कि जब चुनाव आते हैं तो गुटबाजी पीछे रह जाती है और चुनाव जीतना प्राथमिकता बन जाती है। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व रुठे नेताओं और कार्यकर्ताओं को मनाने में एक्सपर्ट है, कई बार भाजपा कार्यकर्ता की नाराजगी सामने आई, लेकिन चुनाव से पहले ही शीर्ष नेतृत्व ने सब सामान्य किया है।

संगठन के तौर पर भाजपा भारी

2027 के विधानसभा चुनाव में संगठन की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मीडिया को बताने वाली रणनीति बता चुके हैं। मसलन भाजपा अपने मजबूत संगठन, पन्ना प्रमुख, मेरा बूथ सबसे मजबूत जैसे आधार पर हर चुनाव को जीतती है। संगठन का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र पोलिंग बूथ होता है, लिहाजा पिछले कई महीनों से भाजाप बूथ प्रबंधन पर फोकस कर रही है। प्रत्येक बूथ की बैठक हो रही हैं, शक्ति केंद्रों की बैठक हो चुकी है। हर स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके रणनीति बताई और बनाई जा रही है। भविष्य में चुनाव को पूरी तरह बूथ स्तर पर केंद्रित किया जा रहा है। इसके लिए बूथ की टोली को और सशक्त व सतर्क किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर विधानसभा कोर कमेटी और जिला कोर कमेटी बनाई गई है। जो भाजपा के सभी कार्यक्रमों व सरकारी योजनाओं को बेहतर ढंग से धरातल पर उतारने के लिए काम कर रही है। भाजपा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर युवा संवाद कार्यक्रम, पूर्व सैनिकों का सम्मलेन, महिला सम्मेलन और ओबीसी जातियों का सम्मेलन हो रहे हैं। भाजपा हर स्तर पर हर व्यक्ति को

- **2027 में कांग्रेस चुनाव हारती है तो फिर कांग्रेस उत्तराखंड से लुप्त हो सकती, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि लगातार तीसरा चुनाव हारने पर उत्तराखंड कांग्रेस में हताशा और निराशा बढ़ेगी, कार्यकर्ताओं और नेताओं का मनोबल टूटने लगेगा, कांग्रेस के वोट बैंक में निराशा जन्म लेगी।**
- **भाजपा अपने मजबूत संगठन, पन्ना प्रमुख, मेरा बूथ सबसे मजबूत जैसे आधार पर हर चुनाव को जीतती है, संगठन का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र पोलिंग बूथ होता है, लिहाजा पिछले कई महीनों से भाजाप बूथ प्रबंधन पर फोकस कर रही है, प्रत्येक बूथ की बैठक हो रही हैं, शक्ति केंद्रों की बैठक हो चुकी है।**

जोड़ने का काम कर रही है। प्रेदश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का मानना है कि फरवरी 2027 में चुनाव प्रस्तावित है, लेकिन अगर उससे पहले भी चुनाव होता है तो भाजपा चुनाव के लिए तैयार है। भाजपा एक बार फिर चुनाव जीतकर उत्तराखंड में जीत की हैट्रिक लगाएगी। फरवरी से पहले चुनाव की सुगबुगाहट इसलिए है क्योंकि 2027 के शुरू में ही हरिद्वार में कुंभ मेला भी आयोजित होना है। जनगणना का काम भी शुरू होना है, ऐसे में माना जा रहा है कि कुंभ से पहले भी चुनाव हो सकते हैं।

कांग्रेस की कितनी है तैयारी

भाजपा की तरह कांग्रेस भी अपने आप को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। हाल ही में उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा भी राज्य के दौरे पर आई थीं। उन्होंने भी प्रदेश भर में कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक की थी। कुमारी शैलजा ने उत्तराखंड के तमाम क्षेत्रों का भ्रमण भी किया था। इसी आधार पर उन्होंने आगामी चुनाव के लिए बेहतर रणनीति तैयार करने पर जोर दिया था। राजनीति के जानकार मान रहे हैं कि कांग्रेस भी सत्ता पर काबिज होने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना की मानें तो संगठन को मजबूत करने का काम कांग्रेस पिछले पांच साल से कर रही है। संगठन सृजन के बाद प्रदेश के सभी ब्लॉक में कांग्रेस का पुनर्गठन किया गया है। प्रदेश के सभी 27 संगठनात्मक जिलों और महानगर अध्यक्षों ने ब्लॉक स्तर को मजबूत किया है। इसके साथ ही बूथ स्तर पर काम किया जा रहा है। विधानसभा स्तर पर बीएलए नामित किए जा चुके है। इसके बाद बूथ कमेटी बनाई जाएगी। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष का कहना है कि कांग्रेस ने प्रदेश को चार जोन में बांटा है, जिसकी जिम्मेदारी प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल, हरक सिंह रावत और करण महरा को दी गई है। इसके साथ ही इन चारों जोनों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और हरीश रावत भी शामिल होंगे। कांग्रेस का सबसे बड़ा हथियार कार्यकर्ताओं को एकजुट करके, राज्य सरकार की विफलताओं पर हमला करने का है। कांग्रेस की एक बड़ी कमी भी है, कांग्रेस नेता भाषण या बयानों में तो सत्ता हासिल कर रहे हैं, लेकिन धारातल पर कितना जनाधार बचा है इसका अध्ययन नहीं कर रहे। जबकि भाजपा अपने विधायकों व मंत्रियों की उनके विधानसभा क्षेत्र में क्या स्थिति है इसका आंतरिक सर्वे तक करा चुकी है। इन्हीं सर्वे के आधार पर टिकट वितरण की व्यवस्था की जाती है। जिनका रिपोर्ट कार्ड संदिग्ध होता है उनका टिकट पक्का कटता है, जबकि कांग्रेस में ऐसा नहीं है। यदि प्रदेश कांग्रेस स्तर से टिकट नहीं मिलता है तो कांग्रेस नेता दिल्ली से टिकट ले आते हैं और फिर प्रदेश के पदाधिकारियों को उनकी हैसियत का अहसास कराते हैं।

एसआईआर का असर

उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में एसआईआर का असर भी देखने को मिलेगा। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के सीमांत जिलों के बहुत से परिवार यूपी और उत्तराखंड दोनों राज्यों के चुनावों में मतदान करते रहे हैं। इस बार ये संभव नहीं होगा। यानी नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून जैसे मैदानी जिलों में एसआईआर का असर साफ नजर आएगा। क्योंकि एसआईआर प्रक्रिया पूरी होने पर एक व्यक्ति का एक ही वोट रहेगा। कुछ घुसपैठियों के वोट भी मतदाता सूची से हटने वाले हैं। मैदानी जिलों में बांग्लादेशी और रोहिंग्या को कांग्रेस वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करती रही है। एसआईआर को लेकर कांग्रेस से ज्यादा भाजपा एक्टिव है। भाजपा ने कई महीने पहले ही नारा दे दिया था कि मेरा वोट मेरे गांव में। यानी प्रवासियों का आह्वान किया था कि वो रहे कहीं भी लेकिन मतदाता अपने मूल गांव के बने रहे। लिहाजा इस चुनाव में एसआईआर भी बड़ा फैक्टर हो सकता है।

नमो युग के 12 बरस

एनडीए के 12 वर्षों की एक सफलता ये है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है, कांग्रेस ने देश को लाचारगी, बेचारगी और हीन भावना की गर्त में गिरा दिया था। देश को यही एहसास कराया जाता था कि भारत में विकास धीरे-धीरे ही होता है, भारत में तेज विकास संभव ही नहीं है और बड़ी ही चतुराई से धीमे विकास को 'हिंदू ग्रोथ रेट' नाम देकर कांग्रेसी विफलता का कलंक देश की हिंदू आबादी पर लगा दिया।

शालिनी चौहान
नई दिल्ली

12 वर्षों में भारतीय राजनीति में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। ये वही देश है जब गैर भाजपाई सरकार के कार्यकाल में परियोजनाएं दशकों तक अटकी, लटकी और भटकी रहती थी, लेकिन 2014 के बाद सरकार के काम करने का तरीका बदला, सिस्टम वही है पर नेतृत्व बदलने से बड़ा परिवर्तन देखा जा रहा है। अब विकास के सिर्फ दावे नहीं होते, विकास फाइलों में नहीं होता बल्कि धरातल पर नजर आता है। इसलिए देश को मोदी पर भरोसा है। मोदी सरकार को 12 बरस हो गए फिर भी जनता का विश्वास मोदी पर बरकरार है। विश्वास का आलम ये है कि मिडिल इस्ट में युद्ध के कारण ऊर्जा संकट के मद्देनजर मोदी ने आह्वान किया कि हो सके तो डीजल पेट्रोल का खर्च कम करें, एक आह्वान पर मंत्री, नेता, जज और आम आदमी ने आरामदायक कार छोड़कर पब्लिक टांसपोर्ट का उपयोग किया, साइकिल और बाइक से चलना शुरू किया। जनता का यही भरोसा मोदी की ऊर्जा है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू का रिकार्ड तोड़ने पर जब एनडीए ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान किया तो मोदी ने खुद अपना 12 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को तरक्की के लिए प्रतिस्पर्धा का मूल मंत्र दे दिया। रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस को भी जबरदस्त तरीके से लपेटा। पीएम मोदी ने कहा कि एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है। कांग्रेस ने देश को लाचारगी, बेचारगी और हीन भावना की गर्त में गिरा दिया था। देश को यही एहसास कराया जाता था कि भारत में विकास धीरे-धीरे ही होता है, भारत में तेज विकास संभव ही नहीं है और बड़ी ही चतुराई से धीमे विकास को एक नाम दिया था, 'हिंदू ग्रोथ रेट' यानी कार्यशैली कांग्रेस की, दायित्व कांग्रेस का, विफलता कांग्रेस की लेकिन कलंक देश की बड़ी हिंदू आबादी के नाम लगाया गया। जबकि असल में इस कुसंस्कृति का नाम होना चाहिए था 'कांग्रेस ग्रोथ रेट।' 'कांग्रेस ग्रोथ रेट' की एक ही पहचान थी और वो थी शासन, नीति, नीयत और निर्णायक फैसले लेने में लाचारी। अटल विहारी वाजपेयी के नेतृत्व में ही एनडीए सरकार पहली बार सत्ता में आई, तभी हमें तेज विकास की झलक देखने को मिली, लेकिन दुर्भाग्य से 2004 में देश एक बार फिर अस्थिरता के भंवर और कांग्रेस की जकड़ में फंस गया और कांग्रेस ने देश को करोड़ों रुपये के घोटालों में धकेल दिया। 2014 में फिर एनडीए सरकार बनी, तो देश की किस्मत बदल गई। देश ने विकास की वो रफ्तार देखी जो तब आती है जब नीयत, नीति और फैसला लेने की प्रक्रिया एक साथ मिलकर काम करती हैं। देश ने देखा कि जिन कामों में दशकों लग जाते थे, वे कुछ ही महीनों में पूरे हो गए हैं।

140 करोड़ लोगों की उम्मीद पूरी करनी है

पीएम मोदी ने कॉन्केल्व को संबोधित करने से पहले देश की जनता को नमन किया। मोदी ने कहा मैं देश की महान जनता को नमन करता हूं। इतना लंबा कार्यकाल मिलना जनता की परिपक्वता का प्रतीक है। जनता-जनार्दन ही ईश्वर का रूप है। इतने लंबे समय तक भारत माता की सेवा करना, उनकी सेवा करने का सौभाग्य मिलना, केवल ईश्वर की विशेष कृपा से ही संभव है। इसलिए मैंने हमेशा इस सेवा को एक आध्यात्मिक साधना के रूप में देखा है। यह आध्यात्मिक साधना कभी भी अकेले नहीं रही। यह एक सामूहिक यज्ञ है, जिसमें आप सभी और कई अन्य सहयोगियों ने कर्तव्य की भावना के साथ अपनी सेवाएं दी हैं। कांग्रेस के विश्वासघात के बाद 2014 में देश के लोगों ने अपना भरोसा मुझे सौंपा था। मुझे आज गर्व है एनडीए परिवार के तौर पर हमने देश का विश्वास और मजबूत किया। देश के लोगों ने देखा है जब सही नीयत से सरकार चलती है तो देश विकास के पथ पर आगे बढ़ता है। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से निकलना ये बताता है कि हमारी नीतियां सही हैं। 2014 से पहले के दशकों में काफी अस्थिरता और उथल-पुथल रही, जिससे देश को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि अब लोग एक स्थिर सरकार का कामकाज देख रहे हैं और उसकी निर्णायक क्षमता की सराहना कर रहे हैं। आज मैं इस देश की महान जनता के सामने नतमस्तक होता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं। जब 2014 में एनडीए की जीत हुई थी, तो मैंने कहा था कि देश के आम नागरिक के लिए एक नई उम्मीद जगी है। इस उम्मीद को बनाए रखना और उसे आगे बढ़ाना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। पीएम मोदी ने कहा कि मेरा मानना है कि जो लोग कल तक गरीब थे और वो अब नया मध्यम वर्ग बन गए हैं, उन्हें हमें वापस पीछे नहीं जाने देना चाहिए। इसलिए एक सरकार और जन-प्रतिनिधि के तौर पर हमें दिन-रात काम करना होगा। 140 करोड़ लोगों के इस देश ने हम पर जो उम्मीदें जताई हैं, उन्हें पूरा करने के संकल्प के साथ हमने पूरी कोशिश की है। हमें भारत के युवाओं, महिलाओं, मध्यम वर्ग और किसानों की आकांक्षाओं को पूरा करना होगा।

2014 में एनडीए सरकार बनी, तो देश की किस्मत बदल गई, देश ने विकास की वो रफ्तार देखी जो तब आती है जब नीयत, नीति और फैसला लेने की प्रक्रिया एक साथ मिलकर काम करती हैं, देश ने देखा कि जिन कामों में दशकों लग जाते थे, वे कुछ ही महीनों में पूरे हो गए हैं।

- **पिछली सरकारें अनुच्छेद 370 पर चर्चा करने से बचती थीं, हमने अनुच्छेद 370 हटाया और पूरे देश में एक संविधान लागू किया, पहले पूर्वोत्तर भारत में हिंसा होती थी, लेकिन हमने शांति और स्थिरता बहाल की है, पहले भारत आतंकवादी हमले सहता था, अब आतंकवादियों के खिलाफ सर्जिकल और एयर स्ट्राइक होती है और ऑपरेशन सिंदूर से दुनिया भारत की ताकत देखती है।**
- **कांग्रेस के दौर की विकास दर और एनडीए के दौर की विकास दर के बीच का अंतर दिखाता है, कि एक सिस्टम लोगों को इंतजार कराता था, आज का सिस्टम नतीजे देता है, एक सिस्टम काम को रोकता और पटरी से उतारता था, आज का सिस्टम यह पक्का करता है कि काम समय पर और बड़े पैमाने पर हो, 2014 से 2026 तक की कहानी सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं है।**

कोविड-19 महामारी नहीं भूल सकते

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने देश की जरूरतों को अपनी नीतियों और फैसलों का आधार बनाया और नई पहल करने के लिए एक नई सोच अपनाई। युवाओं के लिए कौशल विकास मंत्रालय बनाया, सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए एक अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया। मछुआरों के लिए एक समर्पित मत्स्य पालन मंत्रालय बनाया। हमारा फोकस साफ था-विकास की इस दौड़ में कोई पीछे न छूटे। हमने दिव्यांगजनों के लिए कानून बनाए और आदिवासी समुदायों के लिए 'जनमन' जैसी योजनाएं शुरू कीं। पहले पशुपालकों और मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड का फायदा नहीं मिलता था, हमने उन्हें भी यह सुविधा दी। इसके अलावा हमारी सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स को 'स्वनिधि क्रेडिट कार्ड' की सुविधा दी। हम कोविड-19 महामारी के समय को कभी नहीं भूल सकते। जब हर तरफ अफरा-तफरी और परेशानी थी, तब भारत ने उस संकट का सामना करते हुए भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ना जारी रखा। यहां तक कि जब दुनिया भर के बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही हैं, भारत ने 2025-26 में 7.7 प्रतिशत की विकास दर हासिल की है। इसके अलावा 31 मार्च को खत्म हुई पिछली तिमाही में भारत की विकास दर 7.8 प्रतिशत रही है। पीएम मोदी ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए बताया कि 2014 में 74 एयरपोर्ट थे जो 2026 तक 160 से ज्यादा हो जाएंगे, 2014 में 1,000 किलोमीटर एक्सप्रेसवे थे जो 2026 तक 6,700 किलोमीटर हो जाएंगे। 2014 में सिर्फ पांच शहरों में मैट्रो सेवा थी जो 2026 तक 20 से ज्यादा शहरों में होगी। 2014 में रक्षा निर्यात सिर्फ 700 करोड़ रुपये था जो 2026 तक 23,000 करोड़ रुपये हो जाएगा। 2014 में देश में सिर्फ 25 करोड़ इंटरनेट यूजर्स थे, आज 100 करोड़ से ज्यादा यूजर्स इंटरनेट से जुड़े हैं। 2014 में डिजिटल पेमेंट न के बराबर थे, आज भारत डिजिटल ट्रांजैक्शन में दुनिया में पहले नंबर पर है। 2014 में भारत अपनी जरूरत के ज्यादातर मोबाइल फोन आयात करता था। आज भारत 330 मिलियन से ज्यादा मोबाइल हैंडसेट बनाता है। 2014 में सोलर क्षमता सिर्फ 2.5 गीगावाट थी, आज यह 150 गीगावाट से ज्यादा है। 2014 में इथेनॉल ब्लेंडिंग सिर्फ 1.5 प्रतिशत थी, जबकि आज यह 20 प्रतिशत तक पहुंच गई है। 2014 में देश में एक भी सेमीकंडक्टर यूनिट नहीं थी, आज 10 से ज्यादा सेमीकंडक्टर यूनिट बन रही हैं। आज देश का हर नागरिक 'विकसित भारत' के सपने से प्रेरित है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति, सरकार या राजनीतिक दल तक सीमित नहीं है, यह देश के हर व्यक्ति का सपना और संकल्प बन गया है। हमें इस सपने को पूरा करने के लिए अपना हर पल समर्पित करना होगा।

एनडीए के लिए राष्ट्र प्रथम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना था कि अगर 12 साल में इतना कुछ हासिल किया जा सकता था, तो पिछले दशकों में ऐसा क्यों नहीं हुआ? यह कांग्रेस के दौर की विकास दर और एनडीए के दौर की विकास दर के बीच का अंतर दिखाता है। एक सिस्टम लोगों को इंतजार कराता था, आज का सिस्टम नतीजे देता है। एक सिस्टम काम को रोकता और पटरी से उतारता था, आज का सिस्टम यह पक्का करता है कि काम समय पर और बड़े पैमाने पर हो। 2014 से 2026 तक की कहानी सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं है। यह उस भारत की कहानी है जो पहली बार अपनी पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ने लगा है, एक ऐसा भारत जो बड़े लक्ष्य तय करता है और उन्हें हासिल करने के लिए बिना थके काम करता है। इसलिए देश किसी भी राजनीतिक दल से बड़ा है और जब हम 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं, तो कोई भी फैसला मुश्किल नहीं होता। हमने ऐसे फैसलों पर साहसी और सोच-समझकर कदम उठाए हैं जिन्हें कभी असंभव माना जाता था, लेकिन जो देश के सुरक्षित भविष्य के लिए जरूरी थे। पिछली सरकारें अनुच्छेद 370 पर चर्चा करने से भी हिचकिचाती थीं। हमने अनुच्छेद 370 को हटाया और पूरे देश में एक समान रूप से संविधान लागू किया। पहले पूर्वोत्तर भारत में हिंसा का बोलबाला था, लेकिन हमने उस क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल की है। पहले भारत चुपचाप आतंकवादी हमले सहता रहता था। अब हमने आतंकवादियों के खिलाफ सर्जिकल और एयर स्ट्राइक करके जवाब दिया है और दुनिया को भारत के संकल्प और ताकत का परिचय ऑपरेशन सिंदूर से दिया।

मोदी सरकार ने 12 साल पूरे होने पर खेती किसानी से जुड़ा अपना रिपोर्ट कार्ड भी जारी किया। इस रिपोर्ट कार्ड में 2014 से 2026 के बीच देश का खाद्यान्न उत्पादन 357.73 मिलियन टन तक पहुंच गया है और पीएम-किसान निधि जैसी योजनाओं से किसानों को बड़ी आर्थिक सुरक्षा मिली है। रिपोर्ट के अनसुार पिछले 12 वर्षों में भारत के कृषि क्षेत्र और किसानों के सशक्तिकरण में व्यापक सुधार हुआ है। सरकार का कहना है कि अब कृषि नीतियों का ध्यान केवल बुनियादी मदद देने से आगे बढ़कर किसानों की उत्पादकता बढ़ाने, बाजार तक उनकी पहुंच आसान करने, आय को सुरक्षित करने और नई तकनीक जोड़ने पर है। सिंचाई सुविधा, कर्ज की आसान पहुंच, मजबूत फसल बीमा और एमएसपी पर खरीद बढ़ने से देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बना हुआ है। देश में दूध का उत्पादन 2014-15 के 146.31 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में 247.87 मिलियन टन हो गया है। इसी अवधि में मछली उत्पादन 9.58 मिलियन टन से बढ़कर 19.78 मिलियन टन हो गया। इन सभी सुधारों और कृषि उत्पादकता में वृद्धि के कारण भारत का कृषि निर्यात भी तेजी से बढ़ा है। आंकड़े बताते हैं कि 2013-14 में 37.29 बिलियन डॉलर का कृषि निर्यात था, जो 2024-25 में बढ़कर 51.1 बिलियन डॉलर हो गया है, जिससे विश्व बाजार में भारतीय कृषि की मजबूत पहचान बनी है। ●

विपक्षी सियासत दांव पर

जनगणना अभियान में प्रशासनिक सिस्टम को घर-घर जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन करना है, यह देश के सबसे बड़े प्रशासनिक अभियान में से एक है लिहाजा जनगणना विभाग ने चुनाव आयोग को बता दिया है कि फरवरी-मार्च में उनकी पूरी मशीनरी जनगणना के काम में व्यस्त रहेगी, इसलिए नवंबर-दिसंबर में विधानसभा चुनाव कराने के कयास लगाए जा रहे हैं।

डा.वीरेंद्र पुष्पक
वरिष्ठ पत्रकार

उत्तर प्रदेश में समय से पहले विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। क्योंकि जनगणना विभाग की तरफ से निर्वाचन आयोग को बता दिया गया है कि फरवरी और मार्च में देश भर में राष्ट्रीय जनगणना का काम तेजी से किया जाना है। लिहाजा इसी साल नवंबर-दिसंबर में विधानसभा चुनाव कराए जाने के कयास लगाए जाने लगे हैं। दरअसल जनगणना अभियान के तहत प्रशासनिक अमले को घर-घर जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन करना है। ये देश के सबसे बड़े प्रशासनिक अभियान में से एक है। ऐसे में जनगणना विभाग ने चुनाव आयोग को आगाह किया है कि फरवरी-मार्च के दौरान उनकी पूरी मशीनरी जनगणना के काम में व्यस्त रहेगी। प्रशासनिक सिस्टम के लिए एक ही समय में देश की जनगणना करना और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में विधानसभा चुनाव कराना लगभग असंभव होगा। चुनाव आयोग के पास सूबे में चुनाव को तय समय से आगे टालने का विकल्प नहीं है, क्योंकि ऐसा करने पर उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ सकता है। चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने के 6 महीने पहले कभी भी चुनाव कराए जा सकते हैं। इसके लिए संसद से किसी विशेष मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती। यही वजह है कि फरवरी-मार्च की बजाय चुनाव समय से पहले नवंबर-दिसंबर में कराने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। उत्तराखंड में समय से पहले चुनाव इसलिए भी हो सकते हैं क्योंकि अगले साल हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन होना है। कुंभ मेला की सुरक्षा और व्यवस्था में प्रशासनिक अमला लगेगा तो चुनाव कराना मुश्किल होगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपनी पार्टी मीटिंग में नेताओं और कार्यकर्ताओं से साफ कह चुके हैं कि सरकार समय से पहले चुनाव करा सकती है। भाजपा के भीतर भी इस बात की चर्चा चल रही है कि समय से पहले अगर चुनाव हो तो उसकी तैयारी रखनी चाहिए। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन यह चर्चा पॉलिटिकल पार्टियों में खासकर भाजपा और समाजवादी पार्टी के भीतर तेजी से हो रही है। ऐसे में अगले साल देश के पांच राज्यों में चुनाव है और अगर चुनाव समय से पहले हुए तो सभी राज्यों में एक साथ होंगे अकेले उत्तर प्रदेश नहीं, लेकिन चर्चा फिलहाल उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हो रही है। राजनीति के जानकार मान रहे हैं कि जनगणना का काम दो महीने आगे बढ़ाया जा सकता है।

अखिलेश का करियर दांव पर

विधानसभा चुनाव करीब हैं लिहाजा उत्तर प्रदेश की राजनीति में बदलते घटनाक्रमों ने सियासी माहौल को पूरी तरह बदल दिया है। ताजा राजनीतिक घटनाओं के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने पुराने मुद्दों को नए संदर्भ में जनता के सामने रखने का अवसर मिल गया है। टीवी न्यूज चैनल के एक कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह, इलेक्शन एक्सपर्ट मनोज कुमार सिंह और सेफोलॉजिस्ट अमिताभ तिवारी ने विधानसभा चुनाव को लेकर खुलकर चर्चा की। समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक कमाल अख्तर के इस्तीफे पर पेनलिस्ट की राय थी कि इस घटनाक्रम से समाजवादी पार्टी की आतंरिक कलह सामने आई है। क्योंकि कमाल अख्तर यूपी के मुरादाबाद जिले के कांठ विधानसभा क्षेत्र से सपा विधायक हैं और मुरादाबाद लोकसभा सीट से रुचिवीरा सपा की सांसद हैं। दोनों के बीच छत्तीस का आकंड़ा है। रुचिवीरा की शिकायत पर ही कमाल अख्तर से मुख्य सचेतक का पद छोड़ने के लिए कहा गया था। एक्सपर्ट इसे केवल एक संगठनात्मक बदलाव नहीं, बल्कि पार्टी के भीतर बढ़ती बेचैनी का संकेत बता रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है किबदलते राजनीतिक समीकरणों और विधानसभा चुनावों की तैयारी के बीच समाजवादी पार्टी के अंदर कई स्तरों पर असंतोष दिखाई दे रहा है। इसलिए मतदाताओं का मिजाज भी बदल रहा है। एक्सपर्ट की चर्चा के बीच यह बात प्रमुखता से सामने आई कि पहले जिन सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों को विपक्ष अपनी सबसे बड़ी ताकत मानता था, अब उनमें बदलाव दिखाई दे रहा है। मतदाता अब पहले की तुलना में अधिक राजनीतिक सोच के साथ फैसले ले रहा है। यही वजह है कि कई पारंपरिक वोट बैंक यानी सपा का यादव और मुस्लिम वोट भी भविष्य को ध्यान में रखकर अपने विकल्पों पर विचार कर रहा हैं। राजनीति का पोस्टमार्टम करने वाले कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने 2022 में विधानसभा चुनाव लड़ा और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर सरकार को लगातार घेरने का काम किया, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में वो सांसद चुने गए और यूपी छोड़कर दिल्ली चले गए। उनकी गैरमौजूदगी में योगी आदित्यनाथ को सुरक्षित पिच मिल गई। जिस पर वो खुलकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। यदि अखिलेश यूपी विधानसभा में रहते तो हो सकता है कि योगी को खुला मैदान न मिलता। इसे अखिलेश यादव की कमजोरी माना जा रहा है। समाजवादी पार्टी की टेंशन कांग्रेस भी बढ़ा रही है, कांग्रेस के यूपी प्रभारी ने कांग्रेस को सपा का बड़ा भाई बताते हुए दावा किया कि बड़ा भाई यूपी की आधी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। यानी कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से आधी सीटें मांग ली है। वैसे सपा के लिए आगामी विधानसभा चुनाव करो या मरो का है, यदि इस बार सपा की चुनावी हार हुई तो फिर अखिलेश यादव को पार्टी चलाना भी मुश्किल हो सकता है। अखिलेश का राजनीतिक करियर भी संकट में पड़ सकता है।

विपक्षी दल और उसके नेता चुनावी साल में ही नजर आते हैं, चुनाव सिर पर आने पर विपक्षी दलों के नेता अपने सोये हुए कार्यकर्ताओं को जगाने का काम करते हैं, लेकिन भाजपा में ऐसा नहीं है, भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को हर समय एक्टिव रखती है, कार्यकर्ताओं और नेताओं को एक्टिव रखने के लिए ही कोई न कोई अभियान भाजपा चलाती रहती है।

चढ़ावा चोरी का पासा उल्टा पड़ा

वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह का मानना है कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष खासकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव सबसे ज्यादा मुखर है, लेकिन हिंदुओं को उनका सनातनी ढोंग समझ में आ रहा है। क्योंकि सपा मुखिया अखिलेश यादव हों या कांग्रेस नेता सोनिया गांधी अथवा राहुल गांधी इन सभी को अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा का न्योता दिया गया था, लेकिन इनमें से एक भी नेता अयोध्या नहीं पहुंचा बल्कि इसे भाजपा का कार्यक्रम बताकर बहिष्कार किया। अब यही नेता सबसे ज्याजा श्रीराम मंदिर चढ़ावा चोरी पर छाती पीट रहे है। श्रीराम मंदिर का चढ़ावा चोरी का मुद्दा सबसे पहले सपा मुखिया अखिलेश यादव ने ही उठाया था, लेकिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो एक्शन लिया उससे पासा पलट गया। वैसे भी विपक्ष की विश्वसनीयता संदिग्ध हो चुकी है। इसलिए हिंदु अब बिखरना नहीं चाहता। विपक्ष के राम मंदिर का मुद्दा उठाने से हिंदु की चेतना और जागी है। टीवी के ही एक कार्यक्रम में विपक्ष के प्रवक्ता ने जब राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया तो भीड़ के बीच से एक राम भक्त आगे आया और बोला कि हमने श्रीराम मंदिर में दान दिया है, हम दान देकर भूल गए हैं। जो लोग छाती पीट रहे हैं उनमें से न तो कोई अयोध्या में रामलला के दर्शन करने गया है और न ही श्रीराम मंदिर के लिए फूटी कोड़ी दी है। जिन लोगों ने भी राम के कोष से चोरी की है उसे कानून सजा दे या न दे लेकिन श्रीराम उन्हें ऐसी सजा देंगे कि चोरी करने वालों की जिंदगी नरक हो जाएगी। कुल मिलाकर जनता यह देख रही है कि योगी सरकार कार्रवाई कर रही है लिहाजा योगी आदित्यनाथ की छवि पहले से और मजबूत हो रही है। इसलिए योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में हैट्रिक लगाने से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस रोक पाए ऐसे तो आसार नहीं हैं।

जिन्होंने राम के घर में चोरी की है उसे कानून सजा दे या न दे, पर श्रीराम उन्हें ऐसी सजा देंगे कि चोरों की जिंदगी नरक हो जाएगी, वैसे जनता देख रही है कि योगी सरकार कार्रवाई कर रही है लिहाजा योगी आदित्यनाथ की छवि पहले से और मजबूत हो रही है, इसलिए योगी आदित्यनाथ को यूपी में हैट्रिक लगाने से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस रोक पाए ऐसे तो आसार नहीं हैं।

योगी की अखिलेश को चुनौती

अखिलेश यादव अयोध्या के चढ़ावा कांड को सत्ता की सीढ़ी बनाना चाहते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को चुनौती दे दी कि वो चुनावी साल में बड़े धार्मिक बन रहे हैं, तिलक लगाकर घर से निकल रहे हैं। खुद को खुद ही सनातनी होने का सर्टिफिकेट दे रहें हैं। योगी ने चुनौती दी कि अगर वो सनातनी है, हिंदू हैं तो खुलकर मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर बोलें। श्रीकृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए आंदोलन करें। योगी ने कहा कि मैं जानता हूं कि अखिलेश यादव श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे पर नहीं बोलेंगे क्योंकि इससे उनका मुस्लिम वोट बैंक छिटक जाएगा। अखिलेश यादव सिर्फ मुल्ला और मौलवियों के सामने घुटने टेकते हैं। इसलिए माना जा रहा है कि योगी की चुनौती ने सपा को बैकफुट पर धकेल दिया है। योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व और धार्मिक आस्था से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाते रहे हैं। वहीं विपक्ष के सामने एक चुनौती यह भी है कि धार्मिक या श्रीराम मंदिर पर बोलते समय उन्हें अपने पुराने बयानों और राजनीतिक रुख का भी सामना करना पड़ रहा है। कई विपक्षी दल तो राम मंदिर जैसे संवेदनशील मुद्दे पर खुलकर आक्रामक रुख अपनाने से भी बच रहे हैं, क्योंकि उन्हें इसके राजनीतिक नुकसान का अंदाज है। योगी आदित्यनाथ खुलकर हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं, साथ ही दावा करते हैं कि सरकारी योजनाओं का लाभ देते समय उनकी सरकार ये नहीं देखती कि कौन हिंदू है और कौन मुसलमान है। बिना किसी भेदभाव के सरकारी योजनाओं का लाभ हर वर्ग, समाज और संप्रदाय के पात्र व्यक्ति तक पहुंचता है। इसलिए लाभार्थी मुस्लिम महिलाओ का रूझान भाजपा में बढ़ा है। शिक्षित मुस्लिम युवा भाजपा और योगी के काम से संतुष्ट लगते है। क्योंकि मुस्लिम भी जानते हैं कि सपा के शासन में सरकारी योजनाओं का लाभ परिवार, संप्रदाय, और जाति देखकर दिया जाता था। भाजपा यदि हिंदुओं की बात करती है तो करे, करनी भी चाहिए, लेकिन वो सपा की तरह भ्रम नहीं फैलाती। कानून व्यवस्था को लेकर भले ही सपा और कांग्रेस योगी सरकार को घेरती रहे, लेकिन जिस तरह की कानून व्यवस्था यूपी में है उसे अंदरखाने विपक्षी भी बड़ा बदलाव मानते हैं। इसलिए विधानसभा चुनावों को लेकर अनुमान लगाया जा रहा कि इस बार राजनीतिक दलों की ताकत ही नहीं, बल्कि उनके नेतृत्व की स्वीकार्यता और जनता के विश्वास की भी परीक्षा होगी यदि विपक्ष अपने संगठन और रणनीति को समय रहते मजबूत नहीं कर पाया, तो उसके सामने नई चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। वहीं सीएम योगी के लिए अयोध्या का घटनाक्रम राजनीतिक रूप से एक नए अवसर के रूप में देखा जा रहा है। क्योंकि विपक्षी दल और उसके नेता व कार्यकर्ता चुनावी साल में ही नजर आते हैं। चुनाव सिर पर आने पर विपक्षी दलों के नेता अपने सोये हुए कार्यकर्ताओं को जगाने का काम करते हैं, लेकिन भाजपा में ऐसा नहीं है। भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को हर समय एक्टिव रखती है। कार्यकर्ताओं और नेताओं को एक्टिव रखने के लिए ही कोई न कोई अभियान भाजपा चलाती रहती है। भाजपा अपने कार्यकर्ताओं व नेताओं को किसी न किसी बहाने जनता के बीच जाने और जनसंवाद करने का अवसर देती है। अभियान चलाकर न सिर्फ सरकारी योजनाओं को पात्रों तक पहुंचाने का काम करती है बल्कि लाभार्थियों की नब्ज भी टटोलती है। इसी बहाने अपने सांसदों व विधायकों की जनता के बीच कैसी छवि है इसका भी पता लगा लेती है। यही भाजपा की जीत का आधार बनता है। जबकि विपक्षी दल के नेता और कार्यकर्ता चुनावी सीजन में जागते हैं और चुनाव होने के बाद फिर सो जाते हैं।

धरोहर

अल्मोड़ा में पाषाण जीवन के प्रमाण

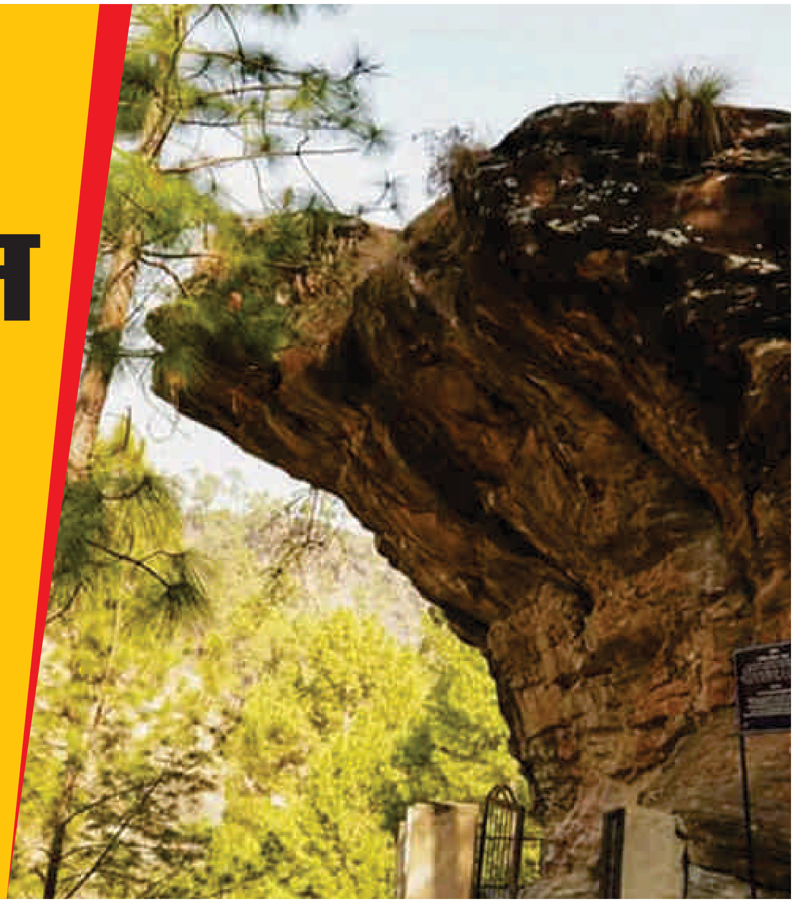

नवपाषाण यानी नियोलिथिक युग, काल, अवधि, या नव पाषाण युग मानव प्रौद्योगिकी के विकास की एक अवधि थी जिसकी शुरुआत मध्य पूर्व में 9500 ईपू के आसपास हुई थी, जिसे पारंपरिक रूप से पाषाण युग का अंतिम हिस्सा माना जाता है, अल्मोड़ा जिले में हुई खोज से साबित होता है कि प्रागैतिहासिक काल में भी हिमालय की गोद में मानव जीवन था और सामूहिक गतिविधियां होती रही हैं।

कमल कपूर
अल्मोड़ा

देवभूमि उत्तराखंड न सिर्फ खूबसूरती के लिए मशहूर है बल्कि यहां की हरी-भरी घाटियां, झरने, झीलें, जंगल, वन्यजीव, पशु-पक्षी और प्राचीन धार्मिक स्थलों के साथ रहस्यमयी गुफाएं पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। इस पहाड़ी राज्य का ऐतिहासिक अल्मोड़ा जिला अपने रहस्यों के लिए जाना जाता है। हिमालय की गोद में बसे अल्मोड़ा जिले में 4000 साल पहले भी मानव रहते थे, यहां हुई खोज से इसके पुख्ता प्रमाण मिले हैं। पिछले साल यानी 2025 में अल्मोड़ा जिला मुख्यालय से 22 किलोमीटर दूर हवालबाग ब्लॉक के ध्यूलीकोट गांव में पुरातत्वकाल की दो महत्वपूर्ण खोज हुई हैं। यानी ध्यूलीकोट गांव से करीब डेढ़ किलोमीटर टापूनुमा पहाड़ी पर प्रागैतिहासिक काल का एक शैलाश्रय मिला है। तो वहीं कड़की उडियार शैलाश्रय में गुफा मिली है, जो पुरातत्वविदों के अनुसार नवपाषाण से ताम्रपाषाण युग (4000-2000 ईसा पूर्व) के हो सकते हैं। शैलाश्रय का अर्थ किसी प्राकृतिक चट्टान या पत्थर के फैलाव से बनी उस खुली गुफा या छज्जे से है, जिसका उपयोग प्रागैतिहासिक काल में आदिमानव अपने रहने या शरण लेने के लिए किया करते थे। ताम्रपाषाण काल का नवपाषाण युग और कांस्य युग के बीच का संक्रमणकालीन दौर था। लगभग 2000 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व तक फैले इस काल की सबसे बड़ी विशेषता पत्थर के औजारों के साथ तांबे के रूप में खोजी गई पहली धातु का उपयोग था। नवपाषाण यानी नियोलिथिक युग, काल, या अवधि, या नव पाषाण युग मानव प्रौद्योगिकी के विकास की एक अवधि थी जिसकी शुरुआत मध्य पूर्व में 9500 ईपू के आसपास हुई थी, जिसे पारंपरिक रूप से पाषाण युग का अंतिम हिस्सा माना जाता है। ये खोज साबित करती है कि प्रागैतिहासिक काल में भी हिमालय की गोद में मानव जीवन था और सामूहिक गतिविधियां होती रही हैं।

10 मीटर ऊंची गुफा

ध्यूलीकोट से करीब डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर मिलने वाली यह गुफा (शैलाश्रय) लगभग 3 मीटर चौड़ी और चार मीटर गहरी है। जबकि इसके ऊपर छतनुमा पत्थर करीब 10 मीटर ऊंचा है। इसमें एक साथ 10 लोग खड़े हो सकते हैं और 15-20 लोग बैठ सकते हैं। इसकी खासियत यह है कि इसमें (उड़ियार) प्राकृतिक छेद भी है, जिसमें से हवा और प्रकाश आसानी से गुफा में जा सकता है। ध्यूलीकोट के शैलाश्रय की एक और खासियत यह है कि इसमें पत्थर से बनी तीन पारंपरिक ओखलियां भी पाई गई हैं। इनकी गहराई 14-15 सेंटीमीटर और चौड़ाई 12-14 सेंटीमीटर हैं। पुरातत्वविदों का अनुमान है कि इस जगह प्राचीनकाल में काफी लोग समूह में रहते होंगे। इस खोज के बाद पुरातत्व विभाग की टीम ने इस जगह के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व का अध्ययन शुरू किया है। ऐतिहासिक अल्मोड़ा जिले में ही लखुडियार के साथ कई स्थानों पर पेटशाल, फड़कानौला, कसार देवी, ल्वेथाप, महरुउड्यार, फलसीमा आदि में प्रागैतिहासिक शैलाश्रय (गुफाएं) मिल चुके हैं। अब ध्यूलीकोट में शैलाश्रय मिलने से पुरातत्वविद भी उत्साहित हैं। ध्यूलीकोट का यह शैलाश्रय टापूनुमा ऊंची पहाड़ी पर होने की वजह के साथ सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। यहां से अल्मोड़ा, लोधिया और रैनडाल जैसे क्षेत्र की निगरानी आसानी से की जा सकती है। ध्यूलीकोट के करीब गुफा मिलने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो सोशल मीडिया यूजर ने कमेंट में लिखा कि वीडियो में जो पुरातात्विक खोज दिखाई गई हैं, वो वाकई में अद्भुत है 4000 साल पुरानी गुफाओं से पता चलता है कि हमारे पूर्वज कितने बुद्धिमान थे। ध्यूलीकोट का ये शैलाश्रय तो पर्यटन के लिए भी एक बेहतरीन जगह बन सकता है। इस तरह की खोजें हमारे इतिहास को जानने का एक नया रास्ता खोलती हैं। क्या आपको लगता है कि उत्तराखंड में ऐसी और भी जगह मिल सकती हैं। एक अन्य यूजर ने कमेंट किया कि ये खोज ना केवल ऐतिहासिक है, बल्कि पर्यटन के लिए भी बहुत अच्छी है।

आदिमानवों द्वारा गेरुआ, काले और सफेद रंग से गुफाओं में शैलचित्र बनाए गए हैं, ये शैल चित्र अब धीरे-धीरे गायब हो रहे हैं, इनके मिटने की वजह धूप और बारिश तो है ही, इसके अलावा लोगों ने इन चट्टानों पर अपना नाम लिखकर भी इन्हें मिटाने की खूब कोशिश की हैं।

पर्यटन की संभावनाएं

देवभूमि उत्तराखंड अपने पुरातत्व और पाषाण काल समेत ऐतिहासिक काल को समेटे हुए हैं इसलिए यहां बहुत सारी प्राचीन गुफाएं मिल चुकी है। जो लोगों को इतिहास के साथ प्राचीन सभ्यता से रू-ब-रू कराती हैं। पिछले साल हुई खोज इतिहास प्रेमियों के लिए महत्वपूर्ण तो है ही, साथ ही पर्यटन की दृष्टि से भी यह आकर्षण का केंद्र बन सकती है। यदि सरकार इस क्षेत्र को पर्यटन से जोड़ती है तो स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि ध्यूलीकोट जैसे शांत वातावरण में प्राचीनकाल की ये निशानियां पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र ही नहीं बनेंगा बल्कि हिमालयी क्षेत्र की पाषाण कालीन संस्कृति को समझने का अवसर भी मिलेगा। यहां की हरी भरी वादियों में इन पुरातत्विक स्थलों की सैर के साथ पर्यटक ट्रेकिंग जैसे एडवेंचर का भी आनंद ले सकेंगे। इतिहासकारों का मानना है कि इस खोज से अल्मोड़ा क्षेत्र को न सिर्फ शोध की दृष्टि से नई पहचान मिली है, बल्कि देश दुनिया के शोधकर्ताओं के लिए यह अमूल्य धरोहर से कम नहीं है।

इंसान के अतीत का सबूत

उत्तराखंड के अल्मोड़ा की लखुडिया गुफाएं इंसान के अतीत का जीता-जागता सबूत है। इतिहास के जानकारों के मुताबिक ये गुफाएं प्रागैतिहासिक काल की हैं, जहां बड़ी संख्या में शैल चित्र हैं। आदिमानवों द्वारा गेरुआ, काले और सफेद रंग से गुफाओं में शैलचित्र बनाए होंगे। ये शैल चित्र अब धीरे-धीरे गायब हो रहे हैं। इनके मिटने की वजह धूप और बारिश तो है ही, इसके अलावा लोगों ने इन चट्टानों पर अपना नाम लिखकर भी इन्हें मिटाने की खूब कोशिशें की हैं। पर्यटक इन गुफाओं में बने शैल चित्रों को देखने जरूर पहुंचते हैं। स्थानीय लोग व पर्यटक मानते हैं कि इस जगह को संरक्षित किए जाने की जरूरत है। बाड़ेछीना क्षेत्र में लखुड़ियार गुफाएं उत्तराखंड की सबसे महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक धरोहरों में से एक हैं। लखुड़ियार का अर्थ है एक लाख गुफाएं, जो इनके विस्तार और विशालता का प्रतीक है। माना जाता है कि ये गुफाएं प्रारंभिक मानवों का आश्रय स्थल थीं, जहां वे प्रकृति के बीच सुरक्षित रहते थे। ये गुफाएं सुयाल नदी के किनारे ऊंची चट्टानों पर हैं, जिससे यह स्थान प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक महत्व दोनों से भरपूर है। नदी किनारे की यह भौगोलिक स्थिति इस बात का संकेत देती है कि पाषाणकाल में लोग पानी और संसाधनों के पास रहना पसंद करते थे। लखुड़ियार गुफाएं अपनी शैल-कला के लिए दुनियाभर में जानी जाती हैं। गुफाओं की दीवारों पर उकेरी गई मानव आकृतियां, जानवरों की छवियां और ज्यामितीय पैटर्न उस समय की सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को समझने में मदद करते हैं। यहां की कला मुख्य रूप से काले, लाल और सफेद रंगों में दिखाई देती है। इन गुफाओं में सबसे आकर्षक दृश्य मानव आकृतियों का सामूहिक नृत्य है, जिसमें एक तरफ 34 और दूसरी तरफ 28 आकृतियां दिखाई देती हैं। ये चित्र इस बात का संकेत देते हैं कि प्रारंभिक मानव केवल शिकार और जीवनयापन तक सीमित नहीं थे, बल्कि उत्सव, नृत्य और सामुदायिक गतिविधियों में भी सक्रिय भाग लेते थे। गुफाओं में विभिन्न पशुओं जैसे लोमड़ी, छिपकली और अज्ञात वन्य प्रजातियों की आकृतियां भी देखी जा सकती हैं। इसके अलावा कुछ चित्र प्रारंभिक हथियारों को दर्शाते हैं, जिससे उस समय के शिकार-कौशल और जीवनशैली का अंदाजा लगाया जा सकता है। लिहाजा लखुड़ियार गुफाएं आज भी पुरातत्वविदों के लिए शोध का महत्वपूर्ण केंद्र हैं।

आदिकाल का अनोखा अनुभव

कई अध्ययनों के अनुसार यहां के चित्र लगभग 6000 वर्ष पुराने होने का अनुमान है। अध्ययन से यह भी अनुमान लगाया गया है कि मानव प्राचीन काल से ही अपने विचारों को चित्रकारी, संगीत, साहित्य तथा नृत्य इत्यादि माध्यमों से अभिव्यक्त करता रहा है आदिमानव काल में भी आदिवासियों के द्वारा अपने विचारों को व्यक्त किया गया होगा, लखुडियार गुफा उसी का ही एक उदाहरण है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और अन्य संस्थान इस स्थल पर विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं, ताकि हिमालयी सभ्यता के प्राचीन इतिहास को बेहतर ढंग से समझा जा सके। अल्मोड़ा से लगभग 19 किलोमीटर दूर स्थित यह स्थल आज एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी बन चुका है। शांत वातावरण, प्राकृतिक सुंदरता और सदियों पुराना इतिहास इसे यात्रियों, विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं और फोटोग्राफरों के लिए अनोखा अनुभव बनाते हैं। लखुडियार गुफाएं कुमाऊं की सांस्कृतिक विरासत और मानव सभ्यता के विकास की एक अमूल्य धरोहर है। यदि आपने कभी आदिमानव काल की कोई चीज नहीं देखी है, तो अल्मोड़ा स्थित लखुडियार गुफाएं आपकी यात्रा के लिए बेस्ट है। यहां सुयाल नदी के किनारे शेराघाट मार्ग पर अल्मोड़ा से 14 किलोमिटर दूर दिंगोली गांव में इसकी खोज वर्ष 1963 में हुई थी। यहां लगभग 6000 साल पुरानी प्राचीन शैल-कला मानव इतिहास और संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। यानी आदिकाल का एक अनोखा अनुभव मिलेगा।

- **ऐतिहासिक अल्मोड़ा जिले में ही लखुडियार के साथ कई स्थानों पर पेटशाल, फड़कानौला, कसार देवी, ल्वेथाप, महरुउड्यार, फलसीमा आदि में प्रागैतिहासिक शैलाश्रय (गुफाएं) मिल चुके हैं, अब ध्यूलीकोट में शैलाश्रय मिलने से पुरातत्वविद उत्साहित हैं, ध्यूलीकोट का यह शैलाश्रय टापूनुमा ऊंची पहाड़ी पर होने की वजह के साथ सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना गया है।**
- **वशेषज्ञों का मानना है कि ध्यूलीकोट जैसे शांत वातावरण में प्राचीनकाल की ये निशानियां पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र ही नहीं बनेंगा बल्कि हिमालयी क्षेत्र की पाषाण कालीन संस्कृति को समझने का अवसर भी मिलेगा, यहां की हरी भरी वादियों में इन पुरातत्विक स्थलों की सैर के साथ पर्यटक ट्रेकिंग जैसे एडवेंचर का भी आनंद ले सकेंगे।**

पुनर्वास की चुनौती

उत्तराखंड में 465 गांव ऐसे हैं, जिन्हें संवेदनशील माना गया है, इन गांवों को कहीं और बसाया जाना है, परंतु कहां यह ऐसा सवाल है अनसुलझा है, उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा से प्रभावितों के लिए 2011 में पुनर्वास नीति लागू की गई, जिसमें 2017 में संशोधन किया गया, फिर 31 दिसंबर 2021 को संशोधन करते हुए कहा गया है कि पुनर्वास के लिए जमीन का चयन प्रभावित क्षेत्र के निकट सुरक्षित एवं उसी जनपद में होना चाहिए।

डॉ.हरीश चंद्र अंडोला
दून यूनिवर्सिटी

मानसून का सीजन आ गया है, हर साल जून में मानसून दस्तक दे देता है। ये वो सीजन है जो उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को डराता है। क्योंकि ये वही सीजन है जब बादल फटते हैं, पहाड़ दरकते हैं, भूस्खलन होता है, सड़के बंद हो जाती है, पुल और पुलिया बाढ़ में बह जाती हैं, बिजली पानी का संकट पैदा हो जाता है, ज्यादातर गांवों का संपर्क आपस में टूट जाता है और पहाड़ की जिंदगी ठहर सी जाती है। मानसून का इकलौता सीजन है जब चारों तरफ पानी ही पानी होता है, लेकिन प्यास बुझाने के लिए पानी नसीब नहीं होता। पहाड़ों पर बिजली की लाइन हो या पानी की लाइन सब तहस नहस हो जाती हैं। पहाड़ का जीवन पहाड़ जैसे कठोर नजर आने लगता है। 2025 की बात करें तो उत्तराखंड एक नहीं अनेक अग्नि परीक्षाओं से गुजरा। पूरे साल प्रकृति ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि पहाड़ से लेकर मैदान तक जनजीवन अस्त-व्यस्त रहा। कहीं बादल फटे, कहीं हिमस्खलन हुआ तो कहीं मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। इन आपदाओं ने न सिर्फ जिंदगियां छीनीं बल्कि वन्यजीवों के साथ पालतू पशुओं की जान भी आफत में डाल दी थी। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 2025 में अलग-अलग आपदाओं से हुए नुकसान का आकलन पीडीएनए यानी पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट से कराया था। जिसकी रिपोर्ट में दावा किया गया था कि उत्तराखंड में आपदाओं से 15,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। आपदा से हुए नुकसान में प्रत्यक्ष क्षति की बात करें तो 3,792.38 करोड़ रुपये की थी। इसमें से 312.19 करोड़ रुपये की अप्रत्यक्ष क्षति हुई है, जिसे नुकसान में गिना गया है। इसके अलावा नुकसान की भरपाई, व्यवस्थाएं पटरी पर लाने और बेहतर पुनर्वास पुनर्निर्माण के लिए 10,998.95 करोड़ रुपये की जरूरत रिपोर्ट में बताई गई थी। 2025 में उत्तराखंड में आई आपदाओं के सोशल इंपैक्ट को 4,966.85 करोड़ रुपये की क्षति पहुंची। जिससे प्रदेश की सोशल इकोनॉमी प्रभावित हुई। आपदाओं के कारण हाउसिंग, एजुकेशन और हेल्थ पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। सिर्फ हेल्थ सेक्टर को 2,579.47 करोड़ रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ। जबकि, हाउसिंग सेक्टर का यह नुकसान 2,005.84 करोड़ रुपये रहा।

हर साल होती है तबाही

पिछले साल की शुरुआत में ही 28 फरवरी को चमोली जिले के माणा कैंप के पास भारी हिमस्खलन हुआ। बर्फ के इस सैलाब में सीमा सड़क संगठन के 55 मजदूर दब गए, जिनमें से आठ लोगों की जान चली गई थी। इस हादसे ने एक बार फिर सीमावर्ती इलाकों में काम कर रहे मजदूरों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए थे। इसके बाद मानसून आया तो अगस्त में उत्तरकाशी जिले की धराली और हर्षिल घाटी में कुदरत का कहर ऐसा टूटा कि 5 अगस्त को खीरगंगा और तेलगाड़ में आए सैलाब ने 60 से अधिक लोगों और नौजवानों मलबे में दफन कर दिया था। धराली बाजार पूरी तरह तबाह हो गया था और 25 से 30 फीट तक मलबा जमने से पूरा इलाका जमींदोज हो गया था। पिछले साल ही यमनोत्री घाटी के सिलाई बैंड क्षेत्र में बादल फटने से सात मजदूर बह गए थे। कुपड़ाखड्ड के उफान पर आने से यमुना नदी में अस्थायी झील बन गई थी। जिससे स्यानाचट्टी कस्बे का अस्तित्व खतरे में पड़ गया था। इसके बाद 22 अगस्त की रात आई आपदा ने भारी तबाही मचाई। कोटडीप, राड़ीबगड़, अपर बाजार, कुलसारी, चेपड़ों और सगवाड़ा जैसे इलाकों में मलबा घरों और दुकानों में घुस गया था। चेपड़ों गांव में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था, जहां एक बुजुर्ग की मौत हुई थी जबकि सगवाड़ा में 20 वर्षीय युवती मलबे में दब गई थी। पहाड़ के लोग इस आपदा से उबरे भी नहीं थे कि सितंबर में नंदानगर क्षेत्र में आफत आ गई।

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की रिपोर्ट के मुताबिक 4 अक्टूबर 2021 तक सिर्फ 83 गांवों और 1,447 परिवारों का ही पुनर्वास किया गया, प्रभावितों को 61.02 करोड़ रुपये की राशि दी गई, गांवों के विस्थापन को लेकर धीमी रफ्तार के लिए राज्य में सुरक्षित जगह का अभाव बताया जाता है, सरकार के पास पुर्नवास की नीति तो है पर नियत नहीं है, यदि नियत होती तो कोई भी काम असंभव नहीं होता।

17 सितंबर की रात अतिवृष्टि के कारण पहाड़ियों से उतरे गदेरों ने कुंतरी और धुर्मा गांव को तबाह कर दिया था। सेरा गांव में आठ मकान बह गए थे जबकि फाली गांव में पांच लोगों की अकाल मौत हो गई थी। पूरे इलाके में एक महीने तक खौफ का माहौल बना रहा था। यही नहीं मानसून की बारिश ने 15-16 सितंबर की रात देहरादून में हुई मूसलाधार बारिश ने 101 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। सहस्त्रधारा में 264 मिमी बारिश दर्ज की गई, जिसने 1924 का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया था। इस दौरान मालदेवता, मसूरी रोड और नंदा की चौकी जैसे इलाकों में भारी नुकसान हुआ था। नंदा की चौकी का पुल बह गया, जिससे लोगों को वैकल्पिक रास्तों से आवाजाही करनी पड़ी थी। सहस्त्रधारा में घरों, होटलों और रेस्टोरेंट्स में पानी भर गया था। कई मकान ढह गए और जगह-जगह भूस्खलन हुआ। मालदेवता के केशरवाला क्षेत्र में सड़क का 100 मीटर हिस्सा बहने से करीब 17 गांवों का संपर्क टूट गया था। कुल मिलाकर वर्ष 2025 उत्तराखंड के लिए प्राकृतिक आपदाओं का ऐसा अध्याय बन गया था, जिसने विकास, सुरक्षा और आपदा प्रबंधन की तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे।

पुनर्वास की नीति है पर नियत नहीं

उत्तराखंड में 465 गांव ऐसे हैं, जिन्हें संवेदनशील माना गया है और इन गांवों को कहीं और बसाया जाना है, परंतु कहां यह ऐसा सवाल है जो अभी तक अनसुलझा है। उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास एवं विस्थापन के लिए 2011 में पुनर्वास नीति लागू की गई थी, जिसमें 2017 में संशोधन किया गया। इसके बाद 31 दिसंबर 2021 को फिर संशोधन किया गया। इस नीति में कहा गया है कि विस्थापन के लिए जमीन का चयन प्रभावित क्षेत्र के निकट सुरक्षित स्थल एवं उसी जनपद में होना चाहिए। विस्थापन के लिए निजी भूमि, राजस्व भूमि, पंचायत भूमि एवं जहां आवश्यकता हो वहां परिवारों के विस्थापन के लिए वन भूमि हस्तांतरण करने की कार्यवाई की जाए, जबकि विस्थापित परिवारों की संवेदनशील व अनुपयोगी भूमि (असुरक्षित भूमि) वन विभाग को हस्तांतरित की जाए। इस पुनर्वास नीति में स्पष्ट किया गया कि यदि विस्थापन के लिए प्रभावित परिवारों को निजी भूमि उपलब्ध नहीं हो पाती है तो उपलब्ध राजस्व या पंचायत भूमि के अधिग्रहण व हस्तांतरण की कार्रवाई संबंधित जिला अधिकारी के स्तर पर की जाएगी। भले ही 2021 में पुनर्वास नीति में संशोधन किया गया हो, लेकिन राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की रिपोर्ट के मुताबिक चार अक्टूबर 2021 तक सिर्फ 83 गांवों और 1,447 परिवारों का ही पुनर्वास किया गया और प्रभावितों को 61.02 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई। गांवों के विस्थापन को लेकर धीमी रफ्तार के लिए राज्य में सुरक्षित जगह का अभाव बताया जाता है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जनवरी 2023 में एक बड़े भूधंसाव का शिकार हुए जोशीमठ के लोगों के लिए अभी भी कोई सुरक्षित जगह नहीं मिल पाई है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि सरकार के पास पुर्नवास की नीति तो है पर नियत नहीं है। यदि नियत होती तो कोई भी काम असंभव नहीं होता।

2025 की बात करें तो उत्तराखंड एक नहीं अनेक अग्नि परीक्षाओं से गुजरा, पूरे साल प्रकृति ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि पहाड़ से लेकर मैदान तक जनजीवन अस्त-व्यस्त रहा, कहीं बादल फटे, कहीं हिमस्खलन हुआ तो कहीं मूसलाधार बारिश ने तबाही मचाई, इन आपदाओं ने न सिर्फ जिंदगियां छीनीं बल्कि वन्यजीवों के साथ पालतू पशुओं की जान भी आफत में डाल दी थी।

पुनर्वास का इंतजार

उत्तराखंड में मानसून से पहले और मानसून के बाद विस्थापन और पुनर्वास को लेकर सवाल उठने लगते हैं, लेकिन मानसून सीजन के समाप्त होने के बाद विस्थापन व पुनर्वास की चर्चाएं फाइलों में बंद हो जाती है। उत्तराखंड आपदा के लिहाज से बेहद संवेदनशील है। यही वजह है कि वैज्ञानिकों समेत तमाम सामाजिक संगठनों की ओर से पुनर्वास पर जोर दिया जाता रहा है, लेकिन आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से इस पर ठोस निर्णय नहीं हो पाता है। इसलिए यह पहाड़ी राज्य में हर साल मानसून के सीजन में भयानक और खौफनाक आपदाओं का दंश झेलता है। प्रलयकारी आपदाओं से न सिर्फ जान माल को नुकसान पहुंचता है, बल्कि सैकड़ों परिवार प्रभावित होते हैं। इसलिए संवेदनशील व अति संवेदनशील क्षेत्रों में बसे परिवारों का विस्थापन, पुनर्वास किया जाना आवश्यक है। ताकि उनको सुरक्षित स्थान पर बसाया जा सके। यह काम जिलाधिकारी के स्तर से होता है लेकिन लंबे समय से सैकड़ों परिवार ऐसे हैं, जिनका अभी तक पुनर्वास नहीं हो पाया है। आपदा प्रबंधन विभाग का कहना है कि प्रदेश के 270 गांव यानी 3744 परिवारों को विस्थापन की श्रेणी में रखा गया है। जिसमें से 2012 से 11 फरवरी 2026 तक 236 गांव यानी 2904 परिवारों को विस्थापित किया जा चुका है। इस पर 128,98,32,817 रुपये खर्च हो चुके हैं। जबकि 34 गांव यानी 843 परिवारों का विस्थापन होना बाकी है। आपदा की वजह से नए गांवों को भी जोड़ा जाता है, जिनको विस्थापित करने की जरूरत है। यानी 28 गांव के 207 परिवार ऐसे हैं, जो विस्थापन की श्रेणी में नए जुड़े हैं, जिन्हें विस्थापित किया जाना बाकी है। ऐसे में कुल 62 गांव के 1050 परिवारों को विस्थापित किया जाना बाकी है।

जन्भूमि नहीं छोड़ते लोग

आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव का कहना है कि विस्थापन में एक समस्या लोगों से जुड़ी हुई भी आती है। क्योंकि जहां लोग रहते हैं, उनकी जड़े और समाजिक ताना बाना वहां से जुड़ा होता है। यही वजह है कि लोग अपनी जन्मभूमि छोड़ना नहीं चाहते है। लोग चाहते है कि वो जहां रह रहे हैं, उसके आसपास ही रहे, ताकि उनका सांस्कृतिक संबंध और लोगों से समन्वय भी बना रहे, जो विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती है। हालांकि इसका रास्ता भी निकाला जा रहा है। कई बार जहां हम जमीन देखते हैं वहां उनको पसंद नहीं आती है। कई बार जहां जमीन देखी जाती है वहां कुछ लोग तैयार होते हैं और कुछ लोग नहीं होते। ऐसी कई तरह की समस्याएं आती हैं। सरकार जो मुआवजा तय करती है वही दिया जाता है। लेकिन सच यह है कि जब आपदा आती है,तब सरकार और सिस्टम को विस्थापन का इंतजार कर रहे गांव की याद आती है, लेकिन हर बार आपदा गुजर जाती है और विस्थापन का इंतजार ग्रामीण करते रह जाते है। यही वजह है कि सैंकडों गांव भूस्खलन की जद में रहते है।

एकिटव हुआ इंडिया ब्लॉक

इंडिया ब्लॉक के नेता महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर, गरीबी जैसे मुद्दे उठाकर भाजपा की आलोचना करते हैं, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी या गरीबी दूर करने के लिए उनके पास कौन सी छड़ी है, ये नहीं बताते, डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होने का दावा करते हैं, लेकिन डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत करने का चमत्कारी आइडिया कोई नहीं बताता।

बाबू सिंह
वरिष्ठ पत्रकार

इंडिया ब्लॉक का जिन्न दो साल बाद फिर बोतल से बाहर निकला है। 8 जून को 24 क्षेत्रीय दलों के नेता दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इकट्ठा हुए। हालांकि तमिलनाडु में जिस टीवीके से कांग्रेस ने ताजा गठबंधन किया है उस टीवीके पार्टी के मुखिया थलपति विजय को बैठक में बुलाया ही नहीं गया। डीएमके मुखिया एमके स्टालिन और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने इंडिया ब्लॉक का बहिष्कार कर दिया है। यानी इंडिया ब्लॉक से दो पार्टी अलग हो चुकी हैं। इंडिया ब्लॉक की बैठक में कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, जम्मू कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती, उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, बिहार से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, कपिल सिब्बल, पहुंचे, एनसीपी (शरद पवार गुट) की सुप्रिया सुले, सीपीएम के जॉन ब्रिटास, सीपीआई के डी.राजा के साथ वामपंथी दलों के नेता शामिल हुए। शिवसेना (उद्धव) के प्रमुख उद्धव ठाकरे व झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता हेमंत सोरेन बैठक में वर्चुअली शामिल हुए। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में करारी हार के कारण बड़े राजनीतिक संकट से जूझ रही टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के कहने पर इंडिया ब्लॉक की यह बैठक बुलाई गई थी। हालांकि 2024 में ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल की वजह से ही इंडिया ब्लॉक में दरार पड़ी थी। इन दोनों ने ही नितिश कुमार का विरोध किया था जिससे नितिश कुमार गठबंधन बनने से ही पहले अलग हो गए और भाजपा का दामन थाम लिया था। खैर इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने विपक्षी दलों की एकता मजबूत करने और भाजपा का मुकाबला करने के लिए नई रणनीति तैयार करने पर जोर लगाया। हालांकि भाजपा ने इंडिया ब्लॉक पर तंज कसते हुए कहा कि वोट चोरी नहीं हुआ बल्कि विपक्षी दलों का वजूद चोरी हुआ है।

कांग्रेस से नाराजगी

इंडिया ब्लॉक की बैठक में अधिकांश नेता अपने अपने राज्यों में हार की हताशा में थे। इसलिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने नसीहत दी कि कांग्रेस को कुर्बानी देनी चाहिए। कुछ नेताओं ने चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नेताओं द्वारा सहयोगी दलों के खिलाफ की गई बयानबाजी और समन्वय की कमी पर नाराजगी जताते हुए कहा कि कांग्रेस को गठबंधन धर्म निभाने के लिए बड़ा दिल दिखाना चाहिए और क्षेत्रीय दलों को आगे बढ़ाना चाहिए। उनका तर्क था कि जिन राज्यों में क्षेत्रीय दल अधिक मजबूत हैं, वहां कांग्रेस को पीछे हटना चाहिए। यानी विपक्षी एकता का संकल्प लेने के उद्देश्य से बुलाई गई बैठक में कांग्रेस को उसकी हैसियत तक बता दी गई। क्योंकि कांग्रेस किसी भी सहयोगी दल को चुनाव जिताने की स्थिति में नहीं है, बल्कि खुद क्षेत्रीय दलों की मदद से अभी थोड़े से वजूद में है। कांग्रेस वो पार्टी बन गई है जो गठबंधन के साथियों का बेड़ा गर्क कर रही है। इसका प्रमाण ये है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस की मदद से सीएम बने उद्धव ठाकरे के पास न पार्टी रही और न ही पार्टी का चुनाव निशान रहा। पार्टी और पार्टी का चुनाव निशान लेकर एकनाथ शिंदे उड़ गए। महाराष्ट्र में एनसीपी के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ। शरद पवार की पार्टी एनसीपी उनके भजीते अजित पवार लेकर उड़ गए। हाल ही में तमिलनाडु में डीएमके के एमके स्टालिन चुनाव क्या हारे कांग्रेस ने उनके साथ गद्दारी की और दशकों पुराना गठबंधन तोड़कर टीवीके सरकार का हिस्सा बन गए। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी ने खुलकर टीएमसी और ममता बनर्जी का विरोध किया, टीएमसी के खिलाफ अपने प्रत्याशी उतारे लिहाजा ममता बनर्जी का 15 साल का मजबूत किला भाजपा ने ध्वस्त कर दिया। अब ममता बनर्जी की पार्टी बचेगी भी या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि एक तरफ जहां ममता बनर्जी इंडिया ब्लॉक में विपक्षी एकता की बात कर रही थी वहीं दिल्ली में उनके 28 में से 20 सांसद ममता बनर्जी के साथ खेला कर रहे थे। टीएमसी के बागी सांसद दिल्ली में पश्चिम बंगाल के भाजपा प्रभारी भूपेंद्र यादव और बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात कर रहे थे। फिर एक गुमनाम पार्टी में बागियों ने अपना गुट विलय कर दिया। बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस

कांग्रेस वो पार्टी बन गई है जो गठबंधन के साथियों का बेड़ा गर्क कर रही है, महाराष्ट्र में कांग्रेस की मदद से सीएम बने उद्धव ठाकरे के पास न पार्टी रही और न ही पार्टी का झंडा रहा, महाराष्ट्र में एनसीपी के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ, तमिलनाडु में डीएमके के चुनाव हारने पर कांग्रेस ने गद्दारी कर दी, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ खेला हो गया।

इंडिया ब्लॉक यानी भाजपा विरोधी दलों का गठबंधन क्यों बना ये महत्वपूर्ण सवाल है? सब यही कहेंगे कि विपक्षी दल एक साथ एकजुट होकर चुनाव लड़े और भाजपा को हराएं। लेकिन इंडिया ब्लॉक का टारगेट ये कभी नहीं रहा, क्योंकि जब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए तो इंडिया ब्लॉक में शामिल सपा को कांग्रेस ने कोई सीट नहीं दी, लिहाजा सपा प्रमुख अखिलेश यादव को मध्य प्रदेश चुनाव में कहना पड़ा कि 'कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है इसे वोट मत देना।' हरियाणा चुनाव में केजरीवाल की पार्टी कांग्रेस से गठबंधन करना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस ने केजरीवाल को तवज्जों नहीं दी और अकेले चुनाव लड़ा, नतीजा कांग्रेस की शर्मनाक हार के रूप में सामने आया। दिल्ली में 2024 का लोकसभा चुनाव आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन में लड़ा, सात की सात सीटें हार गए, इसके कुछ ही महीनों बाद 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा। बिहार विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी हिट हुई, लेकिन चुनाव नतीजों में कांग्रेस तो डूबी साथ में तेजस्वी यादव को भी ले डूबी। पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कांग्रेस चुनाव लड़ती है और केरलम में कम्युनिस्ट पार्टी के विरोध में चुनाव मैदान में उतरती है। किसी भी गठबंधन का मतलब होता है कि सब एकजुट होकर मुकाबला करें, लेकिन इंडिया ब्लॉक में तो एक दूसरे को ही नीचा दिखाने की कोशिश होती रही है। इसलिए चुनावों में हारे हुए खिलाड़ी दिल्ली में एक मंच पर आए और फिर एकता का नाटक किया। दो साल बाद हुई इंडिया ब्लॉक की बैठक की जो तस्वीर आई उन्हें देखकर नहीं लगा कि सारे नेता दिल से मिले हैं। हर नेता के चेहरे के हाव भाव बता रहे थे कि यह गठबंधन मर्जी का नहीं मजबूरी का है। आम आदमी पार्टी के नेता तो साफ साफ कह रहे हैं कि कांग्रेस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसके विपरीत भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए है जिसमें शामिल दलों को लगातार ताकत मिल रही है। भाजपा खुद भी चुनाव जीतती है और अपने सहयोगी दलों को भी चुनाव जिताती है। इसलिए टीएमसी के सांसदों ने ममता बनर्जी से बगावत कर एनडीए का हिस्सा बनने का फैसला किया है।

मर्जी का नहीं मजबूरी का गठबंधन

इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस की छवि सबसे ज्यादा खराब है, क्योंकि दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव हों या तमिलनाडु का हाल में हुआ चुनाव कांग्रेस ने सहयोगियों के साथ धोखा ही किया है। इसलिए कहा जा रहा है कि इंडिया ब्लॉक मर्जी का नहीं मजबूरी का है। मजबूरी ये है कि क्षेत्रीय दलों को एक राष्ट्रीय पार्टी का सहारा चाहिए, जबकि कांग्रेस खुद क्षेत्रीय दलों के सहारे खड़ी है। अब क्षेत्रीय दलों को यह तय करना चाहिए कि कौन किसके सहारे है। मोदी विरोधी इंडिया ब्लॉक का विजन सिर्फ मोदी और भाजपा को हटाना है। इसके अलाव इंडिया ब्लॉक में शामिल दलों की न तो कोई राष्ट्रनीति है, न कोई अर्थनीति है। इंडिया ब्लॉक के नेता महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर, गरीबी जैसे मुद्दे उठाकर भाजपा की आलोचना करते हैं। आलोचना करनी भी चाहिए, क्योंकि विपक्षी दलों का ये काम भी, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी अथवा गरीबी दूर करने की उनके पास कौन सी जादुई छड़ी है, ये नहीं बताते, डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होने का दावा करते हैं,

- **बंगाल में विधानसभा चुनाव में हार के बाद राजनीतिक संकट से जूझ रही टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के कहने पर इंडिया ब्लॉक की बैठक हुई थी, हालांकि 2024 में ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल की वजह से ही इंडिया ब्लॉक में दरार पड़ी थी, इन दोनों के विरोध से नितिश कुमार गठबंधन बनने से ही पहले अलग हो गए थे।**
- **प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की आलोचना करते हैं लेकिन अपनी विदेश नीति किसी भी मोदी विरोधी ने आज तक जनता के सामने नहीं रखी, केंद्र और राज्यों की भाजपा सरकारों की नीतियों की आलोचना तो करते हैं, लेकिन अपनी रामराज्य वाली नीति नहीं बताते, पीएम मोदी का विरोध करते करते विपक्षी नेता देश का विरोध करने लगते हैं ये उन्हें पता ही नहीं चलता।**

लेकिन डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत करने का चमत्कारी आइडिया कोई नहीं बताता। विपक्षी दलों का सबसे फेवरेट नारा है लोकतंत्र और संविधान खतरे में है, लेकिन लोकतंत्र और संविधान से खतरा कैसे टाला जाएगा ये कभी नहीं बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की आलोचना करते हैं लेकिन अपनी विदेश नीति किसी भी मोदी विरोधी ने आज तक जनता के सामने नहीं रखी। केंद्र और राज्यों की भाजपा सरकारों की नीतियों की आलोचना तो करते हैं, लेकिन अपनी रामराज्य वाली नीति नहीं बताते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते विपक्षी नेता देश का विरोध करने लगते हैं ये उन्हें पता ही नहीं चलता। संसद में सिर्फ हंगामा करके जनता के धन को लूटते हैं, लेकिन जनता के हित के कानून पारित नहीं होने देते। क्या इसलिए ही इंडिया ब्लॉक का गठन हुआ है?

एसआईआर से सहमा गठबंधन

इंडिया ब्लॉक की बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 17 अप्रैल, 2026 को लोकसभा के बजट सत्र में जिस तरह हमने अपनी एकजुटता और एकता दिखाते हुए मजबूती से डिलिमिटेशन पर मोदी सरकार के दुर्भावनापूर्ण बिलों को परास्त किया। अब हमें उसी भावना को और मजबूत करना है, आगे बढ़ाना है, ताकि मोदी सरकार के कुशासन के कारण देश के सामने खड़ी कई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और विदेश नीति से जुड़ी चुनौतियों का सामना किया जा सके। खड़गे ने कहा कि एसआईआर के कारण हमारे करोड़ों लोगों से उनका मताधिकार छीना जा रहा है। संविधान पर हमला लगातार जारी है। जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने और डराने-धमकाने के औजार के रूप में लगातार किया जा रहा है। गैर भाजपा सरकारों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। जरूरी वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और आर्थिक माहौल बेहद नकारात्मक है। नई नौकरियां पैदा करने के लिए जिस रफ्तार से नए निवेश आने चाहिए, वे बिल्कुल उस रफ्तार से नहीं आ रहे हैं। कई क्षेत्रों में निजी एकाधिकार बढ़ रहा है और एमएसएमई का भविष्य गंभीर संकट में है। परीक्षा प्रणाली के पूर्ण कुप्रबंधन के कारण हमारे लाखों युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं के साथ विश्वासघात किया जा रहा है। समाज के कमजोर वर्गों पर अत्याचार, खासकर भाजपा शासित राज्यों में लगातार जारी हैं। हमारी विदेश नीति के साथ पूरी तरह से समझौता किया गया है और उन पारंपरिक मूल्यों को कायम नहीं रखा गया है, जिनका भारत लंबे समय से पुरजोर समर्थन करता रहा है। बैठक का निष्कर्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयानों से स्पष्ट हो गया, लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है कि मल्लिाकार्जुन ने एक भी समस्या का समाधान नहीं बताया, न ही कोई विकल्प बताया। इसलिए कांग्रेस सहित इंडिया ब्लॉक के घटक दल पर जनता भरोसा नहीं करती।

अतीत

छल से पीएम बने थे नेहरू

कांग्रेस नेता एक ऐतिहासिक तथ्य बताना भूल जाते हैं कि 15 में से 12 प्रांतीय समितियों ने सरदार वल्लभभाई पटेल को वोट दिया था, प्रांतीय समितियों ने आधिकारिक रूप से नेहरू के नाम का प्रस्ताव ही नहीं किया था फिर भी महात्मा गांधी ने जबरन नेहरू को पीएम बनाकर भारत पर थोप दिया था, गांधी के दबाव में सरदार पटेल को अपनी दावेदारी वापस लेनी पड़ी थी।

नेहरू के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ना नरेंद्र मोदी की सियासी लोकप्रियता का सबसे बड़ा प्रमाण है, देश की सत्ता में लगातार तीन बार आना और टिके रहना मोदी ब्रांड की ताकत दिखाता है, पीएम मोदी ने इतिहास तो रच दिया है, लेकिन अब आगे बारी अग्निपरीक्षा की है, मोदी के सामने चुनौती विकसित भारत के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की है।

कृष्ण कुमार चौहान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैसे तो रिकार्ड बनाने के लिए ही जाने जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है, जिसे छूना किसी भी नेता के लिए ख्वाब जैसा होगा। आजाद भारत में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर बने रहने वाले जवाहर लाल नेहरू के रिकॉर्ड को नरेंद्र मोदी ने पीछे छोड़ दिया है। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर पीएम की कुर्सी पर विराजमान हुए थे। 10 जून 2026 को उन्होंने लगातार अपने कार्यकाल के 4,399 दिन पूरे कर लिए हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू 1952 के बाद चुनी हुई सरकार के 4,398 दिनों तक पीएम रहे थे। इस हिसाब से नरेंद्र मोदी देश के सबसे लंबे समय तक चुने हुए पीएम रहने वाले पहले नेता बन गए हैं। जवाहर लाल नेहरू ने प्रधानमंत्री के तौर पर आजादी के बाद बिखरे हुए भारत को संस्थागत रूप दिया। जिसे नरेंद्र मोदी ने आगे बढ़ाते हुए विकसित भारत बनाने की आधार शिला रखी और 21वीं सदी के भारत को एक शक्ति के रूप में वैश्विक पटल पर खड़ा किया है। नरेंद्र मोदी 2014 में पहली बार, 2019 में लगातार दूसरी बार और 2024 में ऐतिहासिक रूप से लगातार तीसरी बार जनादेश हासिल करके भारत की सेवा कर रहे हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के दौर में कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और राष्ट्र-निर्माण के प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए हैं, जिनमें नया संसद भवन, सेंट्रल विस्टा का रीडेवलपमेंट, कर्तव्य पथ, वंदे भारत ट्रेनें, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, आईएनएस विक्रांत, कश्मीर रेल लिंक, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नमो भारत आरआरटीएस और गंगा एक्सप्रेस-वे जैसे बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। मोदी के कार्यकाल में ही जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 समाप्त हुआ। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और आपरेशन सिंदूर जैसे सख्त फैसले लेकर पड़ोसी पाकिस्तान के साथ दुनिया को बता दिया कि ये नया भारत है। मोदी के कार्यकाल में ही सैन्य उपकरण आयात करने वाला भारत सैन्य सामग्री निर्यात करने वाला राष्ट्र बन गया।

देश और दुनिया से मिली बधाई

नेहरू का रिकॉर्ड तोड़कर आगे निकलने और सबसे लंबे समय तक चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करने वाले नरेंद्र मोदी को देश दुनिया के नेताओं ने बधाई देते हुए नरेंद्र मोदी के परिवर्तनकारी शासन, विकासशील देशों के लिए उनके प्रयासों और समावेशी तथा आर्थिक रूप से गतिशील भारत के दृष्टिकोण की सराहना की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, मेरे दोस्त, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक पीएम बने रहने पर बधाई। वे सचमुच एक बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री हैं। वह मजबूत और समझदार इंसान हैं। उन्हें जीवन में आगे भी बहुत बड़ी सफलताएं मिलेगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका ने कहा कि यह उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार-बार जताए गए विश्वास का प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श और नेतृत्व का उदाहरण बताया। उन्होंने दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की इच्छा व्यक्त की। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला पर्सद-बिसेसर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की साधारण शुरुआत से लेकर एक करोड़ 40 लाख लोगों के राष्ट्र का नेतृत्व करने तक की यात्रा की चर्चा की और विदेश नीति, आर्थिक विकास और सामाजिक-आर्थिक उत्थान में भारत की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को उल्लेखनीय बताया। मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागिन खुरेलसुख ने अपने संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को तीसरे कार्यकाल के लिए चुने जाने और भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली ने अपने संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को लगातार तीन लोकतांत्रिक कार्यकालों में भारत का नेतृत्व करने और देश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री बनने की ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष वॉन डेर लेयेन ने अपने संदेश में कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं और भारत-यूरोपीय संघ संबंध भी लगातार मजबूत हुए हैं। उन्होंने प्रौद्योगिकी, गतिशीलता, सुरक्षा, रक्षा और व्यापार के क्षेत्रों में दोनों पक्षों के सहयोग की सराहना की। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने भी पीएम नरेंद्र मोदी को बधाई संदेश भेजा है। पीएम मोदी ने भी सभी राष्ट्राध्यक्षों का आभार व्यक्त किया है। आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने पीएम मोदी को बधाई देते हुए कहा कि मोदी का सिंगल ऐजेंडा नेशन फास्ट है। मोदी देश के एक महान नेता है। भारत को सही वक्त पर सही नेता मिला। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि आज भारत मोदी के नेतत्व में नए छितिज को छू रहा है। मोदी के मजबूत नेतत्व की बदौलन देश मजबूत बन रहा है। मोदी एक तपस्वी है और वो त्रिकालदर्शी है। राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने प्रधानमंत्री मोदी की इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए कहा कि इसके लिए देश की जनता भी धन्यवाद की पात्र है, जिसने लगातार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जताया है। एक तरफ जहां देश और दुनिया के नेताओं ने मोदी के रिकॉर्ड बनाने पर बधाई दी तो वहीं अपने ही देश में विपक्षी दलों ने पीएम मोदी की उपलब्धियों की सिर्फ आलोचना करते हुए यहां तक कहा कि नेहरू से मोदी की तुलना नहीं की जानी चाहिए।

- **निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी द्वारा जवाहर लाल नेहरू को पीछे छोड़ने पर पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ ने आर्टिकल लिखा है, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि 1952 में पीएम बनना आसान था, क्योंकि तब कुल जमा 53 पार्टियां ही थी उनका भी कांग्रेस के मुकाबले प्रभाव न के बराबर था।**
- **कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी का दावा है कि नेहरू के पीएम बनने को भाजपा 26 जनवरी 1952 यानी गणतंत्र दिवस से गिनती कर रही है, जबकि भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, नेहरू 15 अगस्त 1947 को ही प्रधानमंत्री बने थे, उनके पहले 5 साल (1947-1952) में आधुनिक भारत बना।**

रिकॉर्ड बना, अग्निपरीक्षा की बारी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजनीतिक तौर पर भाजपा को ही नहीं बल्कि एनडीए को मजबूती मिली है, देश के 22 राज्यों में एनडीए की सरकार है। बंगाल से लेकर राजस्थान तक असम से लेकर गुजरात तक भाजपा सत्ता में है। नेहरू के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ना नरेंद्र मोदी की सियासी लोकप्रियता का सबसे बड़ा प्रमाण है। देश की सत्ता में लगातार तीन बार आना और टिके रहना मोदी ब्रांड की ताकत दिखाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिकॉर्ड बनाकर इतिहास तो रच दिया है, लेकिन अब आगे बारी अग्निपरीक्षा की भी है। पीएम मोदी के सामने चुनौती विकसित भारत के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की है। 2026 भारत के लिए रिफॉर्म एक्सप्रेस का साल बन चुका है। मोदी सरकार का लक्ष्य अगले दो से तीन सालों में भारत की जीडीपी को उस मुकाम पर पहुंचाना है जहां हम जर्मनी और जापान को पछाड़कर अमेरिका और चीन के ठीक पीछे खड़े हों।

इलेक्ट नहीं सेलेक्ट पीएम थे नेहरू

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने को भाजपा का स्व-घोषित और संदिग्ध रूप से गढ़ा गया प्रोपेगेंडा बताते हुए कहा कि मोदी के पास पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के प्रति एक रुग्ण जुनून है और वे नेहरू की विरासत को मिटाना चाहते हैं। जयराम रमेश ने कहा कि मोदी भारत के लिए गले की फांस बन गए हैं, क्योंकि वे भारत में लोकतंत्र की हत्या के लिए जिम्मेदार हैं, लोकतंत्र के जिन संस्थानों, स्वतंत्र चुनाव आयोग और मतदाता सूची पर भरोसा किया जाता था, वे अब खतरे में हैं। कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि नेहरू के पीएम बनने को भाजपा 26 जनवरी 1952 यानी गणतंत्र दिवस से गिनती कर रही है, जबकि भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। नेहरू 15 अगस्त 1947 को ही प्रधानमंत्री बने थे। उनके पहले 5 साल (1947-1952) में आधुनिक भारत बना। 560 से ज्यादा रियासतों को बिना लड़ाई के भारत में शामिल किया गया, संविधान बना, जमींदारी खत्म की गई, दलित-आदिवासियों के लिए आरक्षण शुरू हुआ, बड़े-बड़े सिंचाई और बिजली प्रोजेक्ट शुरू हुए और भारत दुनिया में एक ताकत के रूप में उभरा। कांग्रेसियों के अपने तर्क है लेकिन कांग्रेस नेता ये बताना भूल गए कि नेहरू ने ही भारत का अभिन्न हिस्सा यानी आधा कश्मीर पाकिस्तान को दे दिया, जो आज पीओके कहलाता है। नेहरू के कार्यकाल में ही 1962 के भारत-चीन युद्ध के दौरान, चीन ने लद्दाख के अक्साई चिन क्षेत्र में लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर के भारतीय भूभाग पर अवैध कब्जा कर लिया। कांग्रेस नेता एक ऐतिहासिक तथ्य बताना भूल गए कि 1946 में कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव (जो भावी प्रधानमंत्री के चुनाव का आधार था) नेहरू हार गए थे। 15 में से 12 प्रांतीय समितियों ने सरदार वल्लभभाई पटेल को वोट दिया था, प्रांतीय समितियों ने आधिकारिक रूप से नेहरू के नाम का प्रस्ताव ही नहीं किया था फिर भी महात्मा गांधी ने जबरन नेहरू को पीएम बनाकर भारत पर थोप दिया था। गांधी के दबाव में सरदार वल्लभभाई पटेल को अपनी दावेदारी वापस लेनी पड़ी थी। कांग्रेसी ये भी बताना भूल गए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही सारी रियासतों का भारत में विलय कराया था, लेकिन संपूर्ण जम्मू-कश्मीर रियासत को नेहरू ने भारत में विलय नहीं होने दिया था। क्योंकि नेहरू चाहते थे कि जम्मू-कश्मीर पाकिस्तान में चला जाए। कांग्रेस को ये सभी श्रेय भी नेहरू को ही देने चाहिए थे।

एचडी देवगौड़ का आर्टिकल वायरल

कांग्रेस कह रही है कि मोदी की तुलना नेहरू से नहीं की जा सकती, बिल्कुल नहीं की जानी चाहिए क्योंकि नेहरू तो 1946 में ही कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हार गए थे। निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी द्वारा जवाहर लाल नेहरू को पीछे छोड़ने पर पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ ने आर्टिकल लिखा है। जिसमें स्पष्ट लिखा है कि 1952 में पीएम बनना आसान था। क्योंकि तब कुल जमा 53 पार्टियां ही थी उनका भी कांग्रेस के मुकाबले प्रभाव न के बराबर था। 1952 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 16 सीटें जीत कर सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनी थी। सोशलिस्ट पार्टी 12 सीटों के साथ दूसरी बड़ी विपक्षी पार्टी थी। निर्दलीय और अन्य छोटे दलों के उम्मीदवारों ने 37 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि गणतंत्र परिषद को 6 सीटें और हिंदू महासभा व भारतीय जनसंघ को 3-3 सीटें मिली थीं। 1952 में कुल 489 सीटों में से कांग्रेस ने 364 सीटें जीत कर सत्ता हासिल की थी। जबकि 2014 में मोदी का मुकाबला 2593 राजनीतिक दलों से था। इनमें कई राजनीतिक दल अपने क्षेत्र में खासा प्रभाव रखने वाले हैं। जब नेहरू पहली बार पीएम चुने गए तब 17 करोड़ मतदाता थे। मोदी जब पीएम बने तब वोटर की संख्या 84 करोड़ है। मोदी की तुलना नेहरू क्या किसी से नहीं हो सकती। क्योंकि मोदी ने 2014 से पहले यूपीए और फिर इंडिया ब्लॉक जैसे गठबंधनों से मुकाबला किया है। मोदी ने विपक्ष के भाजपा विरोधी एजेंडा चलाने वाले इकोसिस्टम से मुकाबला किया, फेक नैरेटिव, वामपंथी विचारधारा, लाखों भाजपा विरोधी एक्टिविस्ट, हजारों कांग्रेस समर्थक इन्फ्लुएंसर, यूट्यूब से मोदी ने मुकाबला किया। ये सब नेहरू के दौर में नहीं था, उस दौर में अखबार भी गिनती के ही थे। मोदी ने उस मीडिया से भी मुकाबला किया जिनका कांग्रेस के जमाने में सिक्का चलता था, जो एमपी एमएलए को मंत्री तक बनवा देते थे। ●

सियासत

अब नीलकंठ बनेंगे राहुल

राहुल गांधी ने अहंकारी अंदाज में कहा कि बैठक में कांग्रेस के बारे में जो कुछ भी कहा गया, उसका जवाब देना मेरा काम नहीं है, मेरा काम शिव परंपरा को अपनाना है, सब कुछ निगल जाना, नीलकंठ वाले शिव की तरह, जो सारा जहर पी जाते हैं, आपको चाहे जितनी मेरी या कांग्रेस की आलोचना करनी हो करो, हम उसे खुशी-खुशी स्वीकार करेंगे।

उदयभान सिंह
लेखक

8 जून को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इंडिया गठबंधन की बैठक में कांग्रेस और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से सहयोगी नेताओं को कई मुद्दो पर असहमति देखी गई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने तो राहुल गांधी को नसीहत दी कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है इसलिए उसे कुर्बानी देनी चाहिए। सभी नेता अपनी बात रख चुके थे, अंत में राहुल गांधी की बारी आई तो उन्होंने अपने भाषण की शुरूआत सभी के स्वागत के साथ करते हुए किस्सा सुनाया कि कई साल पहले मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त से बहस हुई थी। मैंने उससे कहा था जो तुम कर रहे हो वो बिल्कुल अनफेयर है। उसका जवाब था कि दुनिया ही अनफेयर है। अब इसकी आदत डाल लो। राहुल गांधी ने अहंकारी अंदाज में कहा कि बैठक में कांग्रेस के बारे में जो कुछ भी कहा गया, उसका जवाब देना मेरा काम नहीं है। मेरा काम शिव परंपरा को अपनाना है। सब कुछ निगल जाना। नीलकंठ वाले शिव की तरह, जो सारा जहर पी जाते हैं। आपको चाहे जितनी मेरी या कांग्रेस की आलोचना करनी हो करो, हम उसे खुशी-खुशी स्वीकार करेंगे। हम सभी सहयोगियों को खुश करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारी भूमिका, आपकी भूमिका से बुनियादी तौर पर अलग है। यह मैं अहंकार से नहीं कह रहा हूं। मेरी भूमिका आप सबको प्यार और स्नेह से जोड़ने की है। मैं 2004 से कांग्रेस का सांसद हूं, जब मैंने अपना पहला चुनाव लड़ा था। हमारी पार्टी भारत की दूसरी सभी पार्टियों से बुनियादी तौर पर अलग तरीके से संगठित थी। मैं यह विनम्रता से कह रहा हूं, क्यों? क्योंकि यह पार्टी एक प्रतिरोध आंदोलन के रूप में शुरू हुई थी, जब आधुनिक भारत अस्तित्व में भी नहीं था। अन्य सभी पार्टियों के विपरीत इसे भारतीय राज्य की इंफ्रस्ट्रक्चर और सुरक्षा पर खड़ा नहीं किया गया था। कांग्रेस एक प्रतिरोध आंदोलन है, जो इस विचार की रक्षा करती है कि सभी भारतीय बराबर हैं। राहुल गांधी ने दार्शनिक भाषण देते हुए खुद को और कांग्रेस को टीएमसी, सपा, आरजेडी, नेशनल कांफ्रेंस, पीडीपी आदि दलों से सुपर बताने की कोशिश की। इंडिया गठबंधन की बैठक में राहुल गांधी का व्यवहार ऐसा था जैसे वो नौसिखियों या अनुभवहीन नेताओं को प्रशिक्षण दे रहे हों। राहुल गांधी ने सहयोगी दलों को समझाया कि भाजपा और आरएसएस का मुकाबला पारंपरिक राजनीतिक तरीकों से नहीं किया जा सकता। बल्कि मौजूदा परिस्थितियों में विपक्ष को चुनावी राजनीति से आगे बढ़कर लोकतांत्रिक संस्थाओं और संविधान की रक्षा के लिए व्यापक जन-प्रतिरोध खड़ा करना होगा। राहुल गांधी ने सहयोगी दलों के सामने एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दृष्टिकोण रखा, जो लोकसभा चुनाव 2024 के बाद दिए गए उनके सबसे अहम संदेशों में से एक माना जा रहा है।

आरएसएस के सामने नहीं झुकेगी कांग्रेस

राहुल गांधी ने कांग्रेस को आरएसएस की सोच के बिल्कुल खिलाफ बताते हुए कहा कि हम मर जाएंगे, कांग्रेस पार्टी में मर जाएगी, लेकिन भाजपा या आरएसएस के साथ कभी समझौता नहीं करेंगे। इसके लिए हमें हमारे सिर कटाने पड़ेंगे। मुझे पता है कि इस देश में लाखों कांग्रेस कार्यकर्ता हैं जो कहेंगे हमारे सिर काट दो, हम आरएसएस के सामने झुकेंगे नहीं। मुझे यह कहते हुए अफसोस है कि इस समूह में कुछ भ्रम है। भ्रम यह है कि आप में से कुछ सपा, टीएमसी, आरजेडी आदि अभी भी मानते हैं कि आपके पास जो राजनीतिक साधन हैं, वे अभी भी काम करेंगे। ये तभी काम करते थे जब देश ने आपको निष्पक्ष चुनावी मैदान दिया था। वह मैदान अब मौजूद नहीं है। भाजपा चुनाव आयोग, कानूनी व्यवस्था, नौकरशाही, सीबीआई और खुफिया एजेंसियों को नियंत्रित करती है। भाजपा चुनाव आयोग तक को नियंत्रित करती है। मेरे टीएमसी में कई दोस्त हैं। वे मानते थे कि बंगाल में वे चुनाव जीत रहे हैं। मैं उन्हें बार-बार कहता रहा तुम सपनों की दुनिया में जी रहे हो। मैंने गुजरात में देखा है, मध्य प्रदेश में देखा है, छत्तीसगढ़ में देखा है, हरियाणा और महाराष्ट्र में देखा है। फिर भी आपमें से कई अभी भी आश्वस्त नहीं हैं। कांग्रेस प्रतिरोध की पार्टी है। इसे भारतीय राज्य की तटस्थता की जरूरत नहीं है। बल्कि जितना ज्यादा भारतीय राज्य के संस्थान दबाए जाएंगे, कब्जाए जाएंगे, कांग्रेस उतनी ही आक्रामकता से भारत के संविधान की रक्षा के लिए लड़ेगी। हम सभी कांग्रेस के आदर्शों को साझा करते हैं। वे आदर्श क्या हैं? सत्य, अहिंसा और करुणा। मुझे आपसे लड़ने में कोई रुचि नहीं है। आपसे लड़ने के लिए मुझे पागल होना पड़ेगा। क्योंकि आप हमारे सहयोगी हैं, आप हमारे दोस्त हैं, आप वे लोग हैं जिनसे हम प्रेम करते हैं। प्लीज समझिए हमने 2024 का चुनाव जीता था। हमने हारा नहीं था। राहुल गांधी के भाषण से जाहिर होता है कि उन्हें कांग्रेस का इतिहास पढ़ने की जरूरत है।

राहुल को डीएमके के साथ आने की उम्मीद है पर वो केरल के पूर्व मुख्यमंत्री को गले नहीं लगाएंगे, क्योंकि उनसे राहुल की राजनीतिक लड़ाई है। यानी राहुल ने जिस डीएमके के साथ धोखा किया उसकी तो साथ आने की गारंटी ले रहे है, पर केरल के पूर्व सीएम से नफरत क्यों? इसलिए कहा जाता है कि राहुल कहां से शुरु होते हैं और कहां खत्म होते हैं उन्हें खुद पता नहीं होता।

विपक्ष को माइंडसेट बदलना होगा

आप पूछते हैं कि नीतीश जी इंडिया गठबंधन से क्यों चले गए? वह मेरी वजह से नहीं, कांग्रेस की वजह से नहीं गए। मैं आपको बताता हूं कि निकट भविष्य में वो औजार भी काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि भाजपा और आरएसएस भारतीय राज्य पर अपनी पकड़ और मजबूत कर रही है। कांग्रेस ने 100 साल से ज्यादा पहले यही फैसला लिया था। 1927 से पहले हम एक राजनीतिक संगठन थे। गांधी जी ने जब स्वराज की मांग की, हम प्रतिरोध आंदोलन बन गए। अगर राजनीतिक पार्टियां काम नहीं कर सकतीं, तो क्या काम कर सकता है? प्रतिरोध काम करता है। विरोध काम करता है। जहां हम प्रतिरोध करते हैं, वहां काम करता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं इस देश में 4000 किलोमीटर पैदल चला। युवा प्रतिरोध करता है, तो काम करता है। आपको राजनीतिक ढांचा नहीं चाहिए। आपको नौकरशाही की जरूरत नहीं। आपको खुफिया एजेंसियों की जरूरत नहीं। आपको प्रतिरोध का कर्म करना होगा-अर्थात मैं प्रतिरोध करूंगा। मैं आपको नहीं रुकने दूंगा। यही अंत है। यह एक भावना है, संगठन नहीं। यह सोचने का तरीका है। और चाहे हम उसे पसंद करें या नहीं, हमें वहीं जाना होगा। माइंडसेट बदलना होगा। माइंडसेट अब यह होना चाहिए कि हम एक-दूसरे से नहीं लड़ेंगे। हम प्रेस को हम पर हमला करने का मौका नहीं देंगे। हम प्रतिरोध करेंगे। राहुल गांधी के भाषण की खासियत ये थी कि उनकी आधे से ज्यादा बातें किसी के पल्ले नहीं पड़ी।

आरएसएस का देश के औजारों पर कब्जा

आप सोच रहे हैं कि चुनौती अगला चुनाव जीतने की है। अगला चुनाव तो पहले ही जीत लिया गया है। प्लीज समझिए भारत की जनता में इतना गुस्सा है कि अगला चुनाव पहले ही खत्म हो चुका है। समस्या आरएसएस द्वारा देश के औजारों पर कब्जे की है (औजारों का मतलब सिस्टम से है) समस्या यह है कि आपको जीतने के लिए निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव नहीं मिलेगा। इसलिए हमें प्रतिरोध मोड में जाना होगा। प्रतिरोध सीबीएसई है। प्रतिरोध एनईईटी है। प्रतिरोध है ग्रेट निकोबार। प्रतिरोध है भारत जोड़ो यात्रा। सुबह उठकर पूछो मैं आज प्रतिरोध कैसे करूं? और प्रतिरोध करो। मैं आपको गारंटी देता हूं, यह काम करेगा। मेरी नजर में किसी भी तरफ से कोई भी आलोचना मैं खुशी से झेलने को तैयार हूं, क्योंकि मेरे लिए यह धार्मिक कर्तव्य है, आध्यात्मिक कर्तव्य है। यह अब राजनीति नहीं रही। इसलिए मैं आपको वादा करता हूं कि इस समूह को जोड़ने और सफल बनाने के लिए जितना भी अपमान सहने पड़ेंगे, मैं सहूंगा। आगे कैसे बढ़ें, यह बहुत सरल है। हमें एक खास विचार से दूर होना होगा।

- **हम सभी कांग्रेस के आदर्शों को साझा करते हैं, वे आदर्श क्या हैं? सत्य, अहिंसा और करुणा, मुझे आपसे लड़ने में कोई रुचि नहीं है, आपसे लड़ने के लिए मुझे पागल होना पड़ेगा, क्योंकि आप हमारे सहयोगी हैं, आप हमारे दोस्त हैं, आप वे लोग हैं जिनसे हम प्रेम करते हैं, प्लीज समझिए हमने 2024 का चुनाव जीता था, हमने हारा नहीं था।**
- **अफसोस है कि इस समूह में कुछ भ्रम है, भ्रम यह है कि आप में से कुछ सपा, टीएमसी, आरजेडी आदि अभी भी मानते हैं कि आपके पास जो राजनीतिक साधन हैं, वे अभी भी काम करेंगे, ये तभी काम करते थे जब देश ने आपको निष्पक्ष चुनावी मैदान दिया था, वह मैदान अब मौजूद नहीं है।**

मोदी सरकार टिक नहीं पाएगी

ममता दीदी 100 प्रतिशत तो नहीं, लेकिन 90 प्रतिशत यकीन से कहती हैं कि उनका चुनाव चुराया गया। उद्धव जी 40 प्रतिशत यकीन रखते हैं। मेरे भाई तेजस्वी 40 प्रतिशत लेकिन सुनिए 100 प्रतिशत यकीन रखिए चुनाव चुराये जा रहे हैं। अपने मन से सारे संदेह हटा दीजिए। समझिए कि सोशल मीडिया पर उपस्थिति बनाने में सालों लगते हैं। यह एक हफ्ते में ऑर्गेनिक नहीं होता। मेरे 1 करोड़ यूट्यूब फॉलोअर्स हैं, लेकिन मेरा अकाउंट पूरी तरह दबाया गया है। अगर आप यह सोच रहे हैं कि सोशल मीडिया निष्पक्ष है और विपक्ष को सपोर्ट मिल रहा है, तो आप दूसरी दुनिया में जी रहे हैं। पूरा आर्किटेक्चर-मीडिया, सोशल मीडिया, कानूनी व्यवस्था, नौकरशाही, खुफिया एजेंसियां सब इस सरकार को सत्ता में बनाए रखने के लिए हैं। लेकिन यह सरकार टिक नहीं पाएगी। यह टिक नहीं पाएगी क्योंकि इसने हमारे लोकतंत्र को नष्ट कर दिया है। इसने भारतीय लोगों के भविष्य को नष्ट कर दिया है। अब जो आने वाला है (ईरान के बाद), वह अनियंत्रित है यह हमें जनता को संगठित करने का अवसर देगा। यह भी समझ लीजिए कि हम समन्वित नहीं हैं, साथ काम नहीं करते, ये सब भाजपा और उसके मीडिया दोस्त फैला रहे हैं। यह सच नहीं है। मैं डीएमके की गारंटी ले सकता हूं कि भारत के विचार की रक्षा में हर कोई इस कमरे में खड़ा होगा। हमारे बीच झगड़े हैं, होंगे, लेकिन अगर आप मुझसे कहें कि मैं केरल के पूर्व मुख्यमंत्री को गले लगाऊं, तो मैं नहीं कर सकता और नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी उनसे राजनीतिक लड़ाई चल रही है। यानी राहुल गांधी ने जिस डीएमके के साथ धोखा किया उसकी तो गारंटी ले रहे थे कि वो भी हमारे साथ इस कमरे में होगी, फिर केरल के पूर्व मुख्यमंत्री से नफरत क्यों? इसलिए कहा जाता है कि राहुल गांधी कहां से शुरू होते हैं और कहां खत्म होते हैं कुछ कहा नहीं जा सकता। उनकी बातों को सहयोगी दलों के नेताओं ने कितना समझा होगा यह भी कहना बड़े-बड़े विश्लेषकों के बसकी बात नहीं है। फिर राहुल लचीला बनने की भी कोशिश करते हैं कहते हैं कि हमें लचीला होना होगा और समझना होगा कि हम पर पूरा हमला है। यह साबित करने के लिए कि विपक्ष कमजोर है, अव्यवस्थित है। अंत में मुझे लगता है कि हमारी चर्चाओं में अक्सर उदासी छाई रहती है। लोग सोचते हैं, हे भगवान हम भाजपा को कभी हरा पाएंगे? मैं आपको बताता हूं, अगर हम साथ खड़े होकर प्रतिरोध करें तो उन्हें हराना आसान है। पिछले चुनाव में इस कमरे में मेरे अलावा किसी को यकीन नहीं था कि हम भाजपा को हरा सकते हैं। अब इस कमरे में हर कोई यह विश्वास करना शुरू करे कि हम उन्हें हरा देंगे। इस विश्वास से शुरू कीजिए और मैं गारंटी देता हूं राज्य दर राज्य, चुनाव दर चुनाव, चाहे वे धांधली करें या न करें, वे गिरेंगे। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि राहुल गांधी ज्यादातर मौके पर लिखकर देता हूं, गारंटी देता हूं जैसी जुमलेबाजी करते हैं किंत क्या उन्हें याद रहता है कि उन्होंने क्या गारंटी दी थी, क्या लिखकर दिया था। ●

वृद्धों का तिरस्कार नहीं सम्मान करें

वृद्ध व्यक्ति वह पुस्तक है जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर जीवन के संघर्ष, सफलताएं, विफलताएं, त्याग और धैर्य की कहानियां अंकित होती हैं, उनके सफेद बाल केवल आयु का संकेत नहीं, बल्कि अनुभव के चांदी जैसे मुकुट हैं, उनके चेहरे की झुर्रियां समय की मार नहीं, बल्कि जीवन-यात्रा के मानचित्र हैं।

विश्वनाथ झा
वरिष्ठ पत्रकार

किसी भी सभ्यता की परिपक्वता का आकलन केवल उसके आर्थिक विकास, वैज्ञानिक उपलब्धियों या तकनीकी प्रगति से नहीं किया जाता, बल्कि इस बात से किया जाता है कि वह अपने सबसे अनुभवी, निर्बल और आश्रित नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार करती है। वृद्धजन किसी भी समाज की जीवित स्मृति, सांस्कृतिक विरासत और नैतिक चेतना के संवाहक होते हैं। उनके अनुभवों में इतिहास की गहराई, संघर्षों की सीख और जीवन-दर्शन की परिपक्वता निहित होती है। वे केवल परिवार के सदस्य नहीं, बल्कि पीढ़ियों के बीच ज्ञान और मूल्यों के सेतु होते हैं। विडंबना यह है कि जिन हाथों ने परिवारों को संवारने, बच्चों का भविष्य गढ़ने और समाज की नींव मजबूत करने में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया, वही हाथ जीवन की संध्या बेला में अनेक बार उपेक्षा, तिरस्कार, आर्थिक शोषण और मानसिक प्रताड़ना का सामना करने को विवश हो जाते हैं। आधुनिक जीवनशैली, बढ़ता व्यक्तिवाद, संयुक्त परिवारों का विघटन और सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन ने इस समस्या को और गंभीर बना दिया है। इसी वैश्विक चुनौती की ओर विश्व समुदाय का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रतिवर्ष 15 जून को विश्व वृद्ध दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया जाता है। यह दिवस केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि मानवता के अंतःकरण को झकझोरने वाला अवसर है। इसका उद्देश्य वृद्धजनों के विरुद्ध होने वाली हिंसा, उपेक्षा, आर्थिक शोषण और भावनात्मक उत्पीड़न के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा उनके सम्मान, सुरक्षा और गरिमा की रक्षा के लिए सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करना है। आज जब विश्व तेजी से वृद्ध समाज की ओर बढ़ रहा है, तब वृद्धजनों के अधिकारों की रक्षा केवल सामाजिक आवश्यकता नहीं, बल्कि नैतिक दायित्व और मानवीय उत्तरदायित्व भी बन गया है।

विश्व वृद्ध दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस

विश्व वृद्ध दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस की शुरुआत 2006 में हुई थी। इसका मूल उद्देश्य यह संदेश देना था कि वृद्धों के साथ होने वाला दुर्व्यवहार कोई व्यक्तिगत या पारिवारिक मामला मात्र नहीं, बल्कि एक गंभीर सामाजिक और मानवाधिकार संबंधी समस्या है। 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 जून को आधिकारिक रूप से विश्व वृद्ध दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस के रूप में मान्यता दी। इसके बाद से यह दिवस वैश्विक स्तर पर व्यापक रूप से मनाया जाने लगा। संयुक्त राष्ट्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं तथा नागरिक समाज संगठनों ने वृद्ध अधिकारों को मानवाधिकारों के व्यापक विमर्श का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह दिवस विश्व समुदाय को यह स्मरण कराता है कि वृद्धावस्था किसी व्यक्ति की उपयोगिता का अंत नहीं, बल्कि उसके जीवनानुभव की पराकाष्ठा है। इसलिए वृद्धजनों को सम्मान, सुरक्षा और गरिमापूर्ण जीवन उपलब्ध कराना प्रत्येक सभ्य समाज का कर्तव्य है। मानव जीवन को यदि ऋतुओं के रूपक में समझा जाए तो बाल्यावस्था वसंत है, युवावस्था ग्रीष्म है, प्रौढ़ावस्था शरद है और वृद्धावस्था जीवन की वह शांत गोधूलि है जिसमें अनुभवों का सूर्य अपनी स्वर्णिम आभा बिखेरता है। वृद्ध व्यक्ति वह पुस्तक है जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर जीवन के संघर्ष, सफलताएं, विफलताएं, त्याग और धैर्य की कहानियां अंकित होती हैं। उनके सफेद बाल केवल आयु का संकेत नहीं, बल्कि अनुभव के चांदी जैसे मुकुट हैं। उनके चेहरे की झुर्रियां समय की मार नहीं, बल्कि जीवन-यात्रा के मानचित्र हैं। भारतीय संस्कृति में बुजुर्गों को सदैव सम्मान का स्थान प्राप्त रहा है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है-'अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्॥ अर्थात जो व्यक्ति बड़ों का सम्मान करता है और उनकी सेवा करता है, उसकी आयु, विद्या, यश और बल में वृद्धि होती है। इस दृष्टि से वृद्धजनों का सम्मान केवल सामाजिक कर्तव्य नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्य भी है।

विश्व वृद्ध दुर्व्यवहार जागरुकता दिवस की शुरुआत 2006 में हुई थी, इसका मूल उद्देश्य यह संदेश देना था कि वृद्धों के साथ होने वाला दुर्व्यवहार कोई व्यक्तिगत या पारिवारिक मामला मात्र नहीं, बल्कि एक गंभीर सामाजिक और मानवाधिकार संबंधी समस्या है, 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 जून को आधिकारिक रूप से विश्व वृद्ध दुर्व्यवहार जागरुकता दिवस के रूप में मान्यता दी।

वृद्ध दुर्व्यवहार की अवधारणा

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किसी विश्वासपूर्ण संबंध में किया गया ऐसा कार्य या उपेक्षा, जिससे वृद्ध व्यक्ति को हानि, पीड़ा अथवा कष्ट पहुंचे, वृद्ध दुर्व्यवहार कहलाता है। यह दुर्व्यवहार केवल शारीरिक हिंसा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके अनेक रूप हैं जो अक्सर दिखाई भी नहीं देते। शारीरिक हिंसा मारपीट करना, धक्का देना, चोट पहुंचाना, भोजन या दवाओं से वंचित रखना अथवा किसी प्रकार की शारीरिक प्रताड़ना देना। अपमान करना, तिरस्कार करना, डराना, धमकाना, निर्णय प्रक्रिया से अलग रखना या निरंतर मानसिक दबाव बनाना। वृद्ध व्यक्ति की संपत्ति, पेंशन, बैंक खाते या आर्थिक संसाधनों का उसकी इच्छा के विरुद्ध उपयोग करना। आवश्यक भोजन, दवा, स्वास्थ्य सेवाएं या भावनात्मक सहयोग न देना। वृद्ध व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध किसी भी प्रकार का यौन व्यवहार। ऑनलाइन धोखाधड़ी, बैंकिंग फ्रॉड, पहचान की चोरी और साइबर अपराधों के माध्यम से आर्थिक हानि पहुंचाना। इनमें से सबसे अधिक पीड़ादायक अक्सर वह दुर्व्यवहार होता है जो दिखाई नहीं देता, अर्थात उपेक्षा, अकेलापन और भावनात्मक तिरस्कार।

बढ़ती वृद्ध आबादी और चुनौतियां

विश्व तेजी से वृद्ध समाज की ओर अग्रसर है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, पोषण स्तर में वृद्धि और चिकित्सा प्रौद्योगिकी के विकास के कारण जीवन प्रत्याशा लगातार बढ़ रही है। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार 2050 तक विश्व में 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की संख्या लगभग 2 अरब तक पहुंच सकती है। यह परिवर्तन अवसर भी है और चुनौती भी। एक ओर अनुभवी जनशक्ति और सामाजिक ज्ञान का विशाल भंडार उपलब्ध होगा, वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य सेवाओं, सामाजिक सुरक्षा और देखभाल की मांग भी बढ़ेगी। विभिन्न अंतरराष्ट्रीय अध्ययनों से संकेत मिलता है कि विश्वभर में लगभग प्रत्येक छह वृद्धों में से एक किसी न किसी प्रकार के दुर्व्यवहार का शिकार होता है। वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है क्योंकि अधिकांश मामले सामाजिक भय, पारिवारिक दबाव या निर्भरता के कारण सामने ही नहीं आते। कोविड-19 महामारी के दौरान सामाजिक अलगाव, आर्थिक संकट और स्वास्थ्य संबंधी असुरक्षाओं ने वृद्धजनों की समस्याओं को और अधिक गंभीर बना दिया। इससे यह स्पष्ट हुआ कि वृद्धजनों की सुरक्षा और सम्मान के लिए केवल परिवार नहीं, बल्कि व्यापक सामाजिक व्यवस्था की आवश्यकता है।

भारत में वृद्धजनों की स्थिति

भारत परंपरागत रूप से बुजुर्गों के सम्मान की संस्कृति वाला देश रहा है। यहां माता-पिता और गुरु को देवतुल्य माना गया है। पर बदलती सामाजिक परिस्थितियों ने वृद्धजनों के जीवन को नई चुनौतियों के सामने खड़ा कर दिया है। तेजी से बढ़ता शहरीकरण, रोजगार के लिए प्रवासन, एकल परिवारों का विस्तार तथा उपभोक्तावादी जीवन शैली ने पारंपरिक पारिवारिक संरचनाओं को प्रभावित किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में वृद्धजन स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और आर्थिक निर्भरता से जूझ रहे हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में अकेलापन, सामाजिक अलगाव और मानसिक तनाव बड़ी समस्याएं बनकर उभरे हैं। आज अनेक वृद्ध अपने ही घरों में स्वयं को अनावश्यक और उपेक्षित महसूस करते हैं। यह स्थिति केवल सामाजिक नहीं, बल्कि भावनात्मक संकट का भी संकेत है। वृद्ध दुर्व्यवहार किसी एक कारण का परिणाम नहीं है। इसके पीछे अनेक सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारक हैं। संयुक्त परिवारों के विघटन ने वृद्धों के सामाजिक संरक्षण को कमजोर किया है। जो वृद्ध आर्थिक रूप से दूसरों पर निर्भर होते हैं, उनके शोषण की संभावना अधिक होती है। भूमि, मकान और संपत्ति संबंधी विवाद अनेक बार पारिवारिक तनाव और उत्पीड़न का कारण बनते हैं। विचारों, जीवनशैली और तकनीकी समझ में अंतर संवादहीनता को जन्म देता है। जब रिश्तों का मूल्य उपयोगिता और लाभ से तय होने लगता है, तब वृद्धों को बोझ समझे जाने का खतरा बढ़ जाता है। अकेलापन वृद्धजनों को मानसिक रूप से कमजोर बना देता है और वे शोषण के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं।

वृद्धजनों की सुरक्षा और सम्मान का सबसे प्रभावी माध्यम परिवार है, परिवारों को चाहिए कि वे बुजुर्गों को सम्मानजनक वातावरण प्रदान करें, उनकी भावनाओं और आवश्यकताओं को समझें, निर्णय प्रक्रिया में उन्हें शामिल करें, नियमित संवाद बनाए रखें, उनके अनुभवों का सम्मान करें।

वृद्ध महिलाएं स्थिति चिंताजनक

वृद्ध महिलाओं की स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक है। वे आयु और लिंग दोनों आधारों पर भेदभाव का सामना करती हैं। विधवा महिलाओं को अक्सर संपत्ति अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। कई बार उन्हें परिवार के निर्णयों से अलग कर दिया जाता है और आर्थिक संसाधनों पर उनका नियंत्रण समाप्त हो जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में अशिक्षा, आर्थिक निर्भरता और सामाजिक रूढ़ियां उनकी समस्याओं को और बढ़ा देती हैं। इसलिए वृद्ध महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए विशेष नीतिगत उपायों की आवश्यकता है। भारत में वृद्धजनों की सुरक्षा के लिए अनेक कानूनी और नीतिगत प्रावधान किए गए हैं। माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 इस कानून के अंतर्गत संतान को माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालांकि वृद्ध दुर्व्यवहार की समस्या का समाधान केवल कानूनों से संभव नहीं है। इसके लिए बहुआयामी दृष्टिकोण आवश्यक है। वृद्धजनों की सुरक्षा और सम्मान का सबसे प्रभावी माध्यम परिवार है। परिवारों को चाहिए कि वे बुजुर्गों को सम्मानजनक वातावरण प्रदान करें। उनकी भावनाओं और आवश्यकताओं को समझें। निर्णय प्रक्रिया में उन्हें शामिल करें। नियमित संवाद बनाए रखें। उनके अनुभवों का सम्मान करें। जब परिवार में सम्मान और संवाद का वातावरण होता है, तब वृद्धावस्था बोझ नहीं, बल्कि प्रेरणा का स्रोत बन जाती है।

सफल पहलें और प्रेरक उदाहरण

विश्व के अनेक देशों ने आयु-अनुकूल समाज की अवधारणा को सफलतापूर्वक विकसित किया है। सामुदायिक देखभाल मॉडल, वरिष्ठ नागरिक क्लब, डे-केयर केंद्र, टेलीमेडिसिन सेवाएं, आपातकालीन सहायता प्रणालियां, सक्रिय वृद्धावस्था कार्यक्रम। ये पहल यह सिद्ध करती हैं कि यदि समाज इच्छाशक्ति और संवेदनशीलता के साथ कार्य करे तो वृद्धावस्था को सुरक्षित, सम्मानजनक और सक्रिय बनाया जा सकता है। 2050 तक भारत और विश्व दोनों में वृद्ध आबादी उल्लेखनीय रूप से बढ़ेगी। ऐसे में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार, सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवाएं, चिकित्सा का विकास, डिजिटल और वित्तीय साक्षरता, आयु-अनुकूल शहरों का निर्माण, अंतरपीढ़ी संवाद को प्रोत्साहन, वृद्ध अधिकारों के प्रति सामाजिक जागरूकता। भविष्य का सफल समाज वही होगा जो अपने वृद्ध नागरिकों को विकास प्रक्रिया के केंद्र में स्थान देगा। वृद्धजन किसी राष्ट्र की सांस्कृतिक स्मृति, नैतिक चेतना और जीवनानुभव के अमूल्य भंडार होते हैं। वे केवल अतीत की कहानियां नहीं, बल्कि भविष्य के लिए दिशा-सूचक दीपक हैं। जिस समाज में वृद्धों का सम्मान होता है, वहां संवेदनशीलता, करुणा और मानवीयता जीवित रहती है। विश्व वृद्ध दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस हमें यह स्मरण कराता है कि वृद्ध दुर्व्यवहार केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक समस्या नहीं, बल्कि एक गंभीर सामाजिक और मानवाधिकार संबंधी प्रश्न है। इसके समाधान के लिए सरकार, समाज, परिवार और प्रत्येक नागरिक को अपनी भूमिका निभानी होगी। जीवन की ढलती सांझ को अंधकार नहीं, बल्कि सम्मान और स्नेह के दीपों से आलोकित किया जाना चाहिए। यदि उगते सूरज को प्रणाम करना हमारी संस्कृति है, तो डूबते सूर्य की गरिमा को नमन करना भी हमारा कर्तव्य है।

साभार

विश्लेषण

मोदी के भारत की नई उड़ान

1.45 लाख किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण, लगभग 3000 किलोमीटर आधुनिक एक्सप्रेसवे, 164 वंदे भारत ट्रेनों का संचालन तथा देश में हवाई अड्डों के तीव्र विस्तार ने यह संकेत दिया है कि आधुनिक शासन व्यवस्था में केवल आर्थिक परिसंपत्ति नहीं बल्कि सामाजिक एकीकरण और राष्ट्रीय एकात्मता का माध्यम भी है।

प्रो.डीएस फर्स्वान
निदेशक शिक्षाशास्त्र

राष्ट्र केवल भौगोलिक सीमाओं से निर्मित नहीं होते और न ही उनका निर्माण समय के प्रवाह से होता है। किसी भी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति इस बात में निहित होती है कि उसकी शासन व्यवस्था जन-आकांक्षाओं को किस सीमा तक लोकहितकारी परिणामों में बदल पाती है। लोकतंत्र में चुनाव यह निर्धारित करते हैं कि शासन कौन करेगा? किंतु प्रशासनिक दक्षता यह निर्धारित करती है कि शासन को जनस्वीकृति और नैतिक वैधता किस स्तर तक प्राप्त होगी? ऐसे समय में जब भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 12 वर्षों की शासन यात्रा तथा उनके लगातार तीसरे कार्यकाल की निरंतरता का साक्षी है, तब यह अवसर केवल राजनीतिक समीक्षा का नहीं बल्कि भारतीय लोक प्रशासन की बदलती प्रकृति और राज्य की संस्थागत क्षमता के गंभीर विश्लेषण का है। लोक प्रशासन के अध्ययन में पिछले एक दशक की सबसे महत्वपूर्ण भारत की कार्यसंस्कृति में आया परिवर्तन है। पारंपरिक 'कल्याणकारी वितरण तंत्र' से आगे बढ़ते हुए शासन व्यवस्था को प्रौद्योगिकी-आधारित, नागरिक-केंद्रित तथा विकासोन्मुख प्रशासनिक ढांचे में रूपांतरित करने का प्रयास इस कालखंड की प्रमुख पहचान बनकर उभरा है। सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक विकास को परस्पर विरोधी न मानकर उन्हें प्रशासनिक दक्षता और आधारभूत संरचना निर्माण के साथ जोड़ना इस मॉडल का मूल तत्व रहा है। भारतीय शासन व्यवस्था में ये परिवर्तन लोक प्रशासन के पारंपरिक 'वेलफेयर स्टेट' मॉडल से आगे बढ़कर 'डेवलपमेंटल स्टेट' तथा 'न्यू पब्लिक गवर्नेंस' की धारणा की ओर संक्रमण का संकेत देता है। इस दृष्टिकोण में देश सिर्फ सेवाओं का प्रदाता नहीं रहता बल्कि नागरिक, बाजार और सामुदायिक संस्थाओं के बीच एक समन्वयकारी तंत्र के रूप में कार्य करता है। जनभागीदारी, डिजिटल प्रौद्योगिकी, परिणाम-आधारित प्रशासन तथा बहु-हितधारक सहयोग की धारणा इसी परिवर्तनशील प्रशासनिक प्रतिमान की अभिव्यक्ति हैं।

अंत्योदय का प्रभावी क्रियान्वयन

भारतीय संदर्भ में यह मॉडल प्रशासन को केवल नियंत्रणकारी संरचना न मानकर विकास के उत्प्रेरक के रूप में स्थापित करने का प्रयास प्रतीत होता है। यदि इस परिवर्तन को किसी एक कसौटी पर परखा जाए, तो वह है सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों का विस्तार। लगभग 80 करोड़ नागरिकों को निःशुल्क खाद्यान्न सहायता, लगभग 50 करोड़ लोगों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा कवच, 10 करोड़ से अधिक परिवारों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने की पहल तथा चार करोड़ से अधिक निर्धन परिवारों को स्थाई आवास उपलब्ध कराना केवल कल्याणकारी योजनाएं नहीं हैं, बल्कि वे अंत्योदय के उस प्रशासनिक दर्शन का विस्तार हैं जिसमें विकास का अंतिम लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का संकल्प निहित है। लोक प्रशासन के सिद्धांत यह स्वीकार करते हैं कि किसी भी कल्याणकारी राज्य की सफलता केवल नीति-निर्माण पर नहीं बल्कि उसके प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली तथा डिजिटल वित्तीय तंत्र के विस्तार ने सार्वजनिक संसाधनों के वितरण में पारदर्शिता बढ़ाई है और प्रशासनिक अपव्यय को सीमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके समानांतर आधारभूत संरचना के क्षेत्र में हुए निवेश ने भारतीय विकास प्रशासन को नई दिशा प्रदान की है।

सिस्टम से जटिलता कम हुई

1.45 लाख किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण, लगभग 3000 किलोमीटर आधुनिक एक्सप्रेसवे, 164 वंदे भारत ट्रेनों का संचालन तथा देश में हवाई अड्डों के तीव्र विस्तार ने यह संकेत दिया है कि आधुनिक शासन व्यवस्था में केवल आर्थिक परिसंपत्ति नहीं बल्कि सामाजिक एकीकरण और राष्ट्रीय एकात्मता का माध्यम भी है।प्रशासन के विद्वान लंबे समय से इस तथ्य पर बल देते रहे हैं कि बेहतर संपर्क व्यवस्थाक्षेत्रीय विषमताओं को कम करती है और विकास के अवसरों का अधिक न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करती है। भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था का डिजिटाइजेशन इस कालखंड की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जा सकता है। डिजिटल गवर्नेंस का मूल उद्देश्य नागरिक और शासन के बीच की दूरी को कम करना है। आज भारत विश्व की सबसे बड़ी रियल टाइम डिजिटल पेमेंट का संचालन कर रहा है, जहां यूपीआई के माध्यम से 24,162 करोड़ से अधिक लेनदेन, लगभग 314 लाख करोड़ रुपये के मूल्य के साथ हुए हैं। इसी प्रकार आयकर रिटर्न के निस्तारण की औसत अवधि 93 दिनों से घटकर लगभग 10 दिन होना, कंपनियों के स्ट्राइक-ऑफ की प्रक्रिया का 499 दिनों से घटकर 60 दिन रह जाना तथा फास्टैग व्यवस्था के कारण टोल प्लाजा पर प्रतीक्षा समय का लगभग 47 सेकंड तक सीमित हो जाना प्रशासनिक प्रक्रियाओं में दक्षता और समयबद्धता के नए मानक स्थापित करता है। ये परिवर्तन छोटे अवश्य प्रतीत होते हैं, किंतु व्यापक दृष्टि से देखें तो ये नागरिकों और उद्यमों दोनों की लेनदेन लागत को कम करने वाले महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार हैं। यदि सुशासन के स्वीकृत मानकों, जैसे पारदर्शिता, जवाबदेही, प्रशासनिक दक्षता, सहभागिता तथा समयबद्ध सर्विस के आधार पर मूल्यांकन किया जाए, तो डिजिटल प्रशासन की इन पहलों ने शासन की प्रक्रियात्मक जटिलताओं को कम करने का प्रयास किया है।

80 करोड़ नागरिकों को निःशुल्क खाद्यान्न सहायता, 50 करोड़ लोगों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा कवच, 10 करोड़ से अधिक परिवारों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने की पहल तथा चार करोड़ से अधिक निर्धन परिवारों को स्थाई आवास उपलब्ध कराना केवल कल्याणकारी योजनाएं नहीं हैं, बल्कि ये अंत्योदय के प्रशासनिक दर्शन का विस्तार है।

विकास की रणनीति

लोक प्रशासन के विद्वान लंबे समय से यह प्रतिपादित करते रहे हैं कि प्रभावी शासन का अर्थ केवल अधिक व्यय करना नहीं है बल्कि न्यूनतम प्रशासनिक लागत पर अधिकतम सार्वजनिक मूल्य का सृजन करना है। इस दृष्टि से सेवा वितरण तंत्र में आई गति और सरलता प्रशासनिक पूंजी के अधिक उत्पादक उपयोग का संकेत देती है। आर्थिक प्रशासन के क्षेत्र में भारत ने अपनी विकास रणनीति को नए सिरे से परिभाषित किया है। वर्ष 2013-14 के लगभग 466 अरब डॉलर के निर्यात से बढ़कर 2025-26 में लगभग 866 अरब डॉलर तक पहुंचना, इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात का 6.3 अरब डॉलर से बढ़कर 48 अरब डॉलर होना, मोबाइल फोन निर्यात का लगभग 16 करोड़ रुपये से बढ़कर 2.6 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचना तथा विनिर्माण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का लगभग 165 अरब डॉलर तक पहुंचना इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि भारत वैश्विक उत्पादन श्रृंखलाओं में अपनी भूमिका को सुदृढ़ करने की दिशा में अग्रसर है। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से 20.41 लाख करोड़ रुपये से अधिक का उत्पादन, लगभग 2.16 लाख करोड़ रुपये का निवेश और 14 लाख से अधिक रोजगार सृजन इस बात का प्रमाण है कि औद्योगिक नीति और प्रशासनिक सुगमता को एकीकृत करने का प्रयास किया गया है। उद्यमिता और नवाचार के क्षेत्र में भी संस्थागत परिवर्तन साफ दिखाई देते हैं। 100 से अधिक यूनिकॉर्न कंपनियों वाला भारत आज विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है, जिसने 23 लाख से अधिक रोजगारों का सृजन किया है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का 81वें स्थान से 38वें स्थान तक पहुंचना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता कौशल और क्लाउड अवसंरचना के क्षेत्र में वैश्विक उपस्थिति यह संकेत देती है कि शासन व्यवस्था नवाचार को केवल निजी क्षेत्र की गतिविधि न मानकर राष्ट्रीय विकास की सार्वजनिक संपदा के रूप में देखने लगी है। पर्यावरणीय प्रशासन के क्षेत्र में भी एक नई कार्यसंस्कृति विकसित हुई है। वर्ष 2014 में 2.82 गीगावाट की सौर ऊर्जा क्षमता को बढ़कर 2026 में 150 गीगावाट तक पहुंचना, 100 रामसर स्थलों का विकास, मैंग्रोव पुनर्स्थापन, 262 करोड़ पौधों का रोपण, सात दशकों के बाद चीतों की पुनर्स्थापना जैसे प्रयास यह दर्शाते हैं कि विकास और पर्यावरण संरक्षण को संतुलित रूप से आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है।

जनविश्वास की कसौटी

लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रशासनिक उपलब्धियों की अंतिम कसौटी जनविश्वास होता है। भारत जैसे बहुलतावादी और विविधतापूर्ण देश में लगातार तीन बार स्पष्ट जनादेश प्राप्त होना केवल चुनावी प्रबंधन का परिणाम नहीं माना जा सकता है। यह उस व्यापक धारणा का भी द्योतक है जिसमें नागरिक अपने जीवन में अनुभव किए

लोक प्रशासन की दृष्टि से पिछले 12 वर्षों का आकलन किया जाए, तो यह कालखंड भारत को अधिक सक्षम, उत्तरदायी और सहभागी बनाने के सतत प्रयासों का काल प्रतीत होता है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की अवधारणा ने विकास को समाज के व्यापक वर्गों से जोड़ने का प्रयास किया है।

गए बदलाव को शासन की कार्यक्षमता व नेतृत्व की दिशा से जोड़कर देखते हैं। लोकतांत्रिक निरंतरता इस अर्थ में प्रशासनिक स्वीकार्यता का भी एक रूप है। भारतीय प्रशासनिक चिंतन की परंपरा में शासन का आदर्श केवल विधिक अधिकारिता पर आधारित नहीं रहा है बल्कि लोकमंगल, राजधर्म और प्रजाहित की नैतिक अवधारणाओं से भी प्रेरित रहा है। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब प्रशासनिक दक्षता सामाजिक न्याय, समावेशन और नागरिक गरिमा के साथ समन्वित होती है, तब शासन की वैधता केवल संवैधानिक प्रक्रिया तक सीमित नहीं रहती बल्कि वह सामाजिक विश्वास की पूंजी में भी बदल जाती है। लोक प्रशासन के समकालीन विमर्श में राज्य की क्षमता को किसी भी राष्ट्र के दीर्घकालिक विकास का केंद्रीय निर्धारक माना जाता है। राज्य की क्षमता का आशय केवल कानून लागू करने की शक्ति से नहीं वरन संसाधनों के प्रभावी व सतत पोषणीय प्रबंधन, त्वरित निर्णय-निर्माण, व्यापक सेवा वितरण तथा संकट की परिस्थितियों में संस्थागत प्रत्युत्तर देने की योग्यता से है। बीते वर्षों में डिजिटल अवसंरचना, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, कर प्रशासन के आधुनिकीकरण, आधारभूत संरचना विस्तार तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के व्यापक क्रियान्वयन ने भारत की क्षमता को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण संकेत दिए हैं। निस्संदेह लोकतंत्र में कोई भी सरकार आलोचना से परे नहीं हो सकती और प्रत्येक शासन व्यवस्था को उत्तरदायित्व, समीक्षा और सतत सुधार के लिए तैयार रहना चाहिए। एक निष्पक्ष लोक प्रशासनिक विश्लेषण यह स्वीकार करने से इंकार नहीं कर सकता कि पिछले बारह वर्षों में भारत की कार्यक्षमता, तकनीकी सामर्थ्य, सेवा वितरण क्षमता और संस्थागत विस्तार में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।

रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म

कल्याणकारी कार्यक्रमों, आधारभूत संरचना, डिजिटल नवाचार और प्रशासनिक सुधारों के समन्वय ने देश और नागरिक के संबंधों को नए सिरे से परिभाषित किया है। इतिहास अंततः व्यक्तियों का नहीं अपितु उनके द्वारा निर्मित प्रशासनिक परंपराओं और राष्ट्रीय संस्थाओं का मूल्यांकन करता है। यदि लोक प्रशासन की दृष्टि से पिछले 12 वर्षों का आकलन किया जाए, तो यह कालखंड भारत को अधिक सक्षम, उत्तरदायी और सहभागी बनाने के सतत प्रयासों का काल प्रतीत होता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की अवधारणा ने विकास को समाज के व्यापक वर्गों से जोड़ने का प्रयास किया है, वहीं न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन ने प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल, प्रौद्योगिकी-सक्षम और परिणामोन्मुख बनाने की दिशा दी है। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का सूत्र शासन को स्थिरता से गतिशीलता की ओर ले जाने का प्रयास है, जबकि प्रौद्योगिकी के लोकतंत्रीकरण ने डिजिटल सेवाओं, वित्तीय समावेशन और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से राज्य और नागरिक के बीच की दूरी को अभूतपूर्व रूप से कम किया है। सामाजिक समावेशन, महिला सशक्तिकरण, अंत्योदय, जनभागीदारी और आत्मनिर्भरता के विविध आयामों को यदि एक व्यापक प्रशासनिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, तो वे विकसित भारत की संस्थागत आधारशिला के रूप में उभरते हैं। यदि परम वैभवशाली भारत, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय संकल्प को एक दीर्घकालिक प्रशासनिक योजना के रूप में देखा जाए, तो उसका मूल उद्देश्य एक ऐसे भारत का निर्माण है जहां विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। संभवतः यही उस शासन-दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता है जिसने राष्ट्र प्रथम की भावना को लोक प्रशासन के व्यवहारिक स्वरूप से जोड़ते हुए सेवा, सुशासन और समावेशी विकास को 21वीं सदी के भारत के प्रशासनिक विमर्श के केंद्र में स्थापित करने का प्रयास किया है।

उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी

पीओके व पाक में टकराव

1974 में पीओके को अपना राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विधानसभा देने का औपचारिक ऐलान किया, लेकिन असल में पाकिस्तानी सरकार और सेना ही यहां के फैसलों को नियंत्रित करती है, पीओके में पाकिस्तानी करेंसी ही चलती है, पीओके में चुनाव होते हैं, सरकार बनती है लेकिन असली ताकत पाकिस्तान की सेना और इस्लामाबाद के हाथ में रहती है।

उत्तरांचल दीप डेस्क

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में दशकों की पीड़ा, दमन, भारी टैक्स, और बुनियादी सुविधाओं के अभाव से उपजा वो जन-आक्रोश है, जो अब पाकिस्तानी सेना और हुकूमत के खिलाफ खुले विद्रोह में बदल चुका है। बिजली की बेहिसाब बढ़ी हुई कीमतों, आटे की कीमतों में वृद्धि और भारी टैक्स के खिलाफ संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी (जेएएसी) के बैनर तले डेढ़ लाख से अधिक कश्मीरी सड़कों पर उतर गए। किंतु शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को कुचलने के लिए पाकिस्तानी रेंजर्स और सेना ने अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें रावलकोट और मुजफ्फराबाद में 60 से अधिक लोग मारे गए हैं और 200 से ज्यादा घायल हुए। पूरे पीओके में कहा जाए तो कम से कम 100 बेकसूर लोगों की जान जा चुकी है। बड़ी संख्या में लोग घायल हैं। लेकिन जेएएसी के नेता अपनी मांगों पर डटे हुए है। वो सेना के जुल्मों का हिसाब चुकता करने का ऐलान कर चुके हैं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोग अपनी जमीन से लेकर विदेशों तक पाकिस्तान से अलग होने की मांग को लेकर उठ खड़े हुए हैं। आखिर क्यों वो खुद को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानते हैं? इसलिए पीओके अपने हाल के इतिहास के सबसे उथल-पुथल भरे दौर से गुजर रहा है। संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी (जेएएसी) के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी पाकिस्तान की सेना और स्थापना पर राजनीतिक दखल अंदाजी, आर्थिक उपेक्षा और स्थानीय लोगों की आवाजों को दबाने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन एक बुनियादी सवाल फिर से उठ रहा है कि अगर पीओके पाकिस्तान के नियंत्रण में है, तो फिर वहां अलग प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विधानसभा, अपना संविधान, अपनी अदालतें और अपना अलग झंडा क्यों है? हालांकि पीओके दो हिस्सों में बंटा हुआ है, ये पूरा इलाका 90,972 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आजाद जम्मू-कश्मीर 13,297 वर्ग किलोमीटर में है तो गिलगित-बल्टिस्तान 72,495 वर्ग किलोमीटर में है।

पीओके कितना आजाद है?

पाकिस्तान में पीओके को आधिकारिक तौर पर आजाद जम्मू और कश्मीर कहता है। यहां अपना राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विधानसभा, अदालतें और संवैधानिक ढांचा है। पहली नजर में यह एक स्वशासित इकाई जैसा लगता है, लेकिन हकीकत कुछ और है। 1947 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। पाकिस्तान ने इसे कभी भी अपना पूर्ण प्रांत नहीं बनाया। अगर वह ऐसा करता तो कश्मीर मुद्दे पर उसकी अंतरराष्ट्रीय स्थिति कमजोर हो जाती। इसलिए पाकिस्तान ने एक अलग प्रशासनिक ढांचा बनाया, ताकि दुनिया के सामने यह दिखा सके कि पीओके एक स्वायत्त क्षेत्र है। 1974 में इंटरिम संविधान एक्ट लाया गया, जिसने पीओके को अपना राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विधानसभा देने का औपचारिक ऐलान किया। लेकिन असल में पाकिस्तान की केंद्र सरकार और सेना ही यहां के फैसलों को नियंत्रित करती है। पीओके में पाकिस्तानी करेंसी ही चलती है। पीओके में चुनाव होते हैं, सरकार बनती है लेकिन असली ताकत पाकिस्तान की सेना और इस्लामाबाद के हाथ में रहती है। कश्मीर काउंसिल नाम की संस्था पाकिस्तान को पीओके के मामलों में सीधा हस्तक्षेप करने का अधिकार देती है। एक और विवादास्पद व्यवस्था यह है कि पीओके की विधानसभा में 12 सीटें उन कश्मीरियों के लिए आरक्षित हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं। ये सीटें पीओके के निवासियों के मतदान से नहीं, बल्कि पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के मत से भरी जाती हैं। इससे इस्लामाबाद को चुनावी नतीजों पर अतिरिक्त प्रभाव बनाने का मौका मिलता है। पीओके के राजनीतिज्ञों, जजों और संवैधानिक पदों पर आसीन अधिकारियों को शपथ लेनी पड़ती है कि वे कश्मीर के पाकिस्तान में विलय का समर्थन करेंगे। इससे जो लोग पाकिस्तान के पक्ष में नहीं हैं, उन्हें राजनीति में आने का मौका ही नहीं मिलता। इसलिए पीओके के लोगों को लगता है कि वे न तो पूर्ण रूप से पाकिस्तानी हैं और न ही स्वतंत्र मुल्क के वाशिंदे हैं। वे पाकिस्तान की छाया में फंसे हुए हैं, जहां न तो उन्हें असली आजादी है और न ही पूर्ण अधिकार है। पीओके का यह अनोखा राजनीतिक मॉडल पाकिस्तान की कश्मीर नीति की दोहरी चाल है। एक तरफ वह दुनिया को बताता है कि पीओके आजाद है, दूसरी तरफ वहां की हर महत्वपूर्ण शक्ति और संसाधनों पर पाकिस्तान का कब्जा है।

जब तक पाकिस्तान पीओके को हकीकत में स्वायत्तता नहीं देता, तब तक पीओके में अशांति और असंतोष जारी रहेगा। शायद इसलिए पीओके के लोगों ने अपने हकों के लिए लड़ाई शुरू की है। पाकिस्तान भी पीओके के लोगों को आसानी से आजादी देने वाला नहीं है। हालांकि पाकिस्तान आधिकारिक तौर पर पीओके को अपने भूभाग का हिस्सा नहीं मानता। पाकिस्तान के संविधान में सिर्फ चार प्रांतों पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का उल्लेख है। इस सूची में आजाद कश्मीर का नाम कहीं नहीं है। पाकिस्तान की संसद में भी इसका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 257 में कहा गया है कि यदि जम्मू और कश्मीर के लोग पाकिस्तान में शामिल होने का विकल्प चुनते हैं, तो उस संबंध में शर्तें उनकी इच्छा के अनुसार निर्धारित की जाएंगी।

मई 2024 में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि भारत, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर अपना दावा कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन इसे बलपूर्वक अपने कब्जे में करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि वहां की जनता भारत के हिस्से वाले जम्मू-कश्मीर में विकास देखने के बाद स्वयं भारत में शामिल होना चाहेगी।

पीओके के संसाधनों की लूट

पीओके संसाधनों के मामले में समृद्ध है और पाकिस्तान इस क्षेत्र से रणनीतिक तथा आर्थिक रूप से काफी लाभ उठाता है, जबकि बदले में सीमित विकास ही करता है। यह क्षेत्र सिंधु नदी के शीर्ष पर स्थित है और जलविद्युत क्षमता, वनों और खनिजों से समृद्ध है, जिनमें ग्रेफाइट, बेंटोनाइट, लिमोनाइट, संगमरमर और रत्न शामिल हैं। आंकड़ों की बात करें तो पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों में कृषि के लिए उपयोग होने वाले सिंचाई जल का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा पीओके से ही मिलता है। इस क्षेत्र के पानी से पनबिजली पाकिस्तान की कुल बिजली आपूर्ति का 10 से 15 प्रतिशत हिस्सा है। हालांकि पीओके के लोगों की लंबे समय से शिकायत है कि इन संसाधनों का दोहन पाकिस्तान करता है लेकिन पीओके के लोगों को आर्थिक रूप से कोई खास लाभ नहीं मिलता। पीओके की हालत कितनी खराब है ये एक अध्ययन से सामने आया। पीओके की लगभग दो-तिहाई आबादी, यानी लगभग 66 प्रतिशत आबादी अपनी आजीविका के लिए खेती और पशुपालन पर निर्भर है। लगभग 29 प्रतिशत पीओके के निवासी कुपोषण का शिकार हैं, जो पाकिस्तान के राष्ट्रीय औसत का 19.9 प्रतिशत से अधिक है। पीओके 57.1 प्रतिशत निवासी किसी न किसी स्तर की खाद्य असुरक्षा का सामना करते हैं, जो पाकिस्तान के राष्ट्रीय औसत के 58 प्रतिशत के बराबर है। हालांकि, इस क्षेत्र के पहाड़ी इलाकों में यह आंकड़ा बढ़कर 90 प्रतिशत परिवारों तक पहुंच जाता है। इसलिए आम तौर पर पाकिस्तान की पैरवी करने वाले जम्मू-कश्मीर के बड़े नेता और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारुक अब्दुल्ला ने इस मामले पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा, कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहा है। वहां अत्याचार हो रहे हैं, अब तक बहुत सारे लोग शहीद हो चुके हैं। मैं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से अपील करूंगा कि वह वहां जाकर देखे कि उन लोगों पर क्या मुसीबतें टूट रही हैं।

पीओके के नेताओं, जजों और संवैधानिक पदों पर आसीन अफसर शपथ लेते हैं कि वे कश्मीर के पाक में विलय का समर्थन करेंगे, इससे जो लोग पाकिस्तान के पक्ष में नहीं हैं, उन्हें राजनीति में आने का मौका नहीं मिलता, लिहाजा पीओके के लोगों को लगता है कि वे न तो पूरे पाकिस्तानी हैं और न ही स्वतंत्र मुल्क के वाशिंदे हैं, वे पाकिस्तान में फंसे हुए हैं, जहां न तो असली आजादी है और न ही पूर्ण अधिकार है।

क्या पीओके फिसल रहा है?

बुनियादी सुविधाओं के अभाव के कारण पीओके के नागरिक पाकिस्तान के कुशासन से तंग आ चुके हैं। कई रिपोर्टों और बयानों में यह दावा किया जाता रहा है कि पीओके की जनता पाकिस्तान से आजादी चाहती है और वो भारत की ओर देख रही हैं। मई 2024 में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा था कि भारत, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) पर अपना दावा कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन इसे बलपूर्वक अपने कब्जे में करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि वहां की जनता भारत के हिस्से वाले जम्मू-कश्मीर में विकास को देखने के बाद स्वयं भारत में शामिल होना चाहेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो बात दो साल पहले कही थी वो क्या पूरी होगी? भारत के सेना प्रमुख और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक पीओके को भारत का अभिन्न हिस्सा बता चुके हैं। भारतीय सेना प्रमुख कई मौको पर कह भी चुके हैं कि उन्हें सिर्फ सरकार के आदेश का इंतजार है। भारतीय सेना पीओके को भारत में शामिल करने के लिए तैयार है। ऐसे में क्या पाकिस्तान के हाथों से पीओके फिसल रहा है? क्या पाकिस्तानी हुकूमत और फौज ने पीओके को बर्बाद कर दिया है? क्या पीओके की आवाम वास्तव में विद्रोह को अंजाम तक पहुंचा कर रहेगी अथवा पाकिस्तानी हुकूमत और सेना के सामने सरेंडर कर देगी? इन तमाम सवालों के जवाब अभी मुश्किल है, लेकिन पीओके के आम लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। महंगाई, बेरोजगारी और बिजली बिलों से परेशान लाखों निहत्थे लोग सड़कों पर हैं और पाकिस्तानी सेना व रेंजर्स उन पर गोलियां बरसाई हैं। रावलकोट, गिलगिट-बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और मीरपुर क्षेत्र में हर तरफ सिर्फ चीखें सुनाई दी हैं। लिहाजा भारत ने कड़ा रुख अपनाते हुए यूएन से तत्काल पीओके में दखल देने की मांग की। क्योंकि भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों के मामलों में त्वरित प्रतिक्रिया देने वाली मानवाधिकार संस्थाएं पीओके में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न और दमन पर चुप रहती हैं। यह दोहरा मापदंड यूएन जैसी संस्थाओं को संदेह के दायरे में खड़ा करता है।

मानवाधिकार दी धज्जियां उड़ी

पीओके से सबसे डरावनी खबर ये है कि पाकिस्तानी सेना के तानाशाह फील्ड मार्शल आसीम मुनीर ने संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी (जेएएसी) के नेताओं को क्रश एंड एलिमिनेट (कुचलो और खत्म करो) के आदेश देकर साबित कर दिया है कि पाकिस्तान के लिए मानवाधिकार कोई मायने नहीं रखता। आसीम मुनीर ने पीओके में 14,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात कर लोगों को आतंकित करने की कोशिश भी की। जेएएसी के चार मुख्य नेताओं के सिर पर एक करोड़ पाकिस्तानी रुपये (करीब 30 लाख भारतीय रुपये) का इनाम रख दिया। मीडिया ब्लैकआउट कर दिया, न कोई टीवी चैनल, न इंटरनेट और न मोबाइल नेटवर्क। पीओके में सब बंद कर दिया गया है। यह वही पीओके है जिसे आजादी के बाद कबाइलियों की आड़ में पाकिस्तानी सेना ने हिंसा के बल पर जम्मू-कश्मीर के एक हिस्से पर धोखे से कब्जा कर लिया था। आलम ये है कि धर्म के नाम पर बना पाकिस्तान न तो खुद आगे बढ़ पाया और न ही उसने पीओके को आगे बढ़ने दिया। पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर यानी पीओके बार-बार आजादी की मांग करता रहता है, लेकिन वहां की सरकार और सेना लोगों आवाज को कुचल देती है। दो हिस्सों में बंटे पीओके का एक हिस्सा वो है जिसे आजाद कश्मीर कहा जाता है और दूसरा गिलगित-बल्टिस्तान है, लेकिन दोनों ही बर्बाद हो चुके हैं। आजाद कश्मीर के लोग तो आए दिन अपनी बुनियादी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हैं, लेकिन हर बार की तरह उन पर गोलियां चला दी जाती हैं। एक बार फिर पाकिस्तान की सेना ने अपने ही कब्जे वाले आजाद कश्मीर के लोगों पर गोलियां चलाई हैं। पाकिस्तानी सरकार और सेना बोलती है कि वह प्रदर्शनकारी नहीं, बल्कि मिलिटेंट (आतंकवादी) हैं। ●

सुकून मिलता है मालदेवता में

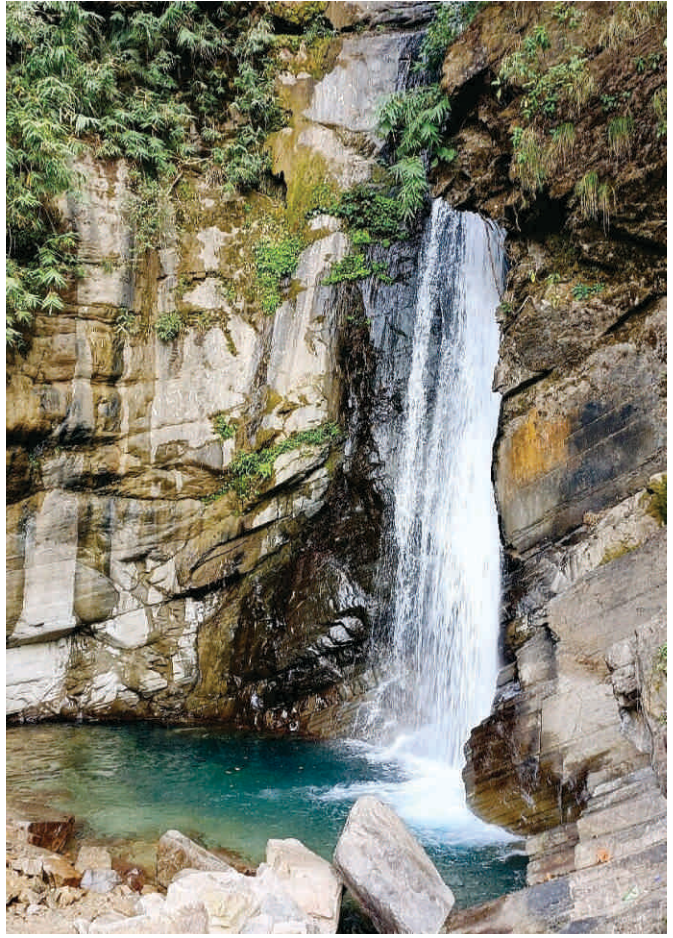

टूरिस्ट रोमांच के शौकीन हैं, तो तैराकी, बाइकिंग और साइकिलिंग जैसी गतिविधियों में हिस्सा लेकर अपनी यात्रा को और मजेदार बना सकते हैं, मालदेवता हर तरह के पर्यटकों को आकर्षित करता है, इसलिए चाहे आराम की तलाश है या फिर मनोरंजन की तलाश है यहां सभी की अपेक्षाएं पूरी होती है।

हरिश भट्ट
रामनगर

कुदरत ने उत्तराखंड को खूबसूरती से नवाजने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कुदरत ने इस पहाड़ी राज्य पर अपने अनमोल खजाने से खूबसूरत जी भर कर लुटाई है। हिमालय की गोद में बसा यह राज्य राजसी चोटियों, हरे-भरे बुग्यालों और शांत झीलों का अनूठा मनोरम संगम है। यह राज्य न सिर्फ शानदार स्कीइंग ढलानों और मिनी स्विट्जरलैंड जैसे नजारों के लिए दुनियाभर में मशहूर है, बल्कि तीर्थाटन के लिए देवों की भूमि है। यहां की हरी-भरी शांत वादियां हर किसी को आकर्षित करती हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से करीब 21 किलोमीटर के फासले पर मालदेवता मंदिर और गांव न सिर्फ पिकनिक स्पॉट है बल्कि शांत और सुरम्य टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, जहां से प्रकृति की भरपूर छटा देखने को मिलती है। गांव की पृष्ठभूमि में हरे-भरे हिमालय की भव्यता दिखाई देती है। प्रकृति प्रेमियों के लिए यह एक बेहतरीन डेस्टिनेशन हो सकता है, जहां वो शांति से कुछ समय बिता सकते हैं। शहर की भागदौड़ से दूर मालदेवता गांव की यात्रा जीवन भर के लिए अविस्मरणीय बन सकती है। मालदेवता में टहलते हुए पक्षियों की चहचहाहट का आनंद लिया जा सकता है। घनी झाड़ियों के बीच बहती खूबसूरत नदी इस पर्यटन स्थल की मुख्य विशेषता कही जा सकती है। सैलानी नदी किनारे बैठकर घंटों तक प्रकृति की गोद में होने का अहसास कर सकते हैं खुद को तरोताजा कर सकते हैं। यदि टूरिस्ट रोमांच के शौकीन हैं, तो तैराकी, बाइकिंग और साइकिलिंग जैसी गतिविधियों में यहां हिस्सा लेकर अपनी यात्रा को और भी मजेदार बना सकते हैं। यानी मालदेवता हर तरह के पर्यटकों को आकर्षित करता है। इसलिए, चाहे आराम की तलाश है या फिर मनोरंजन की तलाश है यहां सभी की अपेक्षाएं पूरी हो जाती है। क्योंकि प्रकृति की गोद में चारों तरफ पर्वतों और हरियाली से सजे संवरे मालदेवता में खूबसूरती और झरनों का संगीत सुना जा सकता है। यहां पर्वतों से गिरने वाले छोटे-छोटे झरनों का संगीत विजिटर्स का ध्यान खींच ही लेते हैं। यही वजह है कि बीते कुछ सालों में यह देहरादून का सबसे डिमांड वाला डेस्टिनेशन बन गया है।

प्राचीन मालदेवता मंदिर

मालदेवता में ट्रेकिंग कर सकते हैं। यहां के अनछुए रास्तों पर ट्रेकिंग करें और छोटे-छोटे गांवों को एक्सप्लोर करें, ताकि आप रोमांच का भरपूर आनंद उठा सकें। ट्रेकर्स के लिए मालदेवता स्वर्ग से कम नहीं है। यह शांत स्थान सालाना बड़ी संख्या में घुमक्कड़ों और साहसिक खोजकर्ताओं को आकर्षित करता है। घुमक्कड़ और खोजकर्ता इस क्षेत्र में रोमांचक यात्राएं करते हुए प्रकृति की सुंदरता का लुत्फ उठाते हैं। मन की शांति और सकारात्मकता का अनुभव करने के लिए मालदेवता मंदिर अवश्य जाना चाहिए। यह यहां का एक और प्रमुख आकर्षण है जहां सैलानियों को अवश्य जाना चाहिए। मंदिर तक पहुंचने के लिए कुछ सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। मंदिर में श्रद्धापूर्वक सिर झुकाने से ऊर्जा का संचार महूसूस होता है। क्योंकि हिमालय की तलहटी में समुद्र तल से लगभग 1800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मालदेवता मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। माना जाता है कि यह मंदिर 1000 वर्ष से भी अधिक पुराना है। स्थानीय निवासियों के साथ दूर-दूर से आने वाले शिव भक्तों द्वारा मालदेवता मंदिर में श्रद्धाभाव से पूजा की जाती है। मंदिर के निर्माण में स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्रियों का ही उपयोग किया गया है और यह अपनी जटिल नक्काशी और शानदार वास्तुकला के लिए जाना जाता है। मंदिर और गांव का नाम मालदेवता कैसे पड़ा ये सवाल भी हर किसी के जहन में आता होगा, तो बताते हैं कि इस जगह को मालदेवता क्यों कहा जाता है? नदी के तेज बहते पानी के ठीक बगल में मंदिर है, जिसे मालदेवता के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि यह स्थान व्यापार मार्ग पर पड़ता था और लोग पहाड़ी यात्रा या भाबर क्षेत्र की तरफ जाने से पहले यहां आराम करने के लिए रुकते थे। चूंकि इस स्थान का उपयोग मुख्य रूप से व्यापारियों द्वारा किया जाता था, इसलिए वे यहां शिव के दर्शन करते थे। माल शब्द का प्रयोग व्यापारिक और हिंदी में सामान या सामग्री के लिए किया जाता है। व्यापारियों के साथ माल होता था इसलिए मंदिर और स्थान का नाम माल प्लस देवता को मिलाकर मालदेवता बन गया। इसलिए इस मंदिर का नाम मालदेवता पड़ा। हरे-भरे जंगलों, झरनों और चमचमाती जलधाराओं से घिरा होने के कारण प्रकृति प्रेमियों, ट्रेकर्स और साहसिक गतिविधियों के शौकीनों के लिए एक आदर्श गंतव्य है। वैसे भी यह क्षेत्र मुख्य रूप से शिवालिक पर्वतमाला के घने जंगलों के बीच है। यह क्षेत्र विभिन्न प्रकार के पेड़-पौधों, वनस्पतियों और जीव-जंतुओं का घर है, जिनमें ओक, पाइन और देवदार के पेड़, साथ ही विभिन्न पक्षी और वन्यजीव शामिल हैं। यह क्षेत्र भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से एक शानदार टाइगर फॉल्स के लिए भी मशहूर है।

मालदेवता की सुंदरता का आनंद लेने का सबसे अच्छा समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक ही है, अंधेरा होने के बाद, जंगली जानवर अक्सर अपने छिपने के स्थानों से बाहर आ जाते हैं, जो किसी के लिए भी खतरनाक हो सकता है, इसलिए सलाह दी जाती है कि सूर्यास्त से पहले सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं।

नदी के किनारे बैठकर थकान दूर करें

मालदेवता गांव के इस क्षेत्र के आसपास पर्यटक कैंपिंग का आनंद ले सकते हैं। घने जंगलों से घिरा यह स्थान कैंपर्स को अपने टेंट लगाने, अपनों के साथ अलाव जलाकर मस्ती करने और मनमोहक नजारों के साथ रात को सुकून की नींद के लिए आमंत्रित करता है। हाइकिंग और कैंपिंग जैसी साहसिक गतिविधियों के लिए भी यह एक लोकप्रिय गंतव्य है। इस क्षेत्र में कई पगडंडियां हैं जो मनोरम दृश्यों वाले स्थानों, छिपे हुए झरनों और एकांत शिविर स्थलों तक ले जाती हैं, जिससे यह बाहरी गतिविधियों के शौकीनों के लिए एक आदर्श स्थान बन जाता है। यदि जंगल में ताजा तैयार किया हुआ भोजन करने की इच्छा है तो फिर खुद ही नदी के किनारे खाना बना सकते हैं। बस आपके पास खाना बनाने के लिए बर्तन और सामग्री होनी चाहिए। मालदेवता में सभी के लिए प्रवेश निःशुल्क है। यह स्थान दिन भर पर्यटकों के लिए खुला रहता है, लेकिन इसकी सुंदरता का आनंद लेने का सबसे अच्छा समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक ही है। अंधेरा होने के बाद, जंगली जानवर अक्सर अपने छिपने के स्थानों से बाहर आ जाते हैं, जो किसी के लिए भी खतरनाक हो सकता है। इसलिए सलाह दी जाती है कि सूर्यास्त से पहले सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं। राजधानी देहरादून और इसके आसपास आम तौर पर साल भर मौसम बहुत ही सुहावना रहता है, इसलिए पर्यटक कभी भी मालदेवता का भ्रमण कर सकते हैं। यदि यात्रा का भरपूर आनंद लेना चाहते हैं, तो गर्मियों के मौसम यानी अप्रैल से अगस्त के बीच मालदेवता का टूर कर सकते हैं। मालदेवता नदी के लिए खास तौर से प्रसिद्ध है, जहां पर्यटक जलधाराओं के बीच पत्थरों पर बैठ कर आराम कर सकते हैं। सुकून पाने और बहते पानी में डुबकी लगाकर ताजगी को महसूस कर सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखें जब भी ऐसे क्षेत्र में घूमने जाएं जहां वन्यजीवों का घर हो वहां तेज आवाज में संगीत न बजाएं क्योंकि इससे आसपास के क्षेत्र में रहने वाले वन्यजीवों के कानों को नुकसान पहुंच सकता है। उनकी जीवनचर्या में व्यवधान पैदा हो सकता है, इसलिए वन्यजीव हमला भी कर सकते हैं।

मालदेवता का अनोखा वाटरफॉल

मालदेवता देहरादून से कुछ ही दूरी पर है। यदि सहस्त्रधारा-रायपुर मार्ग पर गाड़ी चला रहे हैं, तो निश्चित रूप से मालदेवता से होकर आप गुजरेंगे। देहरादून से धनौल्टी जाने वाली नई सीधी सड़क भी इसी गांव से होकर गुजरती है। यह गांव अनेक छोटे-छोटे घरों के कारण भी लोकप्रिय है। रोचक बात यह है कि इस क्षेत्र की दो महत्वपूर्ण नदियां, सोंग नदी और सहस्त्रधारा नदी जिसे बद्री नदी भी कहा जाता है, इसी स्थान पर मिलती हैं। दूर-दूर तक फैले हरे-भरे खेत, चारों ओर फैली विशाल पहाड़ियां और दोनों नदियों का बहता जल, ये सब मिलकर मालदेवता को निःसंदेह एक पवित्र स्थान बनाता है। अनोखा मालदेवता वाटरफॉल भी प्रकृति का एक छिपा हुआ स्वर्ग है। शहर के शोरगुल और भागदौड़ भरी जिंदगी से थक चुके हैं लोग अगर जंगलों, बहते पानी और पहाड़ों की ताजी हवा से घिरे एक शांत स्थान की तलाश में हैं, तो मालदेवता वाटरफॉल एक बेहतरीन जगह है। जो देहरादून के सुरम्य बाहरी क्षेत्र में छिपा हुआ है, यह कम प्रसिद्ध वाटरफॉल प्रकृति प्रेमियों, ट्रेकर्स और प्रकृति के साथ फिर से जुड़ने वालों के लिए बेहतरीन स्थान है। इसलिए कहा जाता है कि मालदेवता घाटी में प्रवेश करते ही एक शांत वातावरण पर्यटकों का स्वागत करता है। मालदेवता के छिपे हुए झरने तक की ट्रेकिंग मध्यम स्तर की है और शुरुआती लोगों के लिए उपयुक्त है। पहली बार ट्रेकिंग करने वालों के लिए भी यह उपयुक्त। ट्रेकर्स जैसे-जैसे जंगल में और अंदर जाते हैं, पेड़ों की घनी पत्तियों से छनकर आती सूरज की रोशनी पगडंडी पर जादुई आकृतियां बनाती है। पानी की आवाज धीरे-धीरे तेज होती जाती है, जिससे हर कदम के साथ रोमांच बढ़ता जाता है। फिर ट्रेकिंग करते हुए अचानक जंगल खुल जाता है और सामने आ जाता है मालदेवता का झरना, जो पहाड़ की ऊंची चोटी से खूबसूरती से नीचे गिरता है। जिससे झागदार सफेद धाराएं बनती हैं, जो नीचे साफ पानी के कुंडों में समा जाती हैं। यह दृश्य मनमोहक और शांतिदायक दोनों है, जो आपको विस्मय में लीन कर देता है। यह क्षण ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रकृति अपने सबसे बड़े रहस्यों में से एक को उजागर कर रही हो। इस जगह की बेमिसाल खूबसूरती की अद्भुत तस्वीरें लेना न भूलें, जो हर उम्र के फोटोग्राफरों को पसंद आएंगी। शानदार पृष्ठभूमि के साथ, प्रकृति की जितनी चाहें उतनी तस्वीरें ले सकते हैं। इस जगह का इस्तेमाल प्री-वेडिंग और पोस्ट-वेडिंग शूट के लिए भी किया जा सकता है। रायपुर से मालदेवता की ओर जाते समय, पहला पड़ाव एक छोटी, जर्जर चक्की (घरत) मिलगी। जिसके नीचे एक पत्थर की नहर से पानी बहता है। यह कलंगा नहर की आपकी पहली झलक होगी। मालदेवता की ओर आगे बढ़ते हुए, नहर साथ देती रहेगी जब तक एक और चक्की पुल के ठीक बगल तक नहीं पहुंच जाते। इस चक्की को कुछ वर्ष पहले पुनर्जीवित किया गया था और यह देखने लायक जगह है। दून घाटी में कभी घराट या जल चक्कियां अनाज पीसने का एकमात्र साधन होती थी। लेकिन अब बिजली की चक्कियों के आने से इनकी चमक फीकी पड़ गई है, क्योंकि बिजली की चक्की इस्तेमाल में आसान और तकनीकी रूप से उन्नत हैं। ●

- **मालदेवता मंदिर में श्रद्धापूर्वक सिर झुकाने से ऊर्जा का संचार महूसूस होता है, क्योंकि हिमालय की तलहटी में समुद्र तल से लगभग 1800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मालदेवता मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, माना जाता है कि यह मंदिर 1000 वर्ष से भी अधिक पुराना है।**
- **इस क्षेत्र में कई पगडंडियां हैं जो मनोरम दृश्यों वाले स्थानों, छिपे हुए झरनों और एकांत शिविर स्थलों तक ले जाती हैं, यदि जंगल में ताजा तैयार किया हुआ भोजन करने की इच्छा है तो फिर खुद ही नदी के किनारे खाना बना सकते हैं, बस आपके पास खाना बनाने के लिए बर्तन और सामग्री होनी चाहिए।**

आधी आबादी के लाडले मोहन

मोहन यादव ने मातृशक्ति के बीच खुद को एक ऐसे भाई के रूप में स्थापित किया जैसा कृष्ण ने द्रोपदी के चीर हरण के समय सशक्त भाई की भूमिका निभाई थी, मोहन सरकार ने मातृशक्ति के लिए किए जा रहे कामों से साबित कर दिया की मातृशक्ति के बीच वे न केवल विश्वसनीय है, बल्कि मातृशक्ति अब उन पर यकीन भी कर रही है और उन्हें लाडला भैय्या कहने लगी है।

आलोक एम इंदौरिया
विश्लेषक एवं स्तंभकार

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव जिस तरह प्रदेश की महिलाओं के समग्र उत्थान लिए काम कर रहे हैं, उससे राजनीतिक विथिकाओं में अब ऐसा माना जाने लगा है कि डा. मोहन यादव और मध्य प्रदेश की बहनों के बीच स्वस्थ आत्मीय रिश्ते न केवल परवान चढ़ रहे हैं बल्कि धीरे-धीरे वे एक ऐसे गठबंधन का रूप लेते जा रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए न केवल बेहद मुफीद होंगे बल्कि 2028 के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की तकदीर लिखने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा सकते हैं। डा. मोहन यादव ने अपने समग्र महिला उत्थान, महिला स्वावलंबन और महिला सुरक्षा के इन तमाम भागीरथी प्रयासों से न केवल मातृशक्ति के बीच अपनी विश्वसनीयता पुख्ता की है बल्कि प्रदेश की बहनों के बीच वे खासे लोकप्रिय भी हो गए हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिस तरह मध्य प्रदेश सरकार आधी आबादी के लिए काम कर रही है उससे एमपी की बहनें मोहन यादव की नीतियों की दीवानी हो गई हैं। उन्हें यकीन है कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार के रहते महिलाओं की तरक्की का मार्ग और विस्तार लेगा।

मातृशक्ति का अटूट विश्वास

दरअसल मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक मामा के रूप में खुद को ऐसा गढ़ा था कि सारे देश में वे मामा के नाम से खासकर महिला, किशोरियों और बच्चियों के बीच स्थापित हो गए थे। कालांतर में सत्ता परिवर्तन के बाद डा. मोहन यादव ने मध्य प्रदेश की कमान संभाली और वे इस बात को बखूबी जानते थे कि यदि प्रदेश में सरकार चलानी है और दोबारा सत्ता में लौटना है तो प्रदेश की कुल आबादी का 49 प्रतिशत महिला आबादी को न केवल खुद से जोड़ना होगा, बल्कि उन्हें अपना मजबूत जनाधार बनाना होगा। इसके लिए इस मातृशक्ति के बीच अपने आप को एक ऐसे भाई के रूप में स्थापित करना होगा जैसा कृष्ण के द्रोपदी के चीर हरण के समय एक सशक्त और समर्थ भाई की भूमिका निभाई थी। डा. मोहन यादव ने सत्ता संभालने के बाद मातृशक्ति के लिए लगातार किए जा रहे अपने कामों से यह साबित कर दिया की मातृशक्ति के बीच वे न केवल विश्वसनीय बन गए बल्कि मातृशक्ति अब उन पर अटूट विश्वास भी कर रही है और उन्हें लाडले भैया से संबोधित भी कर रही है। मध्य प्रदेश की कुल आबादी का लगभग 49 प्रतिशत महिलाएं हैं जिनकी संख्या 4.1 करोड़ से 4.2 करोड़ के आसपास आंकी जाती है। प्रदेश में मतदाताओं की कुल संख्या 5 करोड़ 70 लाख 92 हजार 367 है। इनमें महिला वोटर 2.5 करोड़ से 2.6 करोड़ के बीच अनुमानित हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में लगभग 76 प्रतिशत महिलाओं ने भाजपा के पक्ष में मतदान किया था जो 2018 के चुनाव से लगभग दो प्रतिशत अधिक था। अब सहज ही समझा जा सकता है कि प्रदेश में सत्ता प्राप्त करने के लिए इनका महत्व क्या है?

आधी आबादी पर मोहन सरकार का फोकस

असम में हिमंत बिस्वा सरमा और बंगाल में शुभेंदु अधिकारी, इन दोनों ने अपने आप को मातृशक्ति के बीच न केवल स्थापित किया बल्कि भावनात्मक विश्वास भी पैदा किया है। 2026 में बंगाल में शुभेंदु अधिकारी और असम में हिमंत बिस्वा सरमा की बंपर सफलता का उदाहरण सारे देश के सामने हैं, जिसमें मातृशक्ति का भाजपा को जिताने में जो बड़ा योगदान है वह किसी से छिपा नहीं है। मध्य प्रदेश में लगभग 29 विधानसभा ऐसी हैं जहां महिला वोटर की संख्या पुरुष वोटरों से अधिक है और लगभग 50 सीटों पर वे निर्णायक भूमिका रखती हैं। बेहद समझदार और परिपक्व मुख्यमंत्री में तब्दील हो चुके डा. मोहन यादव इस राजनीतिक मर्म को समझते थे और शुरुआती दौर से ही समग्र महिला विकास, महिला सम्मान और महिला सुरक्षा पर उन्होंने और उनकी सरकार ने फोकस किया। इस बार डा. मोहन यादव ने अपना जन्मदिन भी मातृशक्ति के बीच मना कर एक ऐसी अमिट छाप छोड़ी जिसकी अनुगूंज सारे प्रदेश में सुनाई दे रही है। प्रदेश में 'महिला प्रथम' महिलाओं का वास्तविक आधार बन चुका है। लाडली बहना समेत डा. मोहन यादव के द्वारा प्रारंभ की गई महिला उत्थान, स्वाबलंबन तथा सुरक्षा की तमाम योजनाएं इसका केंद्र बिंदु है। जिसने तकरीबन 1 करोड़ 26 लाख महिलाओं की दैनन्दिनी (जिसमें व्यक्ति प्रतिदिन की महत्वपूर्ण घटनाओं, अपने अनुभवों, विचारों और दिन-भर के कार्यों का लिखित ब्यौरा रखता है) पर सीधा असर डाला है क्योंकि डा. मोहन यादव सरकार ने लाडली बहना योजना के तहत मिलने वाली मासिक सहायता राशि को बढ़ाकर 1500 प्रति माह कर दिया है। हम इसे केवल एक वित्तीय सहायता मानकर ही इसके स्वरूप का आकलन नहीं कर सकते बल्कि यह सरकार और डा. मोहन यादव के बीच इन लाडली बहनों के उस भरोसे की एक ऐसी नजीर है जिसमें वह आज मोहन यादव को लाडला भय्या कहकर संबोधित कर रहीं है। अकेली लाडली बहना ही इस मातृशक्ति के लिए काफी नहीं है, बल्कि लखपति दीदी योजना, मुख्यमंत्री उद्यम शक्ति योजना, नारी शक्ति मिशन जैसी तमाम कार्यक्रमों को एक कड़ी में पिरोकर मोहन यादव ने महिला सशक्तिकरण का एक विशाल पैकेज मध्य प्रदेश में खड़ा कर डाला है। इसके लिए मोहन सरकार ने अपने बजट में से 1.25 हजार करोड़ से अधिक की रकम का प्रावधान महिलाओं के लिए किया। महिलाओं के लिए लाडली लक्ष्मी योजना ने जहां बेटियों की शिक्षा का भविष्य सुरक्षित किया है, वहीं लखपति दीदी, उद्यम शक्ति, ड्रोन दीदी समेत स्वावलंबन की कई सारी योजनाओं के माध्यम से शहर से लेकर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक की महिलाओं ने अपने छोटे-छोटे व्यवसाय शुरू करके खुद को आत्मनिर्भरता और सम्मान दोनों को स्थापित तो किया ही साथ ही परिवार और समाज में अपनी अहम जगह बनाई है।

सत्ता परिवर्तन के बाद डा. मोहन यादव ने मध्य प्रदेश की कमान संभाली और वे इस बात को बखूबी जानते थे कि यदि प्रदेश में सरकार चलानी है और दोबारा सत्ता में लौटना है तो प्रदेश की कुल आबादी का 49 प्रतिशत महिला आबादी को न केवल खुद से जोड़ना होगा, बल्कि उन्हें अपना मजबूत जनाधार भी बनाना होगा।

भाजपा अच्छी तरह जानती है कि असम में दूसरी बार सफलता और बंगाल में सत्ता पलटने व भाजपा को सत्ता सौंपने में महिलाओं का विशेष योगदान है, लिहाजा डा. मोहन मामा की जगह लाडले भाई का व्यक्तित्व बनकर लाडली बहनों की ऐसी ढाल बनकर खड़े हैं जिनके संरक्षण में एमपी की महिलाए खुद को सुरक्षित महसूस कर रहीं हैं।

सरकारी नौकरी में आरक्षण बढ़ा

अकेले राज्य सरकार की योजनाओं पर ही डा. मोहन यादव ने काम नहीं किया बल्कि बहनों के उत्थान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं के क्रियान्वयन में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में प्रदेश ने लगातार शीर्ष स्थान पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। जिसमें गर्भवती और शिशु स्वास्थ्य दर में प्रदेश ने खासी सफलता अर्जित की है। ऐसी एक नहीं तमाम योजनाएं हैं जिन सभी का उल्लेख करना संभव नहीं है। किंतु सच तो यही है कि आज महिला न केवल नगद राशि पाने वाली लाभार्थी बनी हैं, बल्कि राज्य की आर्थिक रीढ़ के साथ-साथ नीति निर्माण में भी सक्रिय भागीदारी निभा रही है। महिला स्वयं सहायता समूह, रसोई गैस कनेक्शन, मुफ्त राशन, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी तमाम योजनाओं में डा. मोहन सरकार ने महिलाओं को सीधा जोड़कर उन्हें सम्मान दिया है। महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण 33 प्रतिशत से बढ़कर 35 प्रतिशत करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य तो बना ही है पंचायत और स्थानीय निकायों में भी महिलाओं की भूमिका को मोहन सरकार ने बेहद मजबूत किया है। डा. मोहन यादव ने महिलाओं को सरकार की प्राथमिकता बताते हुए इन बहनों के बीच अपने आप को एक ऐसे भाई के रूप में स्थापित किया जिसे अपनी बहनों के रोजगार, स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा की न केवल चिंता है, बल्कि इन मुद्दों पर वह खुद और उनकी सरकार संवेदनशीलता के साथ-साथ गंभीर और सख्त भी है। इसके साथ राज्य में अब तक 5 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 60 लाख बहने जुड़ी है और यह न केवल बचत और ऋण का माध्यम है बल्कि गांव में होने वाले निर्णय में एक सशक्त भागीदारी वाली आवाज भी बनी है। नारी शक्ति मिशन के तहत जेंडर जागरूकता, घरेलू हिंसा विरोध, बाल विवाह रोकथाम और डिजिटल साक्षरता ने भी महिलाओं के उत्थान में बेहद योगदान दिया है।

बहनों का पूरा ध्यान

बरहाल डा.मोहन यादव की महिला केंद्रित योजनाओं ने जहां उनकी छवि एक ऐसे भाई के रूप में बनी है जो लगभग हर क्षेत्र में बहनों का पूरा ध्यान रखता है। इससे जहां न केवल भाजपा का महिला वोट बैंक मजबूत होगा वहीं भाजपा इस भरोसे को एक स्थाई समर्थन में बदलने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। रसोई गैस कनेक्शन, फ्री राशन, पीएम आवास और नगद सहायता जैसी योजनाओं से गांव में महिलाओं के बीच भाजपा की पकड़ और जकड़ बेहद मजबूत हो रही है। महिला लाभार्थी वर्ग भाजपा के लिए सशक्त सुरक्षात्मक ढाल बन सकता है और 2023 के चुनाव में यह साबित भी हो चुका है। डा.मोहन यादव और प्रदेश की मातृशक्ति के बीच बॉन्डिंग न केवल मजबूत हुई है बल्कि उसने एक गठबंधन का रूप ले लिया है। प्रदेश की मातृशक्ति मोहन यादव पर न केवल विश्वास करती है बल्कि बेहद गहराई के साथ उनसे जुड़ी भी है। निश्चित रूप से यह जुड़ाव 2028 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सहायक हो सकता है। भाजपा यह अच्छी तरह जानती है कि असम में लगातार दूसरी बार सफलता और बंगाल में सत्ता पलटने और भाजपा को सत्ता सौंपने में महिलाओं का विशेष योगदान है। लिहाजा डा. मोहन यादव मामा की जगह लाडला भाई का एक विशाल व्यक्तित्व बनकर इन लाडली बहनों के बीच ऐसी ढाल बनकर खड़े हैं जिनके संरक्षण में मध्य प्रदेश की महिलाएं न केवल सुरक्षित महसूस कर रहीं हैं बल्कि चहुंमुखी विकास की ओर निरंतर अग्रसर हो रही हैं।

रहस्यमयी देवरिया झील

लोकमान्यता है कि देवरिया ताल का निर्माण पांडवों में बलशाली भीम ने जल प्राप्ति के लिए किया था, एक रहस्य ये है कि जिसे देवरिया ताल कहा जाता है, वो देवताओं के स्नान करने का स्थल रहा है, कुछ प्राचीन हिंदू ग्रंथ इसे इंद्र सरोवर भी बताते हैं, अब आप इसे चाहे देवताओं की झील कहें या हिमालय की मनमोहक पृष्ठभूमि में स्थित देवताओं का अनंत कुंड, लेकिन हर कोई इस बात से सहमत होगा कि स्नान के लिए इससे बेहतर स्थान नहीं हो सकता।

अफजल फौजी
नैनीताल

उत्तराखंड सिर्फ अपनी नैसर्गिक खूबसूरती के लिए मशहूर नहीं है बल्कि देवभूमि पौराणिक, शांति और रहस्यों का संगम भी है। रुद्रप्रयाग जिले में स्थित देवरिया ताल सिर्फ एक पानी की झील नहीं है बल्कि पौराणिक रहस्य को अपने आगोश में छिपाए हुए है। लोकमान्यता है कि यहीं यक्ष (प्रकृति आत्मा) ने पांडवों से प्रश्न पूछे थे और युधिष्ठिर ने सही उत्तर देकर अपने चार भाइयों को जीवनदान दिलाया था। ये अपने आप में एक रहस्य है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में पहाड़ियों से घिरा एक ऐसा स्थान है जहां कहने और देखने को तो एक पानी की झील है, लेकिन यही झील पौराणिक कहानियों का रहस्य अपने आप में समेटे हुए है। यहां का सन्नाटा किसी मंदिर की घंटियों से कम पवित्र नहीं लगता और झील का शांत पानी इंसान को अंदर तक झांकने पर विवश कर देता है। इसी झील का नाम है देवरिया ताल है, जो अपनी रहस्यमयी खूबसूरती, पौराणिक कथाओं के लिए मशहूर है। यह झील लगभग 2,438 मीटर (लगभग 8,000 फीट) की ऊंचाई पर है। रुद्रप्रयाग के सारी गांव से पैदल ट्रेक के जरिये देवरिया ताल तक पहुंचा जा सकता है। यहां से चौंखभा पर्वत की तस्वीर स्पष्ट दिखाई देती है। इसलिए इसे हिमालयी चोटियों के अद्भुत प्रतिबिंब के लिए भी जाना जाता है। यह कोई साधारण या सामान्य झील या ताल नहीं है, बल्कि परीक्षा की भूमि है। जहां सत्य, विवेक और धर्म की कसौटी पर ही जीवन मिलता है। अब चाहे वो झील के शांत जल में चौखंबा का शांत प्रतिबिंब हो या इन बर्फीले पहाड़ों की चोटियों के चारों ओर मंडराते बादल चंद्रशिला पर नव उदय हुए चंद्रमा और एक दिन पुराने सूर्य की सामूहिक झिलमिलाहट हो या गिरे हुए पत्ते से उठने वाली क्षणिक लहर। वास्तव में कुछ भी नहीं बदलता, लेकिन कुछ तो बदल जाता है, यही हिमालय का प्रभाव है। स्थानीय लोग मानते हैं कि आज भी रात में झील से अजीब सी गूंज सुनाई देती है, मानो यक्ष अब भी सवाल कर रहा हो। क्योंकि महाभारत के अनुसार यह वही स्थान है जहां युधिष्ठिर ने यक्ष के कठिन सवालों के जवाब देकर अपने भाइयों अर्जुन, नकुल, भीम और सहदेव को जीवनदान दिलाया था।

19वीं शताब्दी के ब्रिटिश खोजकर्ताओं ने गढ़वाल हिमालय के सर्वेक्षण के दौरान इस झील का दस्तावेजीकरण किया था, जिससे यह बाहरी दुनिया के ध्यान में आई, तब से यह ट्रेकर्स, प्रकृति प्रेमियों व भीड़ वाले पर्यटन स्थलों से दूर एकांत चाहने वालों के बीच पसंदीदा स्थान बन गया है, पर्यटकों की भारी भीड़ के बावजूद देवरिया ताल ने अपनी प्राकृतिक सुंदरता को बरकरार रखा है।

यक्ष और पांडवों से जुड़ी है झील

पौराणिक काल में पांडव सिर्फ योद्धा ही नहीं थे बल्कि वो घुमक्कड़, ऊंचे पहाड़ों पर ट्रेकिंग करने वाले और पर्वतारोहण के शौकीन भी थे। उत्तराखंड के इन पहाड़ों की कहानियां महाकाव्य महाभारत से जुड़ी हुई मिलती हैं। स्थानीय लोककथाओं के अनुसार यह वही झील है जहां पांडवों को वनवास के दौरान एक रहस्यमयी प्राणी यक्ष द्वारा ली गई परीक्षा का सामना करना पड़ा था। कथा के अनुसार पांडव थके-हारे और प्यासे इस शांत झील पर पहुंचे। जब उन्होंने पानी पीने का प्रयास किया, तो उनका सामना यक्ष (प्रकृति आत्मा) से हुआ, जिसने प्यास बुझाने से पहले उनसे कुछ प्रश्न पूछे। चार पांडव यक्ष के सवालों का जबाव नहीं दे पाए और वो मत्युलोकगामी हो गए। लेकिन सबसे बड़े पांडव युधिष्ठिर अपनी बुद्धि, विवेक और धैर्य से यक्ष के प्रश्नों का सही उत्तर दे सके, जिससे उन्होंने अपने भाइयों की जान बचाई और यक्ष (जो सारस के वेश में था) से भाइयों के पुनर्जीवन का वरदान प्राप्त किया। बाद में यक्ष ने स्वयं को मृत्यु के देवता यम के रूप में प्रकट किया। यह कथा न केवल महाभारत का अभिन्न अंग है, बल्कि स्थानीय संस्कृति में भी गहराई से समाई हुई है। आज भी इस झील को पवित्र माना जाता है और यह विश्वास किया जाता है कि देवरिया ताल का जल आध्यात्मिक महत्व रखता है, जो पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है। यदि आपने टीवी पर महाभारत का प्रसारण देखा है या महाभारत ग्रंथ पढ़ा है, तो आपको यह कहानी याद होगी। स्थानीय लोग कहते हैं कि देवरिया ताल की कहानियां, किंवदंतियां सनातनी महाकाव्यों में वर्णित है। एक लोकमान्यता ये भी है कि इस झील का निर्माण पांडवों में श्रेष्ठ बलशाली भीम ने जल प्राप्ति के लिए किया था। एक और रहस्यमयी कहानी ये भी है कि जिसे देवरिया ताल कहा जाता है, वो देवताओं के स्नान करने का स्थल रहा है। देव का अर्थ है भगवान और ताल का अर्थ झील है। कुछ प्राचीन हिंदू ग्रंथ इसे इंद्र सरोवर भी बताते हैं। अब आप इसे चाहे देवताओं की झील कहें या हिमालय की मनमोहक पृष्ठभूमि में स्थित देवताओं का अनंत कुंड, लेकिन हर कोई इस बात से तो सहमत होगा कि स्नान के लिए इससे बेहतर स्थान नहीं हो सकता था। इस शांत स्थान से जुड़ी प्राचीन लोककथाओं का जादू इसे रहस्य से भी कहीं अधिक समृद्ध बना देता है। यह रहस्य केवल एक विशेष प्रकार के संयोजन से ही पैदा होता है।

देवरिया ताल का ऐतिहासिक महत्व

देवरिया ताल की पौराणिक जड़ें तो सर्वविदित हैं, लेकिन इसका ऐतिहासिक महत्व कम ही मिलता है। इतिहासकार कहते हैं कि देवरिया ताल और इसके आसपास का क्षेत्र प्राचीन व्यापार मार्गों का हिस्सा रहा है, जो हिमालयी भीतरी इलाकों को मैदानी क्षेत्रों से जोड़ते थे। देवरिया ताल के आसपास का क्षेत्र सदियों से आबाद रहा है, यहां का स्थानीय समुदाय कृषि, पशुपालन और छोटे स्तर पर व्यापार करता है। यह क्षेत्र मध्यकाल में उत्तराखंड के कुछ हिस्सों पर शासन करने वाले कात्युरी राजवंश से भी प्रभावित रहा है। कात्युरी वंश मंदिरों के संरक्षण और इस क्षेत्र में हिंदू धर्म के प्रसार के लिए जाना जाता है। हालांकि कात्युरी शासनकाल के ऐतिहासिक ग्रंथों में देवरिया ताल का कहीं कोई प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं है, लेकिन प्राचीन मंदिरों और तीर्थ मार्गों के निकट स्थित होने के कारण यह झील संभवतः उस समय भी आध्यात्मिक शांति का केंद्र रही होगी। ऐसी भी मान्यता है कि देवरिया ताल नाम देवस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है देवता, जो झील के दिव्य संबंध को दर्शाता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि देओरिया शब्द देवरिया से आया है, जिसका अर्थ है देवताओं का निवास स्थान। यह इस विश्वास को और मजबूत करता है कि देवरिया ताल केवल एक प्राकृतिक चमत्कार ही नहीं बल्कि एक दिव्य निवास भी है। हाल के इतिहास में देवरिया ताल एक एकांत, शांत और पवित्र स्थान से लोकप्रिय ट्रेकिंग स्थल में परिवर्तित हो गया है। 19वीं शताब्दी के ब्रिटिश खोजकर्ताओं और मानचित्रकारों ने गढ़वाल हिमालय के सर्वेक्षण के दौरान इस झील का दस्तावेजीकरण किया था, जिससे यह बाहरी दुनिया के ध्यान में आई। तब से यह ट्रेकर्स, प्रकृति प्रेमियों और भीड़भाड़ वाले पर्यटन स्थलों से दूर एकांत चाहने वालों के बीच पसंदीदा स्थान बन गया है। पर्यटकों की भारी भीड़ के बावजूद, देवरिया ताल ने अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण को बरकरार रखा है। झील के महत्व से भलीभांति परिचित स्थानीय निवासी इसके प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। झील और उसके आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ बनाए रखने के लिए पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं।

उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में पहाड़ियों से घिरा एक ऐसा स्थान है जहां कहने और देखने को तो एक पानी की झील है, लेकिन यही झील पौराणिक कहानियों का रहस्य अपने आप में समेटे हुए है, लोकमान्यता है कि यहीं यक्ष (प्रकृति आत्मा) ने पांडवों से प्रश्न पूछे थे और युधिष्ठिर ने सही उत्तर देकर अपने चार भाइयों को जीवनदान दिलाया था, ये अपने आप में एक रहस्य है।

देवरिया ताल घूमने का अच्छा समय

देवरिया ताल घूमने का सबसे अच्छा समय सर्दियों के बाद मार्च से मई तक और मानसून के बाद और सर्दियों से पहले अक्टूबर से नवंबर तक है। सर्दियों के महीनों में यानी दिसंबर और जनवरी में जब बर्फबारी शुरू होती है, तो देवरिया ताल की रातें बेहद ठंडी हो जाती हैं। जून-जुलाई में जब गर्मी होती है, रातें ठंडी होती हैं। चोपटा-तुंगनाथ-चंद्रशिला-देवरिया ताल क्षेत्र में ट्रेकिंग के लिए मानसून का मौसम आमतौर पर उपयुक्त नहीं होता है। देवरिया ताल ट्रेक से आगे रोहिणी बुग्याल भी घूमने लायक स्थान है। चोपटा घाटी के घने जंगलों में छिपा रोहिणी बुग्याल एक शांत और सुंदर घास का मैदान है। देवरिया ताल होते हुए चंद्रशिला शिखर की यात्रा के दौरान, रोहिणी बुग्याल कैंपिंग के लिए एक आदर्श स्थान है। रोहिणी बुग्याल से गढ़वाल हिमालय के शानदार दृश्य दिखाई देते हैं, जिनमें केदारनाथ शिखर, चौखंबा, नीलकंठ, थाली सागर, केदार डोम और अन्य पर्वत श्रृंखलाएं शामिल हैं। लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित, सारी गांव चोपटा हिल स्टेशन से लगभग 20 किलोमीटर पहले का एक रमणीय गांव है। सारी गांव बेहद खूबसूरत देवरिया ताल झील के लिए बेस कैंप है, जो सारी गांव से केवल 2.5 किलोमीटर दूर आसान चढ़ाई पर है। कई बार जब चोपटा के सभी होटल बर्फबारी के कारण बंद हो जाते हैं, तो सैलानी सारी क्षेत्र के होटल और होमस्ट की तरफ रुख करते हैं। यहां ठहरने के लिए उपयुक्त होटल और होमस्टे मिल जाते हैं। सारी गांव में आसानी से कुछ लॉज भी उपलब्ध हो जाते हैं। देवरिया ताल के करीब ही बनियाकुंड एक छोटा सा गांव है जहां से चोपटा हिल स्टेशन के लिए घास के मैदानों की श्रृंखला शुरू होती है। यहां कुछ छोटे और आरामदायक होटल और कैंप हैं जो चोपटा आने वाले पर्यटकों के लिए ठहरने के विकल्प हैं। यहीं से केदारनाथ कस्तूरी मृग अभ्यारण्य की शुरुआत होती है। यह मृग अभ्यारण्य चोपटा से मात्र 4 किलोमीटर पहले, समुद्र तल से 2450 मीटर की ऊंचाई पर है, जहां से गढ़वाली हिमालय के विशाल क्षितिज का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। देवरिया ताल पहुंचने के लिए बस या ट्रेन से पहले ऋषिकेश या हरिद्वार पहुंचना होता है वहां से रुद्रप्रयाग होते हुए उखीमठ और फिर सारी गांव तक टैक्सी या बस सेवा उपलब्ध है। ऋषिकेश से सारी गांव लगभग 210 किलोमीटर की दूरी पर है। सड़क मार्ग से यात्रा करने पर लगभग 7 से 8 घंटे का सफर करना होता है। इसके बाद ट्रेक शुरू हो जाता है। अगर पहली बार ट्रेक कर रहे हैं और मौसम खराब है या प्राकृतिक मार्गों में भ्रमित हो सकते हैं, तो स्थानीय गाइड लेने की सलाह दी जाती है। लेकिन ट्रेक रास्ता स्पष्ट और सुरक्षित है, इसलिए अनुभवी ट्रेकर बिना गाइड के भी जा सकते हैं। कुल मिलाकर देवरिया ताल केवल एक ट्रेक या टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है बल्कि ये एक आत्मिक अनुभव है। जब पर्यटक झील के किनारे बैठते हैं, तो वहां का शांत वातावरण भीतर तक छू जाता है। यह झील केवल तस्वीरों के लिए नहीं, बल्कि खुद को जानने और समझने के लिए है। अगर प्रकृति, पौराणिकता और शांति का संगम एक साथ अनुभव करना चाहते हैं, तो देवरिया ताल एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है, जहां आपको सिर्फ झील नहीं, बल्कि अपने अंदर का यक्ष भी मिल सकता है।

व्यंग्य

जिमखाना या जिमखाला

जब हम दिल्ली में डेरा जमाए हुए थे और भारत सरकार की सेवा कर रहे थे तब स्टाफ कार से सफदरजंग एयर पोर्ट कई बार आना-जाना होता था, तभी हमारे चक्षुओं ने 27.3 एकड़ में पसरे दिल्ली जिमखाना (जिमखाला) क्लब के बाहर से ही दर्शन कर अपने सौभाग्य को प्रणाम किया था, क्योंकि ये अंग्रेजों के जमाने में 1913 में इस्टैबलिश्ड हुआ था।

प्रदीप भट्ट
व्यंगकार, मेरठ

सपने हैं सपना देखने में कोई खर्च नहीं होता, खूब देखों वो भी देखो जिसकी भविष्य में कहीं दूर तक कहने-सुनने की जरा सी भी गुंजाइश नहीं है। हमें भी वो सपने आ टपकते हैं जिनके बारे में सोचते या सुनते तक नहीं हैं। खैर एक सपने का किस्सा आपको सुनाता हूं, तो हुआ यूं कि बहुत साल पहले जब हम दिल्ली में डेरा जमाए हुए थे और भारत सरकार की सेवा कर रहे थे तब स्टाफ कार से सफदरजंग एयर पोर्ट कई बार आना-जाना होता था। तभी हमारे चक्षुओं ने 27.3 एकड़ में पसरे दिल्ली जिमखाना (जिमखाला) क्लब के बाहर से ही दर्शन कर अपने सौभाग्य को प्रणाम किया था, क्योंकि ये अंग्रेजों के जमाने में 1913 में इस्टैबलिश्ड हुआ था। हमारे साथी जिमखाला क्लब के बारे में जितना जानते थे हमें बताकर अपने ज्ञान की नुमाइश करते हुए बिन मांगी सलाह भी देने लगे। बोले गुरु तुमको दिल्ली में इत्ते दिन हो गए तुमने दिल्ली के बारे में क्या कुछ जाना है? नहीं जाना है तो हमसे पूछो लेकिन अपने आपको अपडेट रखो। हमने भी उसकी लय में ही उसे जवाब थमा दिया। अरे मियां तुम रुड़की के बारे में क्या जानते हो? उसने ना में मुंडी हिलाई तो हम फट पड़े मियां रुड़की में गंगा मैय्या बहती है एक जगह नदी ऊपर बहती है और नहर नीचे फिर आगे जाकर नहर ऊपर और नदी नीचे हो जाती है। आईआईटी रुड़की कितनी पुरानी है मालूम है, उसने फिर ना में मुंडी हिलाई तो हमने खुतबा देने की मुद्रा में कहा सुनो मियां हर जगह ज्ञान पेलने की आदत से बाज आओ। तुम जैसे लोगों के बारे में ये कहावत मशहूर हो गई कि बंदर को मिली हल्दी की गांठ तो वो खुद को पंसारी समझ बैठा। भाई साहब उस दिन हमारे उस साथी ने बड़ी मुश्किल से थूक हलक के नीचे उतारा और दफ्तर पहुंचने तक एकदम मुर्दा बना रहा। शायद मन ही मन कसम खा ली हो कि इस बंदे से कभी नहीं भिड़ेंगे।

5600 दिवाने हैं हमारे

खैर अंग्रेजों के जमाने की जिमखाला के दिन में दर्शन हुए तो रात को हमारे सपने में जिमखाला क्लब ही आ गया। 27.3 एकड़ में पसरे कल्ब ने इंसानी मोहतरमा का रूप ले रखा था, एक दम गोरी चिट्टी तीन फीट की मोहतरमा। सपने में उसने अपना तारूफ जिमखाला क्लब के रूप में कराया तो हम सपने में ही चौंक पड़े। फिर अपने होशो हवास पर काबू पाते हुए पूछा अरे मोहतरमा 27.3 एकड़ में फैली हो फिर इंसानी रूप में कैसे प्रकट हो गई, वो भी हमारे सपने में और हां पिछले महीने ही तो हॉर्मूज हमारे सपने में आकर अपनी व्यथा बताकर गया है, इस महीने तुम आ टपकी। इरादे तो नेक हैं महोतरमा। उसने कातर नजर से ताकते हुए कहा मियां हमारी मजाक मति बनाओ। देखो जैसे ऋषि मुनि या देवता अपना रूप बदलते हैं तो क्या वैसे हम नहीं बदल सकते। पर तुम 27.3 एकड़ पर कुछ ज्यादा ही जोर नहीं दे रहे हो मियां। 5600 दिवाने (सदस्य) हैं हमारे, सब के सब षडयंत्रकारी, सब के सब जिमखाला में आकर अंग्रेज बन जाते हैं और फिर अपने ही देश के खिलाफ साजिश रचते हैं। बाकी देश से उनका क्या लेना देना है। पहले गोरे चिट्टे अंग्रेज रौब झाड़ते थे अब काले अंग्रेज। जब से जिमखाला क्लब ने इंसानी रूप लेकर मेरे ख्वाब में इंट्री कि थी तो मुझे एक बारिश में भीगे हुई कुकुर की भांति लग रही थी। उसकी मरियल सी आवाज सुनकर सच कह रहा हूं मुझे भी थोड़ी सी तकलीफ तो हुई पर जाने दो जी, मुझे क्या करना। लेकिन दिल है कि मानता नहीं की तर्ज पर पूछ बैठा अपने बारे में और कुछ बताओ मोहतरमा। हमारा ये पूछना था कि जिमखाला तुनक कर बोली क्यूं रे हम पे पीएचडी करनी है क्या? हमने कहा अब तुम हमारे सपने में आई हो हम थोड़े तुम्हारे सपने में घुसे हैं। पहले समस्या बताओ फिर हम समाधान बता देंगे। जिमखाला ने अपने आधे गंजे होते सर को खुजाया फिर बोली तो सुनो।डॉग एंड

- **5600 दिवाने (सदस्य) हैं हमारे, सब के सब षडयंत्रकारी, सब के सब जिमखाला में आकर अंग्रेज बन जाते हैं और फिर अपने ही देश के खिलाफ साजिश रचते हैं, बाकी देश से उनका क्या लेना देना है, पहले गोरे चिट्टे अंग्रेज रौब झाड़ते थे अब काले अंग्रेज साजिश रचते हैं।**
- **जिमखाला बोली पता नहीं एक नंबर में कितनी मेंबर फीस है और दो नम्बर में कितनी, लेकिन मियां वेटिंग 20-25 साल की रहती है, कांग्रेस, सपा, आरजेडी, टीएमसी डीएमके की तरह यहां भी परिवारवाद हावी है, अगर कोई मर गया तो उसके परिवार को प्राथमिकता नहीं मरा तो भी परिवार को प्राथमिकता, आम आदमी सिर्फ वेटिंग में रहता है।**

इंडियन आर नॉट अलाउड

डॉग एंड इंडियन आर नॉट अलाउड (ये मेरे यानी ब्रिटिश शासन के दौरान का नस्लभेदी भेदभाव का सबसे बड़ा प्रतीक था) क्योंकि सर स्पेंसर हरकोर्ट हर्बर्ट साहब ने मेरी बुनियाद रखी थी। अंग्रेजों की हुकुमत में मेरा नाम इंपीरियल जिमखाना क्लब था, आजादी के बाद कालों ने मेरा नाम दिल्ली जिमखाला क्लब रखकर मेरी तोहीन की। मेरे अंगना में तब गोरे अंग्रेज ही अलाउड थे फिर कुछ काले अंग्रेज (गद्दारों) की भी इंट्री हो गई। इन्हीं हर्बट भैया ने 1921 में कानपुर में इंजीनिरिंग कॉलिज बनवाया था। शुरू में अंग्रेज फिर गद्दार, आजादी के बाद ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियन ज्यूडिशरी वगैरह...वगैरह भी मेंबर बनते चले गए और फिर विदेशी जासूसों का हमारे आंगन में आवागमन शुरू हो गया। सीधे-सीधे यूं समझ लो साब मैं इंडियन डिप स्टेट की शराबखोरी, अय्याशी और भारत के विरुद्ध षड्यंत्रों का अड्डा बन गई। अब बताओ ये मजाक नहीं है, देश के प्रधानमंत्री के निवास की दीवार और मेरी दीवार आपस में बात करती होंगी तो क्या टॉपिक होते होंगे। वैसे एक बात बताऊं राजीव गांधी ने इन्हीं हरकतों को देखकर मेरे ऊपर बुलडोजर चलाने और मुझे दिल्ली से बाहर फेंकने का फरमान सुनाया था। क्योंकि पीएमओ हो फाइनेंस या डिफेंस हो दूसरे देशों के लिए जासूसी करने वाले गद्दार शाम को और कभी-कभी तो दिन में भी क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट्स सौंपने आ टपकते थे और मैं सिर्फ देखने के अलावा कुछ नहीं कर पाती थी दोस्त...। आखिरकार मैंने भी तो इंडिया का नमक खाया है। मैंने हूं किया, फिर पूछा अच्छा एक बात बताओ तुम्हारी मेंबरशिप की फीस कितनी है। जिमखाला ने फिर खोपड़ी खुजाई और बोली पता नहीं एक नंबर में कितनी है और दो नम्बर में कितनी, लेकिन मियां वेटिंग 20-25 साल की रहती है। कांग्रेस, सपा, आरजेडी, टीएमसी डीएमके की तरह यहां भी परिवारवाद हावी है। अगर कोई मर गया तो उसके परिवार को प्राथमिकता नहीं मरा तो भी परिवार को प्राथमिकता, आम आदमी सिर्फ वेटिंग में रहता है। जिमखाला तुमसे सरकार को क्या फायदा है। फायदा है ना 1000 रुपये की भारी भरकम रकम सालाना अदा करती हूं। यहां 40 प्रतिशत आईएएस 40 डिफेंस, 20 परसेंट में बाकी सब। और ये सब हाथ में शैम्पेन पीते हुए आपस में चर्चा करते हैं कि हमारा देश बहुत गरीब है इसका कुछ नहीं हो सकता।

एक लंबी सांस लेकर जिमखाला बोली और कुछ पूछना है मियां। हमने कान में उंगली डालकर सर को झटका दिया और पूछा ये नाले की क्या कहानी है खाला? अबकी बार जिमखाला ने आंखें तरेरी हमें देखा फिर हूं करके बोली तो तुम्हे सब पता है। मियां सच कह रही हूं खुले नाले से सबसे ज्याद खतरा प्रधानमंत्री आवास को है। भले ही आज तक कुछ नहीं हुआ भगवान न करे कल कुछ हो गया तो अपनी तो बेज्जती में दाग लग जाएगा। लिहाजा तुम ये सारी बात मोदी जी तक पहुंचा दो और चांडाल चौकड़ी से मुझे मुक्त करा दो। और हां सुनो जो मेरी बात पे यकीन न हो तो रॉबर्ट बेयर की किताब सी नो इविल पढ़ लो सब समझ आ जाएगा। वैसे भी इस किताब को आए हुए 25 बरस होने को हैं पता नहीं इन 25 बरसों में इन गद्दारों ने मेरी छाती पर बैठकर कितने कांड किए होंगे। हमने भी कह दिया शहरी विकास मंत्रालय में हमारा जुगाड़ है वहां से खाली करने का नोटिस भिजवाते हैं। ये सुनते ही जिमखाला ने हमें एक रेपटा रसीद करते हुए कहा अबे किस दुनिया में है, 5 जून तक हमें शिफ्ट करने का ऑर्डर मिला था पर मेरे अंगना में ऐश करने वालों ने शिफ्ट करने पर रोक लगा दी है।

राबर्ट बियर की किताब सी नो इविल जो कि 2002 में पब्लिश हुई है, बकौल राबर्ट बियर सीआईए का भारत की राजधानी दिल्ली में सबसे सेफेस्ट हाउस अगर कोई था तो वो था जिमखाना क्लब यानी जिमखाला क्लब को सीआईए का मिनी हेडक्वार्टर भी कहा जाता था।

राबर्ट बियर की किताब है सी नो इविल जो कि 2002 में पब्लिश हुई है। बकौल राबर्ट बियर सीआईए का भारत की राजधानी दिल्ली में सबसे सेफेस्ट हाउस अगर कोई था तो वो था जिमखाना क्लब यानी जिमखाला क्लब को सीआईए का मिनी हेडक्वार्टर भी कहते थे। बकौल पंकज प्रसून सी नो इविल में रॉबर्ट लिखते हैं कि 1971 के युद्ध में बांग्लादेश आजाद हुआ। 1972 में सोवियत संघ ने भारत को एक टी 72 टैंक बेचा था। अमेरिका जानना चाहता था कि भारत इसे किस सीमा पर डिप्लॉय करेगा। रॉ एवं आईबी इस विषय पर बहुत चौकसी बरत रही थी, लेकिन जो जानकारी कहीं से लीक नहीं हुई वो जिमखाला क्लब में अमेरिकी जासूसों ने लीक करवा ली। अब आप खुद सोचो इतने डेंजरस डेंजरस काम हुए हैं जिमखाला क्लब में, तो क्या भारत का इंटेलीजेंस डिपार्टमेंट दो पैग लगाकर सो रहा था। ना जी ना वो तो एकदम चौकस रहता है पर कुछ गद्दार फिर वो चाहे किसी भी लॉबी के हों उनके लिए देश की सुरक्षा में सेंध लगती है तो लग जाए पर उनकी अय्याशी में कमी नहीं आनी चाहिए बस। कुसूर इनका भी नहीं लगता इनको विरासत में जो मिला है ये वैसा ही करेंगे। वैसे भी जिमखाला के अलावा भी न जाने कितने क्लब सरकारी जमीन पर चल रहे हैं और सरकारी छाती पर मूंग दल रहे हैं। यकीन नहीं तो नजीर पेश करता हूं। 1930 में भारत के एक बड़े पत्रकार दुर्गादास जो एसोसिएटीड प्रेस ऑफ इंडिया अब (प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया) से संबंधित थे, ने जब लंदन का दौरा किया तो पाया कि वहां पत्रकारों के लिए प्रेस क्लब बना हुआ है तो बस उन्होंने आते ही जिद पकड़ ली। भैय्या हमें भी प्रेस क्लब चाहिए और लो जी सरकारी खर्चे से पत्रकारों की मौजमस्ती के लिए प्रेस क्लब बन गया। ये विषय अलग है कि उस पर आज तक वामपंथियों का कब्जा है। यानी जो सीधे काम को भी उल्टे हाथ से करे वो लेफ्टिस्ट यानी वामपंथी कहलाता है। अब भाई साब इससे ज्यादा पोल मति खुलवाओ हमसे। अच्छा नई मानोगे तो सुनो महाराज दिल्ली गोल्फ क्लब, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, मियां सारे के सारे सरकारी जमीन पर सरकारी खर्चे से बने हुए हैं, लेकिन कब्जा वामपंथियों का है। पीटीआई हो या आईआईसी या दिल्ली गोल्फ क्लब के चुनाव आपको घुसने नहीं देंगे। यकीन नहीं तो लालू जी से पूछ लो इतने कद्दावर नेता को भी आईआईसी की मेंबरशिप नहीं मिली थी। हां ये संस्थान काम सरकार विरोधी ही करते रहते हैं। ये जितने भी बजर बट्टू टाइप क्लब हैं सारे के सारे उल्टे एंग्लो से काम करते हैं। टीएमसी ने तो बंगाल में छोटे छोटे बजर बट्टू टाइप क्लब खोल रक्खे थे जो कट मनी से लेकर झट मनी के भ्रष्टाचार में आकंठ में डूबे हुए थे। देख लो दो दिन में सार जिन्न हवा में गायब हो गए। मोदी जी से मिलना तो टेढ़ी खीर है सो जिमखाला की तरह हमने भी मोदी जी की नींद में जुगाड़ लगाया और सारा माजरा सपने में तफ्सील से बयां कर दिया है। अच्छी बात ये हुई कि मोदी जी बोले तुम तो जानते हो प्रदीप बाबू मोदी है तो सब मुमकिन है।

धनौल्टी सोया हुआ शहर?

सालाना गर्मियां शुरू होते ही देवभूमि उत्तराखंड में पर्यटकों का सैलाब उमड़ने लगता है, उत्तराखंड का नैनीताल हो या अल्मोड़, कैंचीधाम, मसूरी, रानीखेत देहरादून अथवा परंपरागत चारधाम सभी जगह भीड़ भाड़ के कारण वातावरण अशांत सा रहता है, फिर बहुत से पर्यटकों के वाहनों में बजने वाला कानफाड़ संगीत बेचैन करता है।

उत्तरांचल दीप डेस्क

उत्तराखंड का धनौल्टी वो शहर है जिसे 'सोया हुआ शहर' भी कहते हैं। सोया हुआ शहर का मतलब यह नहीं है कि यहां के लोग सोये रहते हैं, बल्कि इसका साफ सपाट अर्थ है कि यहां इतनी अद्‌भुत शांति है कि पर्यटकों को लगता है कि यह शहर सो रहा है। यह एक एकांत और शांत पहाड़ी क्षेत्र है, जो अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए पहचाना जाता है। सालाना गर्मियां शुरू होते ही देवभूमि उत्तराखंड में पर्यटकों का सैलाब उमड़ने लगता है। उत्तराखंड का नैनीताल हो या अल्मोड़, कैंचीधाम, मसूरी, रानीखेत देहरादून अथवा परंपरागत चारधाम सभी जगह भीड़ भाड़ के कारण वातावरण अशांत सा रहता है। फिर बहुत से पर्यटकों के वाहनों में बजने वाला कानफाड़ संगीत बेचैन करता है। चारधाम यात्रा में उमड़ रहा श्रद्धालुओं का सैलाब अपनी जगह रहता है लेकिन इसके अलावा भी तमाम टूरिस्ट प्लेस पर्यटकों से खचाखच भर जाते हैं। इस भीड़भाड़ के बीच बहुत से ऐसे ऑफबीट हिल स्टेशन भी हैं जहां एकांत और शांत वातावरण का आनंद लिया जा सकता है। ये वो हिल स्टेशन हैं जहां प्रकृति के नजारे आपका मन मोह लेंगे। उत्तराखंड का धनौल्टी हिल स्टेशन इन्हीं में से एक है। मसूरी से महज 62 किलोमीटर की दूरी पर छोटा सा शहर धनौल्टी अपनी सुंदर पहाड़ियों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है। यहां लम्बी छुट्टी बिताने का प्लान बनाया जा सकता है। क्योंकि यहां सुकून भरे माहौल में एंजॉय करने का भरपूर अवसर मिलेगा। समुद्र तल से करीब 2200 फीट की ऊंचाई पर मौजूद ये जगह एक ऑफबीट टूरिस्ट प्लेस के तौर पर भी जानी जाती है। धनौल्टी की तमाम खासियतों में सबसे खास है 16वीं शताब्दी का देवगढ़ किला। यह किला ना सिर्फ इतिहास के पन्नों में ले जाता है बल्कि यहां से इस इलाके की खूबसूरती कुछ अलग ही दिखाई देती है। देवगढ़ किले का निर्माण 16वीं शताब्दी में प्रतापगढ़ के निकट हुआ था। इस किले में अलंकृत महल और उत्कृष्ट व कलात्मक जैन मंदिर हैं।

ऐतिहासिक देवगढ़ किला

धनौल्टी आने वाले पर्यटक ऐतिहासिक महत्व की धरोहर यानी देवगढ़ किले की यात्रा अवश्य करते हैं। देवगढ़ किला धनौल्टी के इतिहास का एक अनसुना हिस्सा है जो यात्रियों को अतीत में ले जाता है। यह किला कभी देवगढ़ राजपरिवार का गौरवशाली गढ़ हुआ करता था। अपनी भव्य वास्तुकला और मनमोहक चित्रों के लिए प्रसिद्ध, यह किला इतिहास, कला और प्राकृतिक सौंदर्य का एक आकर्षक संगम प्रस्तुत करता है। देवगढ़ किला इतिहासकारों और साहसी

मध्य प्रदेश के दक्षिण भाग यानी छिंदवाड़ा जिले के देवगढ़ वन गांव में भी देवगढ़ किला है, जिसे गोंडा किला भी कहा जाता है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की तलहटी में स्थित यह किला आसपास के भव्य दृश्य प्रस्तुत करता है, इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में गोंड वंश के राजा जाटव ने कराया था।

लोगों के लिए एक आदर्श गंतव्य है। हालांकि मध्य प्रदेश के दक्षिण भाग यानी छिंदवाड़ा जिले के देवगढ़ वन गांव में भी देवगढ़ किला है, जिसे गोंडा किला भी कहा जाता है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की तलहटी में स्थित यह किला आसपास के भव्य दृश्य प्रस्तुत करता है। इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में गोंड वंश के राजा जाटव ने कराया था। हालांकि देवगढ़ किले की संरचना मुगल वास्तुकला से मिलती है, जिससे कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस किले का निर्माण राजा जाटव के उत्तराधिकारी बख्त बुलंद ने कराया था। किंतु धनौल्टी में स्थित ऐतिहासिक देवगढ़ किले का निर्माण 16वीं शताब्दी में गढ़वाल के राजाओं या स्थानीय शासकों द्वारा कराया गया था। यह किला उत्तराखंड के प्रसिद्ध 52 गढ़ों व किलों में से एक है। यह किला क्षेत्र के समृद्ध ऐतिहासिक और शाही अतीत की एक झलक पेश करता है।धनौल्टी में शांति और सुकून मिलेगा

धनौल्टी में देखने लाय क्या है? तो इसका जवाब है यहां की प्राकृतिक सुंदरता है। धनौल्टी एक छोटी सी बस्ती है जिसमें मुश्किल से 50 घर और कुछ होटल व होमस्टे हैं। यह ऐसी जगह नहीं है जहां बहुत से लोग घूमने आते हैं क्योंकि पास का शहर मसूरी इसे पीछे छोड़ देता है। इस जगह में कुछ भी खास नहीं है, यह उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र का एक और छोटा सी बस्ती है, लेकिन फिर भी इसकी अपनी एक अलग ही खूबसूरती है। यानी इस गांव की शांति और सुकून का अनुभव केवल लद्दाख और लाहौल स्पीति जैसे क्षेत्र के छोटे गांवों में ही मिलता है। हरे-भरे पहाड़ों और ऊंचे देवदार के पेड़ों से घिरा यह स्थान उन लोगों के लिए आदर्श है जो शहर की भागदौड़ से दूर कुछ दिन शांति से बिताना चाहते हैं। धनौल्टी से थोड़ी ही दूरी पर स्थित कौडिया वन प्रकृति प्रेमियों और ट्रेकर्स के लिए स्वर्ग है। यह वन घने जंगलों से होकर गुजरता है, जहां कभी-कभी हिमालयी वन्यजीवों के दर्शन भी हो जाते हैं। यह रमणीय वन पिकनिक, पक्षी अवलोकन और फोटोग्राफी के लिए आदर्श है। वन के सुंदर ओक और पाइन के पेड़, हिमालय के मनोरम दृश्य, इसे एक शांत और सुखद स्थान बना देते हैं। टिहरी गढ़वाल जिले में कनाटल के पास स्थित कौडिया वन, हिमालयी क्षेत्र के सबसे खूबसूरत प्राकृतिक वनों में से एक है। अपने शांत वातावरण, घने हरे आवरण और वन्यजीवों के लिए प्रसिद्ध यह वन प्रकृति प्रेमियों, पर्वतारोहियों और पर्यावरण-पर्यटन के लिए एक पसंदीदा स्थान बन गया है। लेकिन इसकी वर्तमान लोकप्रियता के पीछे प्राकृतिक विकास, स्थानीय परंपराओं, ऐतिहासिक परिवर्तनों और संरक्षण प्रयासों की एक लंबी कहानी छिपी है। इस शांत वन में वन्यजीव-जंतुओं का भरपूर विकास हुआ है। हिमालयी लंगूर पेड़ों की शाखाओं पर झूलते मिल जाते हैं, जबकि मायावी तेंदुए और भौंकने वाले हिरण जंगल में विचरण करते हैं पक्षी प्रेमी इस वन में 80 से अधिक प्रजातियों की गिनती कर चुके हैं, जिनमें जीवंत हिमालयी मोनाल (राज्य पक्षी) और घास के मैदानों में घोंसला बनाने वाले चीयर तीतर शामिल हैं। वसंत ऋतु में खिले जंगली फूलों में कीड़े भिनभिनाते हैं और नदियां महसीर मछलियों से भरी रहती हैं। कनाटल एडवेंचर कैंप से कौडिया की 6 किलोमीटर की समतल पैदल यात्रा किसी वन संगीत की तरह मनमोहक है। चीड़ के पेड़ों के बीच से गुजरते हुए एक संकरे कच्चे रास्ते से शुरुआत करते हुए, घाटी के मनोरम दृश्यों को देखते हुए पठार की चोटी पर चढ़ें, फिर कलकल करते झरनों से सजी लहरदार पहाड़ियों में उतरें। दो-तीन घंटे प्रकृति की गोद में डूबने के लिए यह स्थान उपयुक्त है। कम चलने-फिरने वाले यात्रियों के लिए जीप व सफारी चलती हैं।

सुरकंडा देवी मंदिर

कौडिया वन के साथ ही धनौल्टी से लगभग 8 किलोमीटर दूर स्थित सुरकंडा देवी का प्राचीन मंदिर सती और शिव के तांडव की कथा से जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथा के अनुसार, शिव सती के मृत शरीर को ले जाते हुए इस स्थान से गुजरे और अनजाने में उनका सिर यहीं गिर गया। इसी से सुरकंडा देवी मंदिर अस्तित्व में आया और यह धनौल्टी और आसपास के क्षेत्र के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक माना जाता है। यह मंदिर सुरकंडा देवी, चंद्रबदनी और कुंजापुरी के देवी दर्शन त्रिकोण ट्रेक का हिस्सा है। चंबा की ओर जाने वाली मुख्य सड़क से यह 2 किलोमीटर का ट्रेक है, जो मध्यम रूप से चुनौतीपूर्ण है। सैलानियों को

- **कौडिया वन के साथ ही धनौल्टी से लगभग 8 किलोमीटर दूर स्थित सुरकंडा देवी का प्राचीन मंदिर सती और शिव के तांडव की कथा से जुड़ा हुआ है, पौराणिक कथा के अनुसार, शिव सती के मृत शरीर को ले जाते हुए इस स्थान से गुजरे और अनजाने में उनका सिर यहीं गिर गया।**
- **धनौल्टी गांव जैसी शांति और सुकून का अनुभव केवल लद्दाख और लाहौल स्पीति क्षेत्र के छोटे गांवों में ही मिलती है, हरे-भरे पहाड़ों और ऊंचे देवदार के पेड़ों से घिरा यह स्थान उन लोगों के लिए आदर्श है जो शहर की भागदौड़ से दूर कुछ दिन शांति से बिताना चाहते हैं, धनौल्टी से थोड़ी ही दूरी पर कौडिया वन प्रकृति प्रेमियों और ट्रेकर्स के लिए स्वर्ग है।**

सड़क किनारे गाड़ी खड़ी करके मंदिर तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों की लंबी श्रृंखला चढ़नी पड़ती है। मंदिर और पूरा ट्रेक घने जंगलों से घिरा हुआ है। शिखर पर पहुंचने पर आसपास की पूरी घाटी का अद्भुत और मनोरम दृश्य दिखाई देता है। यह मंदिर शरद ऋतु में लगने वाले गंगा दशहरा मेले के लिए भी प्रसिद्ध है। सुरकंडा देवी मंदिर मां के 51 शक्तिपीठों में से ये एक मंदिर है। बादलों के बीच और हरियाली में मौजूद माता के इस धाम पर हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं।

कैंपिंग के लिए खास

धनौल्टी में कैंपिंग के लिहाज से भी खास आकर्षण का केंद्र है। यहां हरे भरे वातावरण के बीच कैंपिंग का एक अलग अनुभव मिलेगा। धनौल्टी में मौजूद इको पार्क टूरिस्ट अट्रैक्शन है। यहां ना सिर्फ ओक और देवदार के पेड़ों के बीच ताजी हवा का आनंद ले सकते हैं बल्कि ये पूरा इलाका नेचर लवर्स के लिए बेहद खास है। धनौल्टी में दशावतार मंदिर, न्यू टेहरी टाउनशिप, बरेहिपानी, जोरांदा फॉल्स, देओगढ़ फोर्ट और माताटीला डैम जैसी खूबसूरत लोकेशंस पर जा सकते हैं। यहां फोटोग्रॉफी करने का अपना अलग ही मजा है। यहां ऐडवेंचर टूरिजम को भी इंजॉय कर सकते हैं। ऐडवेंचर स्पॉर्ट्स जैसे रॉक क्लाइम्बिंग, रिवर क्रासिंग, हाइकिंग और कैंप थांगधर में ट्रैकिंग का लुत्फ लिया जा सकता है। इस कैंप में आपको स्टेइंग के साथ जरूरी सुविधाएं भी मिलेंगी। देश के तमाम राज्य गर्मी की तपन से बेहाल हैं। लोग बड़ी संख्या में उत्तराखंड के हिल स्टेशन्स का रुख कर रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड के बड़े और प्रसिद्ध टूरिस्ट डेस्टिनेशन्स पर जाकर शरीर को ठंडक तो मिल जाती है लेकिन मन को शांति नहीं मिल पाती। अगर मानसिक शांति और ठंडक दोनों को एक साथ इंजॉय करना है तो उत्तराखंड के धनौल्टी का टूर बना सकते हैं। यहां वो सब कुछ मिलेगा, जिसकी कल्पना आपने की होगी।

कैसे पहुंचे धनौल्टी

मसूरी से धनौल्टी सिर्फ एक घंटे की दूरी पर स्थित है। देहरादून के रास्ते यहां जाना चाहते हैं तो ये दूरी और भी कम हो जाती है। देहरादून से धनौल्टी सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर है। सिर्फ सड़क मार्ग से ही धनौल्टी पहुंचा जा सकता है। क्योंकि यहां के लिए कोई रेलसेवा या फिर हवाई सेवा नहीं है। किसी भी बड़े शहर से यानी दिल्ली या बरेली, मुरादाबाद, गाजियाबाद से धनौल्टी के लिए कोई सीधी बस नहीं है, इसलिए अपनी यात्रा को कई हिस्सों में बांटना पड़ेगा। मसलन दिल्ली से जा रहे हैं, तो पहले हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून या मसूरी बस अथवा ट्रेन या फ्लाइट से पहुंचना होगा, जो बहुत आसान है। ये सभी स्थान दिल्ली और आसपास के अन्य सभी बड़े शहरों से बस व ट्रेन द्वारा अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। देहरादून के ज्योलीग्रांट में हवाई अड्डा है। बेहतर होगा ऋषिकेश या मसूरी के लिए सीधी बस लें, क्योंकि इससे यात्रा थोड़ी आसान हो जाएगी।

सिंगल है धुरंधर का रहमान डकैत

पिता विनोद खन्ना के प्रोडक्शन में बनी फिल्म 'हिमालय पुत्र' से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले अक्षय खन्ना को 1999 में हिट हुई फिल्म 'ताल' से पहचान मिली, अक्षय ने 'ताल', 'बॉर्डर', 'हलचल', 'हंगामा', 'गांधी माय फादर', 'रेस', 'दिल चाहता है' जैसी फिल्मों में काम किया पर 22 साल की उम्र में डेब्यू करने वाले अक्षय 19 साल की उम्र से बाल झड़ने की समस्या से जूझने लगे थे।

अरुण सिंह
मुंबई ब्यूरो

बॉलीवुड में अभिनेताओं व अभिनेत्रियों की चमक कब फीकी पड़ जाए कहा नहीं जा सकता। तमाम एक्टर्स ऐसे हैं जो पहले चमके और फिर कुछ समय के लिए पर्दे से गायब भी हो गए। ऐसे ही एक एक्टर अक्षय खन्ना है जो 50 साल के हो चुके हैं। वो जाने-माने एक्टर विनोद खन्ना के छोटे बेटे हैं। अक्षय ने पिता विनोद खन्ना के प्रोडक्शन में बनी फिल्म 'हिमालय पुत्र' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था, लेकिन 1999 में हिट फिल्म 'ताल' से उन्हें पॉपुलैरिटी मिली। अक्षय खन्ना ने 'ताल', 'बॉर्डर', 'हलचल', 'हंगामा', 'गांधी माय फादर', 'रेस', 'दिल चाहता है' जैसी बेहतरीन फिल्मों में काम किया है। 22 साल की उम्र में डेब्यू करने वाले अक्षय 19 साल की उम्र में बाल झड़ने की समस्या से जूझने लगे थे। करियर आगे बढ़ा तो अक्षय की ये समस्या और गहरी हो गई, जिसका असर उनके फिल्मी करियर पर भी पड़ने लगा। अक्षय ने फिल्मों से कुछ सालों का दो बार ब्रेक भी लिया। 27 साल के करियर में अक्षय करीब पांच साल तक घर बैठे रहे। लेकिन फिल्म 'धुरंधर' से ऐसा कमबैक किया है कि अब वह लोगों को खूब भा रहे हैं। रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर' में उन्होंने रहमान डकैत के रोल में ऐसा जलवा बिखेरा है कि सोशल मीडिया पर अक्षय खन्ना छाए हुए हैं। साल 2025 एक्टर अक्षय खन्ना के लिए सक्सेसफुल ईयर कहा जा सकता है। क्योंकि बीते साल की शुरुआत में विक्की कौशल की 'छावा' में उनका औरंगजेब का किरदार बहुत खतरनाक था और साल के आखिरी महीने में रिलीज हुई फिल्म 'धुरंधर' में वह और भी ज्यादा खूंखार रोल में नजर आए। ये दोनों ही फिल्में साल 2025 की सबसे कमाऊ फिल्में साबित हुईं और इंडियन सिनेमा की टॉप 10 सबसे कमाऊ फिल्मों की लिस्ट में शामिल हुईं। इसलिए अक्षय खन्ना का क्रेज अभी खत्म नहीं हुआ है। सोशल मीडिया पर रहमान डकैत का जादू ऐसा चला कि पूछो मत। पाकिस्तान में रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना के रोल को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हुई। फिल्म धुरंधर में रहमान डकैत का दमदार रोल निभाने वाले अक्षय खन्ना की जेन-जी तो जबरदस्त फैन हो गई है। फिल्म में अक्षय की शानदार एक्टिंग और बेहतरीन डांस के अलावा एक और चीज है, जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है, वो हैं एक्टर का हेयर स्टाइल। ऐसे में अक्षय खन्ना के लाइफ से जुड़े कुछ दिलचस्प फैक्ट्स इस बार प्रस्तुत कर रहे हैं।

अक्षय की बॉलीवुड में ड्रीम लॉन्चिंग

अक्षय खन्ना का जन्म 28 मार्च 1975 को मुंबई महाराष्ट्र में गीतांजली और विनोद खन्ना के घर पर हुआ था। पिता एक्टर और राजनेता थे। अक्षय के माता-पिता दोनों ही अब इस दुनिया में नहीं हैं। विनोद खन्ना का निधन 2017 में हुआ था, जबकि मां गीतांजलि 2018 में दुनिया से चल बसीं। एक्टर राहुल खन्ना, अक्षय के बड़े भाई हैं। अक्षय की शुरुआती पढ़ाई बॉम्बे इंटरनेशनल स्कूल, बाबुलनाथ में हुई। इसके बाद उन्होंने 11वीं और 12वीं की पढ़ाई लॉरेंस स्कूल, लवडेल, ऊटी से की। अक्षय का पढ़ाई में खास मन नहीं लगता था। वो हमेशा पढ़ाई से ज्यादा स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड थे। 17 साल की उम्र में अक्षय ने कॉलेज का एग्जाम इसलिए नहीं दिया था, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वो फेल न हो जाएं। इससे भी ज्यादा वो इस बात को लेकर चिंतित थे कि अगर वो फेल हो गए तो पेरेंट्स को क्या मुंह दिखाएंगे। 12वीं के बाद अक्षय आगे पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करना चाहते थे, लेकिन पेरेंट्स से ये बात कहने में भी वो झिझक रहे थे। आखिरकार एक दिन अक्षय ने हिम्मत करके पिता विनोद खन्ना से कह दिया कि वो आगे नहीं पढ़ना चाहते हैं। ये बात सुनते ही विनोद खन्ना भड़क गए थे, लेकिन काफी मनाने के बाद मान गए। इस दौरान अक्षय ने ये इच्छा भी जाहिर कर दी कि वो फिल्मों में करियर बनाना चाहते हैं। विनोद खन्ना ने अपने बेटे के इस सपने का विरोध नहीं किया। उन्होंने अक्षय को पहले एक्टिंग सीखने की सलाह दी और उनका दाखिला किशोर नमित कपूर के एक्टिंग स्कूल में करा दिया। यहां एक्टिंग की बारीकियां सीखने के बाद विनोद खन्ना ने उनके लिए 'हिमालय पुत्र' नाम की फिल्म में पैसा लगाया।

इस फिल्म के डायरेक्टर पंकज पाराशर थे। 1997 में 'हिमालय पुत्र' के जरिए अक्षय को बॉलीवुड में ड्रीम लॉन्चिंग मिली, लेकिन फिल्म फ्लॉप रही। इसके बावजूद अक्षय को फिल्म में सराहा गया। उन्हें 'हिमालय पुत्र' के लिए बेस्ट मेल डेब्यू का स्क्रीन अवॉर्ड मिला था। इस फिल्म के बाद अक्षय खन्ना, जेपी दत्ता की वॉर ड्रामा फिल्म 'बॉर्डर' में सनी देओल, सुनील शेट्टी और जैकी श्रॉफ जैसे स्टार्स के साथ नजर आए। फिल्म में अपने किरदार के लिए अक्षय को बेस्ट मेल डेब्यू का फिल्म फेयर अवॉर्ड मिला। बॉर्डर 1997 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दूसरी फिल्म थी। 1997 में ही अक्षय की तीसरी फिल्म 'मोहब्बत' रिलीज हुई जिसमें उनके अपोजिट माधुरी दीक्षित थीं, फिल्म फ्लॉप रही। इसके बाद भी अक्षय की बैक टु बैक फिल्में आईं जिनमें 'डोली सजा के रखना', 'कुदरत' जैसी फिल्में शामिल थीं। ये सभी फिल्में फ्लॉप रहीं। अक्षय की नाकामी पर कहा गया कि वो कन्वेंशनल हीरो की छवि में फिट नहीं बैठते, इसलिए दर्शकों के बीच उनके लिए अपनी जगह बनाना आसान नहीं है।

1999 में मिली कामयाबी

अक्षय के लिए 1999 का साल सबसे कामयाब साबित हुआ। इस साल पहले उन्हें ऋषि कपूर की बतौर डायरेक्टर पहली फिल्म 'आ अब लौट चलें' में काम करने का मौका मिला। ये फिल्म इंडिया में तो खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन ओवरसीज में इसने अच्छी कमाई की थी। 1999 में अक्षय की दूसरी फिल्म 'लावारिस' पिट गई। हालांकि इसी साल 'ताल' ने उन्हें सही मायनों में असली कामयाबी दिलाई। सुभाष घई की इस रोमांटिक ड्रामा फिल्म में अक्षय ऐश्वर्या के अपोजिट कास्ट किए गए थे। 'ताल' 1999 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली चौथी फिल्म थी। 'ताल' ही वो फिल्म थी जिससे अक्षय ने अपने करियर में 'बॉर्डर' के बाद पहली बार कॉमर्शियल सक्सेस पाई थी। हालांकि 'ताल' के बाद अक्षय की ज्यादातर फिल्में फ्लॉप साबितहुईं। अक्षय ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब वो 19 साल के थे तभी उनके बाल झड़ने लगे थे। इस बात से अक्षय बेहद परेशान रहने लगे थे। फिल्मों में इंट्री करने के बाद तो उनकी बेचैनी और ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि एक हीरो के लिए लुक्स, फिजीक और हेयर ही सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। धीरे-धीरे अक्षय के काफी ज्यादा बाल झड़ गए और गंजेपन की वजह से उन्हें फिल्में मिलनी कम हो गईं, मगर तब भी अक्षय ने विग या पैच नहीं लगाया। समय के साथ उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया और अब वो अपने बाल्ड लुक में ही नजर आएंगे। 'आ अब लौट चलें' और 'ताल' जैसी फिल्मों में काम करते हुए अक्षय ऐश्वर्या पर फिदा हो गए थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद इस बात का जिक्र करते हुए कहा था कि जब भी ऐश्वर्या से मिलता था, तो उनसे नजर नहीं हटा पाता था। इतना ही नहीं उन्होंने ये बात भी स्वीकार कि जब भी ऐश्वर्या उनके सामने आती थीं, तो वो उन्हें घूरने से खुद को रोक नहीं पाते थे, क्योंकि वो बेहद खूबसूरत हैं।

> **1997 में 'हिमालय पुत्र' के जरिए अक्षय को बॉलीवुड में ड्रीम लॉन्चिंग मिली, लेकिन फिल्म फ्लॉप रही, इसके बावजूद अक्षय को फिल्म में सराहा गया, उन्हें 'हिमालय पुत्र' के लिए बेस्ट मेल डेब्यू का स्क्रीन अवॉर्ड मिला था, इस फिल्म के बाद अक्षय खन्ना, जेपी दत्ता की वॉर ड्रामा फिल्म 'बॉर्डर' में सनी देओल, सुनील शेट्टी और जैकी श्रॉफ जैसे स्टार्स के साथ नजर आए।**

अक्षय का एक्टिंग से दूसरा ब्रेक

2000 में अक्षय ने फ्लॉप फिल्मों से परेशान होकर एक साल का ब्रेक ले लिया था। 2001 में वो फिल्म 'दिल चाहता है' में नजर आए थे जिसमें उन्हें सिड के रोल में काफी पसंद किया गया था। इसके बाद 2002 में अक्षय फिल्म 'हमराज' में पहली बार निगेटिव रोल में नजर आए, जिसमें उन्हें पसंद किया गया। धीरे-धीरे अक्षय को हीरो के बजाय साइड रोल मिलने लगे जिसमें उन्हें सराहना भी मिली। 2012 में अक्षय ने दोबारा एक्टिंग से ब्रेक लिया था। इस दौर को एक इंटरव्यू में उन्होंने अपनी लाइफ का सबसे खराब दौर बताया था। उन्होंने कहा था कि मैं उस दौर को याद नहीं करना चाहता जब मैंने ब्रेक लिया था। वो समय मेरी लाइफ का सबसे बुरा दौर था। मैं घर में बैठने वालों में से नहीं हूं, मुझे काम करना पसंद है, लेकिन कई बार समय आपकी परीक्षा लेता है। आपको वो काम नहीं मिलता जो आप करना चाहते हैं, तो आपको घर बैठना पड़ता है। आखिर कौन घर बैठना चाहता है? मैं 19 साल की उम्र से काम कर रहा हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे सेट पर रहना पसंद है। 2012 से 2016 तक इंडस्ट्री से दूर रहे अक्षय ने फिल्म 'ढिशूम' से कमबैक किया। इसके बाद इन्हें 'मॉम', 'इत्तेफाक', 'सेक्शन 375' जैसी फिल्में मिलीं। उनकी पिछली फिल्म 'दृश्यम 2 थी' जिसमें वो एक पुलिस ऑफिसर के रोल में नजर आए थे। अक्षय ने अपने करियर में तकरीबन 45 फिल्में की हैं जिनमें से सिर्फ 8-10 ही सफल साबित हुई हैं। इसके बाद अक्षय ने डिजिटल डेब्यू की तैयारी की और रवीना टंडन के साथ वेब सीरीज 'लीगेसी' में नजर आए।

> **अक्षय का पढ़ाई में मन नहीं लगता था, वो पढ़ाई से ज्यादा स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड थे, 17 साल की उम्र में अक्षय ने परीक्षा इसलिए नहीं दी, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं फेल न हो जाएं, यदि वो फेल हो गए तो पेरेंट्स को क्या मुंह दिखाएंगे ? 12वीं के बाद तो अक्षय आगे पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करना चाहते थे, लेकिन पेरेंट्स से ये बात कहने में भी वो झिझक रहे थे।**

अनमैरिड हैं अक्षय खन्ना

एक इंटरव्यू में अक्षय ने पिता विनोद खन्ना के संन्यास लेने के बारे में भी बात की थी। उन्होंने कहा था, मैं तब केवल पांच साल का था जब पापा सब कुछ छोड़कर ओशो आश्रम चले गए थे। इतनी छोटी उम्र में मुझमें इतनी समझ नहीं थी कि मैं उनके इस फैसले के बारे में कुछ सोच पाता। जब मेरी उम्र 15 साल हुई तो उनके संन्यास के बारे में समझ आया। अक्षय ने कहा था कि उनके पिता के लिए संन्यास लेने का फैसला एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट साबित हुआ होगा, क्योंकि अच्छा-खासा करियर, परिवार छोड़ना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। दूसरे कई एक्टर की तरह फिल्म इंडस्ट्री में अक्षय ने भी एक्ट्रेस तारा शर्मा को डेट किया था। दोनों कुछ सालों तक एक-दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते रहे, लेकिन फिर इनका ब्रेकअप हो गया था। एक समय था जब उनके पिता विनोद खन्ना अक्षय की शादी करिश्मा कपूर से कराना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। विनोद खन्ना ने बेटे अक्षय के लिए अपने दोस्त रणधीर कपूर की बेटी करिश्मा का रिश्ता मांगा था। करिश्मा की मां ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया था। करिश्मा की शादी संजय कपूर से हो गई, लेकिन अक्षय ने कभी शादी नहीं की। अक्षय का कहना है कि वो सिंगल लाइफ एंजॉय करते हैं और उन्हें शादी या बच्चों में दिलचस्पी नहीं है।

मासिक राशिफल

पंडित उपेन्द्र कुमार उपाध्याय
9897450817, 9897791284
ज्योतिषाचार्य, आयुर्वेदरत्न, कथावाचस्पति, यज्ञानुष्ठान विशेषज्ञ
अध्यक्ष-श्री शिवशक्ति ज्योतिष पीठ, बदायूं
निवास प्रभातनगर, निकट इंद्राचौक, सिविल लाइंस, बदायूं (यूपी)

मेष:-

इस माह सरकारी कामकाज में लाभ होगा, लोक संबंधों में वृद्धि होगी, अतिआक्रामकता से बचिए, वाणी संयम अति आवश्यक है। साहस पराक्रम को बनाए रखिए, यात्राओं से लाभ मिलेगा मित्रों से समागम के अवसर मिलेंगे। शत्रु निराश ही रहेंगे, भागीदारी के कार्यों में सफलता हाथ लगेगी। अविवाहितों को विवाह के प्रस्ताव प्राप्त होने का योग बन रहा है। नौकरीपेशा वर्ग के लिए स्थानांतरण के योग हैं। यदि कोई पुरानी बीमारी है तो आराम मिलेगा।

वृषभ:-

इस माह कारोबारी यात्रा लाभकारी रहेगी, मीडिया क्षेत्र में सफलता के योग हैं, क्रोध से काम बिगड़ सकते हैं, पैरों में कष्ट हो सकता है, मध्य माह में सभी परिणाम अनुकूल होने के संकेत मिल रहे हैं। ऋण लेने का मार्ग सुगम होगा। बुद्धि कौशल दिखाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। आपके अनुयायियों की संख्या में वृद्धि होगी, पुराने रोग के उभरने की संभावना है। लेन-देन में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अनिर्णय की स्थिति अभी बनी रहेगी।

मिथुन:-

इस माह आप हंसमुख स्वभाव के कारण समाज में आर्कषण के केंद्र रहेंगे। वाणी संयम रखने की जरूरत है, संपत्ति में वृद्धि के प्रयास सफल रहेंगे, जीवनसाथी से तालमेल बनाने का प्रयास करें। मित्रों के साथ घूमने जा सकते हैं। परिवार में कोई सदस्य बढ़ सकता है। माता की चिंता कम होगी। ननिहाल के किसी व्यक्ति से मुलाकात संभव है। विरोधियों के षडयंत्र बढ़ सकते हैं, सचेत रहें। बरसात में जलीय रोगों के होने की संभावना प्रबल है।

कर्क:-

इस माह आपके भीतर प्रशासनिक क्षमता का विकास होगा, क्रोध से बचने का प्रयास करना होगा, सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग हैं, कार्यक्षेत्र में प्रमोशन की प्रबल संभावना बन रही है। लाभ के प्रचुर अवसर उपलब्ध होंगे। सामाजिक सम्मान बढ़ेगा। मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा धैर्य से काम लें। संचार माध्यम से कोई आनंददायक सूचना मिल सकती है। अनावश्यक क्रोध काम बिगाड़ सकता है। असत्य भाषण से बचने का प्रयास करें।

सिंह:-

इस माह आप अनिर्णय की स्थिति से गुजरेंगे। रक्तदान करने का अवसर मिलता है तो चूक न करें। अचानक कोई धार्मिक यात्रा हो सकती है। भाग्य प्रबल रहेगा, सम्मान में वृद्धि होने के योग हैं। नई नौकरी की तलाश पूरी हो सकती है। सहयोगियों की संख्या में वृद्धि होगी। परिवार के लोगों से मेल मिलाप के अवसर मिलेंगे। अकारण क्रोध को टालें, क्रोध आपका काम बिगाड़ सकता है। वाणी संयम रखना आपके लिए हितकारी होगा।

कन्या:-

इस माह कार्य क्षेत्र में सफलता की प्रबल संभावनाएं हैं, भूमि अथवा भवन से लाभ के योग हैं, लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। लाभ के अवसर आपको मिलेंगे। सीने का रोग उभरने की संभावना बन रही है। पड़ोसियों से संबंधों में सुधार होगा। मान सम्मान में भी वद्धि के अवसर मिलेंगे। आलस्य से काम बिगड़ सकते हैं, किसी कारणवश अस्पताल जाने की संभावना बन रही है। यदि रोजगार की तलाश में हैं तो नौकरी मिलेगी।

तुला:-

इस माह तुला राशि के जातकों को लाभ के प्रचुर अवसर मिलेंगे, कार्य क्षेत्र में सफलता के योग हैं, ललित कलाओं में अचानक रुझान बढ़ेगा, जीवनसाथी से तालमेल बैठाना कठिन होगा। मनपसंद उपहार की प्राप्ति संभव है। मेडिटेशन कर सकते हैं। मनोनुकूल परिणाम मिलने में संदेह रहेगा। घर से दूर यात्रा पर जाना पड़ सकता है। ज्यादा ठंडा न पीएं गले की तकलीफ बढ़ सकती है, अपनी मेहनत के बल पर सब कुछ पा सकेंगे।

वृश्चिक:-

इस माह किसी को पैसा उधार न दें। भाग्य साथ देगा धार्मिक यात्रा होगी, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। ज्यादा व्यसन हानिकारक हो सकता है, वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, वरना बनते काम बिगड़ सकते हैं। खरीददारी के लिए बाहर जा सकते हैं। आय के स्रोत बढ़ेंगे आपकी कोई मनोकामना इस माह पूरी हो सकती है। किसी कारणवश अस्पताल जाने की जरूरत पड़ सकती है। झगड़ों से दूर रहने का प्रयास करें।

धनु:-

इस माह अनिर्णय की स्थिति बनी रहेगी। पैर में चोट लगने का भय रहेगा, आप जिस मानसिक बिखराव के दौर से गुजर रहे हैं उससे निकलने में अभी कुछ और समय लग सकता है। स्वाभाविक परिवर्तन आपके लिए आगे चलकर सुखद साबित होगा। बड़े भाइयों से सहयोग मिलेगा। लाभ के अवसर मिलेंगे। पिता से किसी प्रकार की मदद मिल सकती है। व्यापार में सफलता मिलेगी। आलस्य बढ़ सकता है, जो हानिकारक हो सकता है।

मकर:-

इस माह जीवन साथी से तर्क-कुतर्क ठीक नहीं रहेगा, अनिर्णय की स्थिति बनी रहेगी, संभल कर चलिए मुंह के बल गिर सकते हैं। खर्चों से पार पाना मुश्किल होगा। सामाजिक सम्मान बढ़ेगा। किसी धर्म गुरु से मुलाकात होने की सांभावना है। ससुराल के लोगों से मुलाकात हो सकती है। गलत स्रोतों से धन मिलने की संभावना है, सावधानी बरतें। अदालती प्रकरणों में जीत मिलने के योग हैं। नौकरीपेशा लोग इस माह ज्यादा व्यस्त रहेंगे।

कुंभ:-

इस माह आपको अपने जीवनसाथी की मदद करनी होगी। विवादित मामलों में जीत मिल सकती है, लाभ के अत्यधिक अवसर उपलब्ध होंगे। बड़े भाई का सहयोग आपके लिए आशीर्वाद साबित होगा। हिम्मत से काम लेने की आवश्यकता है। संचार माध्यम से धन अर्जित करेंगे। धार्मिक यात्रा होगी। ससुराल के लोगों से मुलाकात हो सकती है। अकस्मात धन मिलने से मन प्रफुल्लित होगा। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है।

मीन:-

इस माह ललितकला से जुड़े लोगों को तकनीकी शिक्षा में सफलता मिलने का योग बन रहा है, रुका हुआ धन प्राप्त होने से परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। बैंक बैलेंस बढ़ेगा, लेकिन वाणी पर संयम रखना होगा। कारोबारी यात्रा की प्रबल संभावना है। यात्रा में अपने सामान का ख्याल रखें। रोमांटिक मूड बना रहेगा। परिवार के साथ घूमने जा सकते हैं। भाग्य की वजह से कई रुके काम बन सकते हैं। कोई शत्रु अनायास ही सामने आ सकता है।

nupur.com NRITYA

नुपुर नृत्य कला केंद्र हल्द्वानी

में सभी के लिए
01 फरवरी 2021 से पुनः
कक्षाएं आरंभ
हो गई है।

जिसमें क्लॉसिकल डांस, तबला वादन, सेमी क्लासिकल, गिटार, पेंटिंग आदि का प्रशिक्षण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों का पालन करते हुए तथा कक्षों (क्लास) को नियमित रूप से सेनेटाइज कर आधुनिक तरीके से देने की व्यवस्था पूर्ण कर ली गई है ।

एडमिशन के लिए संपर्क करें।

www.facebook.com/nupurnrityakalakendra
You Tube: Search: nupurnrityakalakendra
nupurnritya99@gmail.com
www.nupurnritya.com

NEAR KANDPAL ENT. Hospital, SHAKTI SADAN GALI, NAWABI ROAD, HALDWANI (NAINITAL), Uttarakahnd
05946 220841, 91 9760590897
91 9411161794

NUPUR HALDWANI